राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07]   पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौथा दिवस   [संख्या: 04

सोमवार,

14 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश, चन्द्रभान सिंह आक्या, सर्वश्री, सदस्यों का सत्रांत तक निलम्बन समाप्त करने के लिए अनुरोध

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरी प्रार्थना है कि गतिरोध बना हुआ है। रीट में जो चीट हुई, उसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए आपके चेंबर में हमने अपनी बात भी रखी थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार हमारे चार माननीय सदस्यों के निलम्बन को आप बड़ा हृदय रखते हुए समाप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल को कहें और उसके बाद आज उस पर बहस की बात अगर आती है और यदि सरकार बहस के लिए तैयार है तो हम भी बहस के लिए तैयार हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम तार्किक तरीके से सरकार को बतायें कि क्यों सीबीआई की जांच की आवश्यकता है, लाखों नौजवानों के सपनों को क्यों चकनाचूर किया गया है। ये सारी बातें बहस में आ जायेंगी तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय। अब आ गये, सर जी। आप बोलें भाई साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्षमा चाहता हूं, कुछ विलम्ब हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस रीट को लेकर जिस प्रकार का असंतोष नौजवानों में भी है, परिवारजनों में भी है और सम्पूर्ण राजस्थान में इस परीक्षा को लेकर जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं, उससे शिक्षा के प्रति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है, उसके मन में भी बड़ी उठा-पटक है और मैं सोचता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय का जब तक कोई अन्त नहीं होगा, हम सब लोग चाहते ही हैं कि बच्चों का अहित न हो, बेरोजगारों का अहित न हो। मैंने पहले उस दिन भी कहा कि इसको दो टुकड़ों में करें, बच्चों की भर्ती का प्रोसेस, जिसे आपने 62 हजार कर दी है, उसको आगे लागू रखें।

नये बच्चों को जिनको उसमें अप्लाई करना है, उनको आप अधिकार दें, तारीख तय करके उनकी परीक्षा करवाकर, उनका सलेक्शन करें, उधर विद्यालय खाली हैं, उन्हें भी सुविधा से जोड़ लें। इधर यह जो अनियमितता करने वाली गैंग राजस्थान में एक लम्बे समय से आपरेट कर रही है और इसमें बड़े-बड़े दिग्गज लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके कारण से राजस्थान के अन्दर शिक्षा के प्रति थोड़ी रुचि रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं तो वह बच्चा जो मेहनत करके अपनी जिन्दगी बनाना चाहता है, उसके सारे रास्ते बन्द हो गये। केवल कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले और पैसा खर्च करने वाले लोग ही अब राजस्थान की नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। हमारे भाग्य में, हमारी योग्यता होते हुए भी हम इस काम्पीटिशन में अपने आपको स्टैण्ड नहीं कर पाएंगे। इस समस्या के कारण आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि चर्चा हो और इस चर्चा में हम लोग भाग लें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आपके इस निर्णय को मैं शिरोधार्य करता हूं। हमारे सामने यह है कि हमारे चार विधायकों को जिन्हें आपने निलम्बित कर रखा है, उनका निलम्बन आदेश निरस्त नहीं होता है तो उस चर्चा में भाग लेना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

मैं चाहता हूं कि किसी तरह से एक बार आप इस क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करके आप बुला लें, आपके चैम्बर में हमको भी बुला लें, हमसे बात कर लें और इस पर चर्चा करने के लिए जो भी आप समय तय करें और चर्चा तय करके, राजस्थान के सभी लोगों को पक्ष और विपक्ष के सारे व्यूज कम से कम जनता के सामने चले जायें कि इसमें कमी कहां रही, कैसे कमियों को ठीक करने के लिए आगे भविष्य में क्या रोडमैप बनेगा, किस तरह से बच्चों को आश्वस्त कर पाएंगे कि अब राजस्थान में होने वाली हर भर्ती में पवित्रता के आधार पर, हर व्यक्ति को हक मिलेगा ताकि उन बच्चों को भी संतोष हो, उनके परिवार को भी संतोष हो और हम सब लोगों पर जो सन्देह की अंगुली घूम गई है, उस पर लोगों को यह विश्वास दें कि नहीं, ये जन प्रतिनिधि जनता के हितों के लिए सब एक सरीखा राय रखकर, इसका कोई स्थायी हल करने का विचार रखते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिन लोगों ने भी गलती की, चाहे मैंने की, मेरे समय में हुई, किसी के भी समय हुई, जो भी अपराधी हैं, उनको दण्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करें, ताकि हमेशा के लिए इस गिरोह को तोड़ने में हम सफल हो जायें।

मेरी प्रार्थना यही है कि अगर आप चाहते हैं हाउस में इस पर डिस्कशन हो तो हमारे जो चार माननीय सदस्य बाहर हैं, पहले आपकी तरफ से प्रस्ताव आयेगा, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन आवर है, प्रस्ताव आ नहीं पायेगा। मैं सोचता हूं आपको थोड़े समय के लिए सदन को एडजॉर्न करके बातचीत करने के बाद, उनके वापस होने के बाद, हम चर्चा में भाग लेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे। राजस्थान की जनता के सामने ठीक प्रकार से तथ्य अगर जायें तो वह तुलना कर सकेगा कि वास्तव में राजस्थान के हमारे प्रतिनिधि और हमारी सरकार हमारी समस्या के बारे में क्या स्थायी हल सोचने का विचार रखती है। इस पर चर्चा होकर के आगे बढ़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब। पहले आप बोल लें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अभी विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठायीं, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रीट परीक्षा के मामले में सीबीआई जांच के बिन्दु पर विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही बाधित करने का..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय कल्ला साहब, एक मिनट। माननीय सदस्य, बैठें। पाइन्ट आफ आर्डर क्वेश्चन ऑवर में नहीं आता है। मेरी इस बात की गंभीरता को समझें। मैं संसदीय मंत्री से कहूंगा इस पर कर दें, फिर मैं अपना कमेंट करूंगा, फिर बात करेंगे, नहीं तो फिर अन्त नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सब-ज्युडिस के बारे में बताना है।

श्री अध्यक्ष: पता है, प्लीज। एक मिनट, धारीवाल साहब। जो भावना अभी विपक्ष के नेता ने कही, ये प्रिसिडेंस रहे हैं कि हमने क्वेश्चन ऑवर को तीन-चार बार, इस तरह से राजस्थान विधान सभा में इम्पोर्टेंट इश्यूज पर

(श्री अध्यक्ष)
हमने क्वेश्चन ऑवर को स्थगित किया, पर उसके बाद ही हमने चर्चा की है, ऐसा नहीं है कि चर्चा में गैप हो, तो मेरी इच्छा है कि जो आपने भावना व्यक्त की है, जिस पर चर्चा प्रारम्भ हो, सके, चार माननीय सदस्यों को उस दिन निकालना पड़ा, जो घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उन सब बातों को समझकर मैं संसदीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे सरकार का कोई पक्ष है, वह सदन में रख दें। फिर, मैं अपनी बात कह पाऊंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो हम भी चाहते हैं, चर्चा होनी चाहिए, जो बात है साफ आनी चाहिए कि भई हो क्या रहा है।

जिन चार सदस्यों के निलम्बन की बात थी, उनका व्यवहार तो देख ही लिया गया था, सारा सदन देख रहा था, क्योंकि सदन की उच्च और गौरवशाली परम्पराएं रही हैं। सदन में अनुशासन बनाने के लिए कई बार कठोर निर्णय भी लिये गये हैं प्रक्रिया एवं नियमों के तहत। अब अगर यहां पर अनुशासन नहीं रहेगा तो सदन का क्या होगा? सब्जी मण्डी कहलायेगा तो यह बात और फिर दूसरी बात एक ही व्यक्ति बार-बार अनुशासन तोड़े और बार-बार उसको सदन में लिया जाये, यह बड़ी दु:खदायी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा में आपने शर्त रख दी साहब, उन चार लोगों का निलम्बन वापस लो, तभी जाकर के चर्चा हो पायेगी। निश्चित तौर पर हम लेने को तैयार हैं, लेकिन यह बात भी आपको देखनी चाहिए कि ऐसे सदस्यों को, जो आपकी तरफ के सदस्य हैं, अगर वे इसी प्रकार से अनुशासन तोड़ते रहे तो फिर इस सदन की मर्यादा जो भंग हो रही है, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे, आप भी बच नहीं सकते उस बात के लिए, क्योंकि गौरवशाली परम्पराएं रही हैं। आप बरसों से सदन में आते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

निलम्बन निरस्तीकरण

रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश, चन्द्रभान सिंह आक्या, सर्वश्री, सदस्यों का सत्रांत तक निलम्बन निरस्तीकरण का

प्रस्ताव

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यही प्रस्ताव करता हूं कि उन चार सदस्यों को बुलवा लिया जाये, उनका निलम्बन रद्द कर दिया जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके चैम्बर में भी कहा था, जो कुछ घटना हुई वह अच्छी नहीं है, इसमें किसी को भी दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन उस दिन जो भी गाली-गलौज की स्थिति आई, वह भी मैंने कहा, आप स्वयं देख लें और देखने के बाद स्वयं ही उस पर निर्णय करें कि क्या यह व्यवहार उचित था? अगर इधर का व्यवहार आपको अनुशासन के हिसाब से ठीक नहीं लगता तो वह व्यवहार भी ठीक नहीं था। इन दोनों को ही कण्डेम करते हुए, हम अगर इस व्यवस्था को चलाने की मंशा रखते हैं तो जरूर चलायें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं सोचता हूं, मैं आसन पर ही छोड़ता हूं इस विषय को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गलती केवल हम ही हमने की और बाकी लोगों ने जो गलती की उसको नजरंदाज कर जाएंगे तो अनुशासन तो दोनों तरफ से बनेगा, एक तरफ से नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल स्थगित होता नहीं है, पर इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रश्न काल को स्थगित करके इस पर चर्चा की जानी चाहिए, पर चर्चा करने के साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस दिन हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के कारण चार सदस्यों को निलम्बित करना पड़ा और जो घटना की जानकारी मैंने ली, मैं समझता हूं कि उस घटना में सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी व्यवहार उस तरह का नहीं था, जो व्यवहार सत्ता पक्ष का होना चाहिए। इसलिए, मैं उन चार माननीय सदस्यों के व्यवहार के प्रति भी अपनी उतनी ही गम्भीरता व्यक्त करता हूं, निवेदन करता हूं अनुशासन के अन्दर रहकर अपनी बात कहें, सदन के अन्दर कोई बात बोल रहा है तो ऑब्स्टेकल नहीं करें और मैं आशा करता हूं कि सदन के पक्ष और विपक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे इस सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, जिसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दोष दें। लेकिन हम स्वयं भी इस सदन की गरिमा को बनाये रखें, ऐसा काम करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और मैं समझता हूं कि जैसा माननीय संसदीय मंत्रीजी ने जिस भावना को व्यक्त किया है कि हमें अनुशासन बनाये रखना है, ऐसी घटना नहीं हो लेकिन इस बात पर चर्चा करने के लिए जो माननीय संसदीय मंत्री ने कहा है, मैं एक्सेप्शनली यह फैसला करता हूं कि आधा घण्टा हम सदन को स्थगित करते हैं। आधे घण्टे बाद चर्चा करेंगे और जो माननीय सदस्य, जिनको हमने निलम्बित किया है उनको सदन में आने की परमिशन होगी और हम जो चर्चा

(श्री अध्यक्ष)

कर रहे हैं, माननीय सदस्यों से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से प्रतिपक्ष के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परम्परा में जो हमारे राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियम हैं उन नियमों में 52(7), 31a(7) जो ज्युडिशियरी के अन्तर्गत कोई मैटर सबज्युडिश हो, उसको डिस्कस करने के लिये वो सब हमको डिबार करते हैं।

मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि सबज्युडिश मामला है, इसमें 28 तारीख को हाई कोर्ट इसके बारे में डेलिब्रेट कर रहा है। हमारा मैन थ्रस्ट इस बात पर होना चाहिये कि ये जो घटना हुई है वह घटना किस तरह से हुई भविष्य में यह घटना नहीं हो और हम सब मिलकर किस तरह से इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो जिससे राजस्थान में परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे, उसकी सैंक्टिटी बनी रहे और राजस्थान के नौजवान आदमियों को जो नौकरी का डिप्राइवेशन हो रहा है कि हमारी व्यवस्था की कमी के कारण यदि पेपर लीक होता है और जॉब नहीं मिलता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है और राजस्थान के नौजवान के लिए ठीक नहीं है। हम सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस मीनेस को रोकने के लिए हम कानून बनायें, कठोर कानून बनायें और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, उस पर ज्यादा सार्थक चर्चा करें। मैं समझता हूं कि हमारी विधान सभा की जो गरिमा है, उस गरिमा के माध्यम से हम राजस्थान के नौजवानों को यह मैसेज दे सकेंगे कि हम कलेक्टिवली, the word I am using here is the 'collective government', whether it is the BJP government or the Congress government, is actually failed to create a confidence among the youngsters कि हम परीक्षा आयोजित करते हैं और उन्हीं लोगों के कारण यदि पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था की कमी है। यह कमी व्यवस्था में नहीं रहे, यह हम सबका उत्तरदायित्व बनता है और मैं आशा करता हूं कि डिबेट में हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि भविष्य में यह घटना नहीं हो। कैसे रोक सकें, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिये सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं। 11.30 बजे बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। विपक्ष के जो साथी बोलना चाहें वो पहले बोल लें। पक्ष के जो साथी बोलना चाहते हैं वो बोल लें और सार्थक चर्चा करके हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और मैं सदन की कार्यवाही को 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.12 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 11.30 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: चर्चा का समय दो घंटे निर्धारित किया है। एक घंटे विपक्ष अपनी बात कह पायेगा और एक घंटे सरकार अपनी बात कह पायेगी। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तेजना नहीं हो, शान्तिपूर्ण अपनी बात कहें और हम गरिमापूर्ण डिबेट कर सकें, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुन तो लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: There is no point of order. Please understand it. प्लीज आप बैठें। Don’t challenge my order. प्लीज आप बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष: बैठें, अंकित नहीं होगा। क्वेश्चन ऑवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। नहीं होता, विराजिए आप। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, बैठें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: I said I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। राजेन्द्र राठौड़। रिकार्ड नहीं होगा। Mister, don’t compel me. प्लीज आप बैठें। Don’t compel me. I said, I am on leg. It is very unfortunate. आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, आप जानते हैं कि क्वेश्चन ऑवर में, जीरो ऑवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, I will not allow it. राजेन्द्र राठौड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: I said I will not allow it.

अनुरोध एवं मांग

रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. द्वारा जांच

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों से मैं आपका आभार व्यक्त करूं। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट में चीट के लिये राजस्थान का अवाम चाहता था कि राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में हम तर्कों के आधार पर चर्चा करें क्योंकि राजस्थान के 26 लाख से ज्यादा नौजवान सालभर की तैयारी के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए। संसदीय परम्पराओं में बहुत कम क्षण ऐसे आते हैं जब प्रश्न काल स्थगित होता है। आपने बड़ा मन रखकर न केवल हमारे माननीय सदस्यों का निलम्बन रद्द किया बल्कि चर्चा प्रारम्भ की।

अध्यक्ष महोदय, पांच बार रीट की परीक्षा घोषित होने के बाद स्थगित होती गयी और अन्ततोगत्वा 26 नवम्बर को दो चरणों में यह परीक्षा हुई और 26 लाख 51 हजार अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में दो चरणों में भाग लिया। परीक्षा के प्रारम्भ से ही इस सरकार ने पारदर्शिता का नगाड़ा बहुत जोर से बजाया। 30 हजार सीसी टीवी कैमरे लगाने की बात कही। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नेटबन्दी की बात कही और राजस्थान आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम, 1971 में इस रीट की परीक्षा को आपने आवश्यक परीक्षा घोषित की।

रीट की परीक्षा सम्पन्न होते ही सरकार आरोपों के घेरे में घिरने लगी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरपरस्ती में चलता है, जिसके नेशनल कन्वीनर राज्य के तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, इनसे जुड़े लोगों पर परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी सरकार ने डाली और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, 6 लाख 20 हजार अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जिला बदर किया गया ताकि परीक्षा में नकल नहीं हो जाये।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जिनकी सरपरस्ती में कांग्रेस का प्रदेश का संगठन चलता है, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी सफल परीक्षा, रीट की परीक्षा हुई है जिसका स्थान गिनीज बुक आफ रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है इस रीट की परीक्षा में जितनी बड़ी चांदी कूटी गयी है, उसका नाम गिनीज बुक आफ रिकार्ड में निश्चित रूप से जब परतें दर परतें खुल जाएंगी तो, मंत्री महोदय, जरूर दर्ज होगा। इस रीट की परीक्षा का नाम गिनीज बुक आफ रिकार्ड में इसलिए भी जायेगा कि वह परीक्षा केन्द्र जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ब्लैक लिस्टेड घोषित किये थे, अचानक वह सफेद शाह अच्छे हो गये और उन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया ओर वह विवादित प्रिन्टिंग प्रेस, 2011 में जिस प्रिन्टिंग प्रेस की चर्चा राजस्थान में चहुं ओर गूंजी, कोलकाता की प्रिन्टिंग प्रेस को फिर पेपर छापने की अनुमति दी गयी और मैं समझता हूं कि 26 सितम्बर से ही जब गंगापुर सिटी में रीट का प्रश्न पत्र 15 लाख रुपये में सौदा करते हुए देशराज मीणा गिरफ्तार हुए और उसके बाद यह सिलसिला चला।

अध्यक्ष महोदय, संजय मीणा, कान्स्टेबल देवेन्द्र गुर्जर, फिर बत्तीलाल के पास होता हुआ मुख्य किरदार भजनलाल मीणा तक पहुंचा। एक आरएएस, एक जिला शिक्षा अधिकारी, दो आरपीएस, 12 कॉन्स्टेबल रीट की परीक्षा में गैर सरकार सह को-आर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और को-आर्डिनेटर प्रदीप पाराशर जो सरकार में नहीं, पर परीक्षा आयोजन में एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वह काम किसी भी रूप में लिया जाये तो उन सहयोगियों का सहयोग समझदार लोग काफी लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई हैं और कुल मिलाकर 42 लोग अलग-अलग महकमों के निलम्बित किये गये हैं। रीट की परीक्षा के एक माह बाद जब यह पूरी बातें चलीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, अचानक न जाने कौनसे सलाहकार ने सलाह दी और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ जाती है, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डा. डीपी जारोली को निलम्बित किया।

अध्यक्ष महोदय, यह षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था। ताना-बाना बहुत पहले से बुना गया। अलग-अलग स्थानों पर परीक्षा के आयोजन की प्रमुख भूमिका में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिले के को-आर्डिनेटर वह सब आये। अध्यक्ष महोदय, विडम्बना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकार्ड पर है कि रीट की परीक्षा से एक महीने पहले 5 करोड़ रुपये में इस प्रश्न पत्र को हूबहू चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्रपूर्वक 5 करोड़ रुपये में और उसमें भजनलाल, पृथ्वीराज, बत्तीलाल मीणा के जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और उसके बाद 12-12 लाख रुपये, वह पूरी सूची है, टेबल की जा सकती है, उसमें एसओजी ने माना कि यह सौदा हुआ। एक माह पूर्व जो रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का, उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपये एडवांस दिये गये और एसओजी ने अपने रिकार्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपये बरामद किये और एसओजी की जांच ने यह माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्रीजी, 300 अभ्यर्थी एक महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपये में रीट के प्रश्न पत्र को इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया।

अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, यह कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। सीकर में एक कलाम कोचिंग सेंटर है, उसका कमाल तो बहुत ही जोरदार है। मैं निवेदन करूंगा कि बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारण्टी है, फीस हमारी मनमर्जी है और वह बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा उनकी तीन महीने की फीस है 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और इनकी सबकी जिम्मेदारी है। यह जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है, कलाम का कमाल तो गजब का है। पूरी फैकल्टी में सरकारी नुमाइंदें, जो सरकार में नौकर हैं, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डा. लक्ष्मीनारायण बेनीवाल हैं जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पहले पिंक सिटी पब्लिकेशन से कालेज व्याख्याता में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में शत-प्रतिशत प्रश्न आ गये, बड़ा विवाद चला। राजेश्वर आरपीएस डेपुटेशन में लक्ष्मणगढ़ थे, आजकल बीकानेर में हैं, यह इस कलाम इंस्टीट्यूट के हैड हैं। राजीव अगड़िया कालेज के लैक्चरर हैं। युनूस खान उर्फ खान सर, जो कि पहले मेरे जिले के रतनगढ़ की कालेज में थे, आजकल सीकर में हैं। अरविन्द भास्कर बाड़मेर में प्रिंसिपल थे, आजकल सीकर में हैं। एस.एस. यादव जयपुर के शिक्षक हैं, पर सीकर में बैठे हैं। विवेक धाधड़िया 2018 में भूगोल में भर्ती हुए, कैसे सलेक्ट हुए, यह मैं आगे बताऊंगा। हरवंश गोदारा, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा वहां विराज रहे हैं। यानी ये वे लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए भी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपकी हर हालत में नौकरी लगेगी, जिसको गारंटीड बैच कहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर जांच की जाएगी, 2 जनवरी, 2020 को प्रथम श्रेणी व्याख्याता की जो परीक्षा हुई थी, इस कलाम ने क्या कमाल किया? अध्यक्ष महोदय, कुल जितना सलेक्शन हुआ है, उसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिशत देखेंगे तो इनका प्रतिशत बहुत बड़ा है। मैं निवेदन करूं, मैं कोई स्कोर करना नहीं चाहता, पर कई बार यह कहावत बिलकुल सही साबित होती है - 'जब सैयां भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का।'

जब मैं फोटोग्राफ देखता हूं, आप कहेंगे कि फोटो किसी के साथ भी हो सकती है, अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर विवाद नहीं करना चाहता। आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को सरकार में बैठे लोग लेकर और आदरणीय सोनिया गांधी जी को ले जाकर कहें कि ये थिंक टैंक हैं, ये कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करने वाले टैंक हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाये। हद तो तब हो गयी जब गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस एण्ड गुड गवर्नेंस से उसको पैसा साइफन किया जाये। अगर मैं गलत हूं तो आप जब जवाब दें, तब बतायें कि क्या यह सही नहीं है कि 2019-20 और 2020-21 के अन्दर 82 करोड़ रुपये इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस एण्ड गुड गवर्नेंस के माध्यम से दिये गये? क्या यह भी सही नहीं है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के इन्होंने तीन स्टेट कार्डिनेटर बना रखे हैं, उसमें से एक स्टेट कॉर्डिनेटर को रीट की जिम्मेवारी है। आपके सात रीजनल कॉर्डिनेटर हैं, मैं नाम बता दूंगा, उसमें पांच रीजनल कॉर्डिनेटर्स को रीट परीक्षा की जिम्मेदारी, यह सारा काम था। डा. डी.पी. जारोली और सब लोगों ने मिलकर एक महीने पहले राजस्थान के कोचिंग सेन्टरों से गारन्टेड बैच आप लगा लेना, हूबहू परीक्षा प्रश्नपत्र आपके पास पहुंच जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि रीट की परीक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो सम्बन्धित कलेक्टर और एस.पी. की खैर नहीं। वक्तव्य छपा, लोगों में विश्वास हुआ, पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि एस.ओ.जी. की जांच यह कह रही है कि सात जिलों के अन्दर रीट का प्रश्न-पत्र गया, चोरी का प्रश्न-पत्र बिका। इन सात जिलों के अन्दर कलेक्टर और एस.पी. के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? यह आप बतायें तो जरूर अच्छा लगेगा।

मंत्री महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने एक स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी बनायी। रीट में अगर परीक्षा केन्द्र प्रस्थापित करने हैं, आपको कॉर्डिनेटर लगाने हैं, यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसने कहा था कि रीट के प्रश्न-पत्र एस.पी. और कलेक्टर की निगरानी में जिले के स्ट्रांग रूम में रखे जायेंगे, यह जयपुर में कैसे बदला गया? रीट का प्रश्न-पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निलंबित सचिव अरविंद सेंगवा के आदेश से यह कहा गया कि यहां जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है। एस.पी. और कलेक्टर की निगाह में कोई बात नहीं और आपने शिक्षा संकुल में स्ट्रांग रूम के अन्दर परीक्षा का प्रश्न-पत्र रखवाया। सीसीटीवी कैमरे क्यों बन्द हुए? पुलिस वहां से क्यों हटी? दो चाबियां थीं, एक जिला शिक्षा अधिकारी और एक आपके कॉर्डिनेटर प्रदीप पाराशर के पास। ये दोनों चाबियां किस प्रकार एक मिलीं? किस प्रकार इस रीट की चोरी में शामिल रविन्दर सिंह, डी.ई.ओ. और रामकृपाल मीणा, इनको निलंबित करने और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। यह कौन था जिसने अध्यक्षीय रूप में टेलीफोन करके कहा कि दोनों चाबियां ले जाओ और प्रश्न-पत्र निकालकर हूबहू ले आओ? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चोर को भी कितना ईमानदार माना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसकी भी सलाहकार जी ने सलाह दी। रीट के लेवल - 1 व लेवल - 2 के दोनों प्रश्न-पत्र उसी एक स्ट्रांग रूम में थे। मंत्री महोदय, चोर कितना ईमानदार था? इस कलयुग में उस चोर की ईमानदारी हरिशचन्द्र की ईमानदारी के बराबर होगी। उसने एक प्रश्न-पत्र चुराया, दूसरे प्रश्न-पत्र पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रश्न-पत्र की आपने परीक्षा रद्द की। मेरे समझ में नहीं आया।

आपने जब परीक्षा के मुख्य आयोजनकर्ता डी.पी. जारोली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविन्द सैंगवा, सुभाष यादव, बी.एस. बाजवा को निलंबित किया और प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया तो फिर उसके बाद बचा क्या है? मैं समझता हूं कि यह सौ करोड़ से ज्यादा का सौदा था। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वह तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी।

(समय: 11:45 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मेरा आरोप है कि पहले जो ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केन्द्र थे। सभापति महोदय, कलाम का तो मैंने बताया, कलाम का कमाल तो है ही, प्रिंस भी प्रिंस है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि राजाओं के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी। यह प्रिंस कालेज, सीकर, सीकर बाईपास पर वह विशाल बिल्डिंग।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं प्रतिपक्ष के नेता, आपसे भी मांग करूंगा कि ईडी को लिखवाओ कि यह इतनी सम्पत्ति कहां से आ गयी? चार साल के अन्दर प्रिन्स कालेज सीकर और कलाम इंस्टीट्यूट, आप इनकी बिल्डिंगें देखिये, करोड़ों रुपये की बिल्डिंगें हैं। आपने कोचिंग सेन्टर बनाया, पहले ब्लैक लिस्टेड किया। कमला देवी कालेज, अलवर को ब्लैक लिस्टेड किया, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय कोटकासिम को ब्लैक लिस्टेड किया, शिव शक्ति स्कूल, जयपुर को ब्लैक लिस्टेड किया। सुनील आई.आई.टी. जयपुर को आपने वापस परीक्षा केन्द्र बनाया। पन्नाधाय संस्थान टोंक को बनाया। मेरी सरकार से मांग है कि इन ब्लैक लिस्टेड केन्द्रों को आपने रीट की परीक्षा में चीट करने के लिए पुन: परीक्षा केन्द्र बनाया, उसमें कौन किरदार थे?

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान 04 फरवरी, 2020 को रात्रि को 09.33 पर, एक राजस्थान पेंशन ग्रुप है, सभापति महोदय, पेंशन ग्रुप के बारे में तो आजकल आपको और मुझको चिन्ता करनी पड़ेगी ही। हम उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया की साइट खोली तो रसद मंत्रीजी, मैंने डी.पी. जारोली का एक मैसेज लिखा हुआ पढ़ा, इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है - 'मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कुछ बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है। मैंने दबाव में आकर सरस्वती प्रिन्टिंग प्रेस, कलकत्ता को प्रश्न-पत्र छपाने का आदेश दिया'।

उसके बाद एक नौजवान शिक्षक ने, उस क्षेत्र से है, जहां से मैं एक बार एमएलए रहा हूं, उसका नाम असलम चौबदार है, उसने यह बात मीडिया में कह दी। हमारे सामने बैठे हुए मंत्रीजी नाराज हो गये। आपका तो उसने नाम नहीं लिया। आपने उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर नंबर 29/2020, आनन्द पुरी में। अन्डर सेक्शन देखें, आई.टी. एक्ट 2008 सेक्शन 66, मंत्रीजी सर्वोच्च न्यायालय कभी स्क्रैप कर दिया। आपने करवाया तो इनको यह तो कहते। फिर आपने 499, 505 और 506 के अन्दर उसको गिरफ्तार किया। यह तो इस्तगासे से होता है। फिर आपने अचानक साइट से एफ.आई.आर. नम्बर हटवा दिया। फिर 151 में उसको गिरफ्तार करके, सिर्फ इस बात पर कि यह बोला क्यों?

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि शक उस समय गहरा गया। सभापति महोदय, टेट 2011-12 की बात बड़ी हुई। कलकत्ता प्रिन्टिग प्रेस की बात मैंने पहले भी की है। दुबारा उसी प्रिन्टिंग प्रेस को, क्योंकि किरदार बदले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थे। पहले एक बड़े किरदार ने 2011-12 में सीधा खुद आदेश दिया था, क्योंकि खुद ही आदेश देने वाले थे। अब वे किरदार सरकार में आ बैठे। इसलिए उन्होंने अपने नये किरदार, नये दोस्त जारोली को कहा कि यह आदेश दे और उसने वह आदेश दिया। मैं समझता हूं कि अब उस एफ.आई.आर. का जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं है। एस.ई.पी. ने 196/2013 में दर्ज की थी। मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं दिया, मैं उसके ऊपर बात नहीं कहना चाहता, पर आज भी अगर यही आयोजक रहे, यही प्रिन्टिंग प्रेस रही और आपने 62 हजार पदों पर रीट लेवल-2 की परीक्षा पुन: कराने की घोषणा कर दी तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार की परीक्षा होगी, यह सबके सामने है। यक्ष प्रश्न यह भी है कि रीट लेवल-2 के अन्दर जिन 10 लाख 32 हजार 853 पात्रता वाले, कहां से कहां प्रश्न-पत्र पहुंचा है। 12 लाख 67 हजार 540 परीक्षा में बैठे हैं। 10 लाख 32 हजार 853 में से 7 लाख 73 हजार 512 को इलिजिबल मान लिया। वाह क्या रिजल्ट है? हमारे बच्चे काफी आगे आ गये। 72 हजार विद्यार्थी ऐसे थे, 150 में से 144 नंबर लिये। क्या इंटेलिजेंस है? अभी हाल ही में, 72000, 150 में से 146, 144, 143 रीट लेवल-2 में।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि लोकेश मीना ने आत्महत्या की, अखबारों में आया और आत्महत्या इसलिए की कि उसने रीट की परीक्षा में पास कराने के लिए कैलाश विश्नोई से 24 लाख लिये, देवाराम गुर्जर से सवा लाख लिये। अब आपने रीट की परीक्षा रद्द कर दी सैकण्ड लेवल की, आत्महत्याओं का ये सिलसिला राजस्थान में अनवरत जारी रहेगा। आप कोई न कोई बन्दोबस्त करें। मैं मांग करूंगा मुख्य किरदार जी, बुलाकर उनको कह दो कि पैसा-टका जो लिया है, पहुंचा देंगे वापस, मरना बन्द करो। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। अभी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हुआ। मुख्य मंत्रीजी का बयान, परीक्षा रद्द करने से खुश नहीं हूं लेकिन विपक्ष की हरकतों से तंग आकर फैसला लेना पड़ा। हमारी हरकतें, भाजपा वाले नॉन-इश्यू को इश्यू बनाते हैं। प्रश्न पत्र तो पूरे देश में लीक हुए। बिहार में तो बेरोजगारों ने ट्रेन जला दी और भाजपा के लोग निकम्मे हैं। अब निकम्मे लोगों की इतनी सी बात मनवा दीजिए सी.बी.आई. को जांच दिलवा दो। हम कब कह रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी, आप तो अपने कामदारों को अच्छा मानो, किरदारों को अच्छा मानो परंतु निकम्मा माना है, बहुत-बहुत धन्यवाद, उसकी बात हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी कहेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं बात खतम करूं उससे पहले, एक साल पहले आपने राजस्थान पब्लिक एग्जामिशन (प्रीवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) विधेयक को लाने की घोषणा की थी इस सदन में, एक साल पहले। चूंकि परीक्षा रीट की हो जानी चाहिए थी, उसके बाद लेकर आएंगे आप। मेरा आरोप है एक साल पहले जो आपने घोषणा की थी राजस्थान पब्लिक एक्जामिशन (प्रीवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) विधेयक की, क्यों नहीं लेकर आए? दूध की रखवाली बिल्ली को। अब आप देख लो साहब, रामगोपाल मीना जी और प्रदीप पाराशर जी, मैं मांग कर रहा हूं, ये बच्चे जिन्होंने 7 लाख 73 हजार पात्रता मिली और 12 लाख, इनका कितना खर्चा लगा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दैनिक भास्कर ने लिखा, प्रत्येक विद्यार्थी पर औसत परीक्षा की तैयारी में 1 लाख 25 हजार रुपया खर्च हुआ। 10 हजार करोड़ रुपये बेरोजगार की जेब से निकल गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक रामगोपाल मीना के कालेज पर बुलडोजर नहीं, आप यूपी टेट की परीक्षा की तरह सबकी सम्पत्तियां जब्त करते। सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा:

"न मांझी है, न रहबर है, न हक में हवाएं हैं,
है किश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है,
जी बहुत चाहता है, सच बोलें,
क्या करें हौसला ही नहीं होता।।"

आप में से बहुत से लोग सच बोलेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, सभापति महोदय। बहुत सारे उदाहरण और प्रसंग हमारे माननीय उप नेता प्रतिपक्ष के भाषण में आये हैं। मैं उनको दोहरा कर सदन का समय जाया नहीं करूंगा। पिछले दिनों इस सारे घटनाक्रम पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक स्टेटमेंट आया कि विपक्ष नॉन-इश्यू को इश्यू बना रहा है। मेरा सवाल मुख्य मंत्रीजी से ही है कि यदि किसी भी तरीके से किसी प्रसंग में यदि परीक्षा रद्द हुई, एस.ओ.जी. की जांच हुई तो फिर ये नॉन-इश्यू किस तरीके से हुआ? इसी तरीके से परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा रद्द होने के बाद किसी केन्द्र की एजेंसी से जांच की मांग की जाती है तो यह बात समझ से परे है कि उस पर बेरोजगारों की भर्तियों पर न तो वह

(श्री सतीश पूनियां)

एजेंसी भर्ती कराती है, एजेंसी सिर्फ जांच करती है और जांच करके निरपेक्ष तरीके से उन दोषियों और आरोपी तक पहुंचती है।

सभापति महोदय, समस्या खुद सत्ताधारी दल ने अपने वायदों से पैदा की है। भाषणों में भी और जन घोषणा पत्र में भी बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि यदि हमारी सत्ता आएगी तो हम राजस्थान के लाखों लोगों, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जन घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें भी इस बात का उल्लेख होता है। 70 लाख बेरोजगार अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं और नौकरियां महज मिलती हैं उस दौरान 48 हजार लोगों को। अभी पिछले तीन बजट में कुल 1 लाख 78 हजार भर्तियां निकालने की घोषणा हुई। इस प्रकार तीन वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 67 हजार 429 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें रीट का लेवल-2 का पेपर रद्द होने के बाद 50 हजार भर्तियां बचती हैं। अभी असत्य इसलिए पकड़ा जाता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया 2022-23 के अभिभाषण में बताया कि एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 94 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। तीन साल में एक लाख लोगों को कैसे दे दी? इसका कोई जवाब सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। तीन साल में जे.ईएन., कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, रीट, पटवारी, एस आई, इनकी सारी भर्तियां पेपर आउट होने से रद्द हो गयीं और 15 से अधिक भर्तियां प्रशासनिक और अन्य कारणों से रद्द हो गयीं। ये सरकार के कामकाज की एक बानगी है।

30 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जिनको ये भरोसा था कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। सरकार सिर्फ डेढ़ लाख को देती है और उसमें भी कंडीशन लगा देती है कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, इसमें ड्रेस पहनकर आइए और डिपार्टमेंट्स में अपना काम कीजिए। अधिकांश विद्यार्थी पार्ट टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि वह भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस पूरे भर्ती प्रकरण में 2 अक्टूबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी का बयान आता है कि विपक्ष और बीजेपी के लोग बेवजह इसको तूल दे रहे हैं। भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये तो ऐसी परीक्षा है जिसका गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया जा सकता है। मुझे अफसोस है सदन में कहते हुए कि राजस्थान इस पूरे प्रकरण से शर्मसार हुआ है, कलंकित हुआ है। राजस्थान में इस तरीके से

(श्री सतीश पूनियां)

कभी भी संगठित नकल नहीं हुई और नकल नहीं, मैं तो इसको कहूंगा बेरोजगारों के हक पर सीधे-सीधे डाका पड़ा है। बानगी यह है कि इस पूरे रीट के मामले में उदयपुर के एक नौजवान की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वह रीट परीक्षा में पास होने के लिए पेपर के लिए किसी संचालक को पैसे देता है, कोचिंग संचालक को और वही कोचिंग संचालक उसकी हत्या कर देता है। रानीपुरा के लोकेश मीना की सुसाइड और उससे जितने जुड़े हुए तथ्य हैं, उसकी यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो मुझे लगता है बहुत लोगों तक आंच आयेगी, इसलिए हम लोगों ने एक सूत्री मांग रखी थी। एस.ओ.जी. की जांच की अपनी मर्यादा है, एस.ओ.जी. मंत्रियों और मुख्य मंत्री से पूछताछ नहीं कर सकती इसलिए कोई निरपेक्ष केन्द्र की एजेंसी इसकी जांच करे। यह निवेदन हम लोगों ने किया था।

माननीय सभापति महोदय, कई प्रश्न खड़े होते हैं। इसमें पूरा मास्टर माइंड जो एक संस्थान है, जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल। उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पेट्रोन हैं, हमारे यहां के मौजूद माननीय मंत्रीजी। वह उदयपुर में एक सहयोग संस्थान का फीता काटते हैं जो कोचिंग चलाता है। उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुडे हुए तमाम पदाधिकारी, आयुक्तालय में भी नौकरी करते हैं। वह लोग प्राइवेट लोग हैं और उनको इस तरीके से अलग-अलग जगह, अलग-अलग भूमिकाओं में रखा जाता है। अभी तक जितने पेपर होते थे कोषागार में रखे जाते थे। संकुल में रखने की योजना क्या थी? सी सी टी वी कैमरे क्यों नहीं लगाये गये? और उन राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए उन प्राइवेट लोगों को इस परीक्षा का समन्वयक क्यों बनाया गया पूरे प्रदेश भर में? यह भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने ये कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षण में हुई है, वह श्रीमान जारौली है कहां? जो डाक्टर बने सिंह है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल का हिस्सा है और इस पूरे प्रकरण के मास्टर माइंड हैं, उनको हमेशा बराबर आयुक्तालय में ही पोस्टिंग क्यों दी गयी? वह बने सिंह कहां है और उनके बयान किस तरीके से लिए जाएंगे और क्या वह खुलासा करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि यह कंट्राडिक्शन यहीं पैदा होता है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं होता और जो ऐसी बात करते हैं, उसको जेल में डालो।

(श्री सतीश पूनियां)

(समय: 12.00 बजे)

उन्होंने भी कहा कि बीजेपी अपने तथ्य प्रस्तुत करे, हम किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हैं। एसओजी की मर्यादा छोड़ दीजिए, यदि आप तैयार ही हैं तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, तो देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर रहे व्यक्तियों को, उनके खानदान को भी जेल जाना पड़ा है।

मैं इस सदन में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से भी और सदन के माध्यम से भी कि राजस्थान में लाखों-करोड़ों बेरोजगारों पर कुठाराघात करने वाले इस पेपर लीक की, इस पेपर के डाके की, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिये। सक्षम एजेंसी से होनी चाहिये। मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह जांच निष्पक्ष होती है, इसमें सब लोगों, क्योंकि यह उन लोगों से जुड़ा हुआ सीधा-सीधा मसला है, राजस्थान के करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ मसला है। यह केवल किसी एक परीक्षा, एक व्यक्ति से, किसी जाति बिरादरी से, किसी दल से सम्बन्धित नहीं है। ऐसे मसलों पर, दल से ऊपर उठकर भी, मुझे लगता है कि उन करोड़ों बेरोज़गारों के भविष्य के लिए ईमानदारी के साथ, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं कर सके। यह सिलसिला हो सकता है पहले भी हो, लेकिन छोटे परिमाप में थे। उसके बाद से, 2019 के बाद से लगातार, 29 दिसम्बर को पुस्तकालयाध्यक्ष की परीक्षा हुई। 25 दिसम्बर को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तीन की हुई। जेईएन की हुई। 23 अक्टूबर को पटवार की हुई। राजस्थान उप निरीक्षक की हुई। 14 सितम्बर को फिर एसआई की हुई। रीट 2021 की हुई। 26 सितम्बर को वापस रीट 2021 की हुई। इन सारे प्रकरणों में अधिकांश लोग तो फरार हैं। बहुत सारे मामले लम्बित हैं। मुझे लगता है कि कोई न कोई स्वतंत्र एजेंसी निष्पक्ष तरीके से जांच करे, ताकि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को भी न्याय मिले। उनके परिवारों को यह सम्बल मिले कि कहीं न कहीं प्रकृति न्याय करती है, कहीं सत्ता न्याय करती है।

सभापति महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि लाखों-करोड़ों बेरोजगारों पर जो कुठाराघात हुआ, उसमें कोई भी दोषी हो, मुझे खुशी हुई कि इसी सदन के एक माननीय मंत्री ने कहा कि इसमें कोई भी लोग शामिल हो, चाहे मुख्य मंत्री ही क्यों न हो, चाहे मंत्री ही क्यों न हो, यदि इसमें जांच की आंच उन तक भी आती है, तो निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही हो, ताकि राजस्थान में एक उदाहरण पेश हो। यह उदाहरण गिनीज बुक में इस रूप में नहीं हो कि संगठित

(श्री सतीश पूनियां)

गिरोह और नकल राजस्थान में काम करते हैं। गिनीज बुक में नाम इस रूप में दर्ज होना चाहिए कि राजस्थान में लाखों बेरोज़गारों के साथ जो अन्याय, कुठाराघात करता है, उनको जेल के सींखचे दिखाने की भी हिम्मत राजस्थान की सरकार, कोई एजेंसी कर सकती है, तब तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के उन बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, नहीं तो लीपापोती होगी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई दोषी होगा, तो राजस्थान की पूरी सरकार होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करें। नैतिकता और ईमान है तो ये बातें सच्चाई के साथ, सबके सामने आनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, तीन दिन के लम्बे संघर्ष के बाद, आपने रीट भर्ती पेपर पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें विस्तार से बताईं। मैं तो आपके माध्यम से इस सदन में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से लगभग 38 लोगों को कन्वीनर क्यों बनाया गया? अजमेर में ब्लैक लिस्टेड स्कूल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया, क्योंकि वह राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े व्यक्ति का था। रीट के पेपर मुद्रण का काम सरकार के एक मंत्री के कहने से, उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, जिसके कारण खुद मंत्रीजी को, बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। पेपर्स को शिक्षा संकुल में क्यों रखा गया, जबकि आरपीएससी अपने पेपर्स को पुलिस कस्टडी या ट्रेजरी में रखती है? कंटेनर के चालक की मौत आज संदेहास्पद है। उसे लालच क्यों दिया गया कि जल्दी पहुंच जाओगे तो आठ हजार रुपये दिए जाएंगे?

सभापति महोदय, सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। चालक की पत्नी खुद रीट की अभ्यर्थी थी, तो ऐसे में उसे कन्टेनर लाने के लिए क्यों कहा गया? पूरा प्रदेश आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता है। बजट का बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आज युवा बाहर, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलित हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डा. डीपी जारोली को चेयरमैन बनाने से पहले क्या उन्हें परीक्षा आयोजन का अनुभव था? क्या वह परीक्षा नियंत्रक थे?

(श्री नारायण बेनीवाल)

नहीं थे, तो क्यों बनाया? जब उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है, वह बीस दिन से कहां है? इसका सरकार सदन के सामने खुलासा करे। एसओजी ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? क्या सरकार को डर है कि वह मंत्रियों व मुख्य मंत्री कार्यालय के कई आईएएस और बड़े अधिकारियों का नाम ले सकते हैं? इस डर के मारे उनको गायब कर रखा है? यह सदन के सामने स्पष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आरपीएससी समेत सभी प्रमुख भर्ती संस्थाओं के मुखिया का चयन राजनीतिक स्तर पर नहीं हो, उसके लिए पृथक से कानून बने। उसे परीक्षा आयोजन का अनुभव, पेपर का अनुभव, साथ ही शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर बैठाने से प्रदेश का युवा आज कुंठित है।

सभापति महोदय, बड़ी हंसी की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में, कभी किसी की परीक्षा नहीं ली, वह आरपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, वह राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। आखिर हम राजनीति के चलते, राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? जब किसी संस्था का मुखिया उसकी पूरी प्रक्रिया को जानता ही नहीं है, उसको आपने अध्यक्ष बना दिया, तो बेड़ा गर्क होना तो तय है। राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों की होती हैं जो सीएम साहब के सब्जी ले जाते हैं। वे आरपीएससी चेयरमैन बन जाते हैं, बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं तो वह युवाओं के भविष्य का क्या ध्यान रखेंगे, इस पर सदन को गहराई से विचार करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पदों पर बैठाने का काम केवल इन संस्थाओं में ही नहीं हो रहा है, प्रदेश के तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में यह धन्धा बेखौफ चल रहा है। डा. भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें। तो जिस व्यक्ति को कुलपति बनाया गया, वह लॉ विषय का ही नहीं है, उनके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में थानवी जी को कुलपति बनाया, जो योग्य नहीं है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि प्रदेश के मुखिया जी ने डा. बीआर अम्बेडकर यूनिविर्सिटी के दीक्षांत समारोह में यह कहा कि कोई कुलपति बनने को तैयार ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जबकि उनके सामने ऐसे योग्य व्यक्ति राजस्थान में बैठे हैं, जिनको यदि कुलपति बनाया जाए तो निश्चित रूप से ... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस तरीके से कोई ...(व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): हम आपकी बात सुनते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, बीच में इंटरवीन नहीं करें, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): हम आपकी बात सुनते हैं, आप हमारे विचारों को सुनिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। दो घण्टे का टाइम था, प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। श्री बेनीवाल। (व्यवधान) कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें, ऐसे नहीं। इस तरह से नहीं। (व्यवधान) एक मिनट आप विराजिये। विराजिये। आसन से व्यवस्था हो चुकी, माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है, दो घंटे का समय निर्धारित है ...(व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप विराजिये, सहयोग कीजिये। अंकित नहीं हो रहा है। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, परम्पराओं का निर्वहन करें। (व्यवधान) आप बहुत वरिष्ठ हैं। क्यों खड़े हो रहे हो, क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? आसन से व्यवस्था हो गई, बीच-बीच में क्यों उत्तेजना पैदा करते हो? (व्यवधान) श्री बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री जी के सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे जूनियर विधायक की बात को सुनने से ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सुनने की क्षमता नहीं है...(व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज सहयोग करें। आप लोग आसन की व्यवस्था नहीं मानेंगे? (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं, प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज आप सहयोग करें। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: राजेन्द्रजी, आप लोग विराजिये। किसी का कोई अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): जानते तो आप भी जारोलीजी को थे न पहले लेकिन उन्होंने क्या किया? (व्यवधान) ऐसे दादागीरी नहीं चलेगी आपकी। आप किसी मुगालते में मत रहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आसन सक्षम है। आसन अपनी व्यवस्था देने में सक्षम है। (व्यवधान) विराजिये आप लोग। मजाक बना दिया। अपनी वाणी पर लगाम लगाइये। माननीय सदस्य, यह सदन है, कोई चौपाल नहीं है जहां बैठकर आप जो चाहे वह बोलेंगे। आसन की अपनी व्यवस्था है। विराजिये आप। मैं आपको अलाउ नहीं करता। माननीय सदस्य श्री बेनीवाल। प्लीज, विराजिये आप। माननीय श्री बेनीवाल, आप सिर्फ अपनी बात कहेंगे। कौन वरिष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे, फिर माननीय कटारिया साहब बोलेंगे।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, सारी बातों का सारांश मैं एक ही बात के साथ लास्ट में मैं मेरा भाषण कंक्लूड करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कल जब कटारियाजी के भाषण के बाद यह बात कही कि आपके शासन काल में भी कई पेपर आउट हुए हैं तो बाहर का जो युवा है, आज हमने जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर और मीडिया के प्लेटफार्म पर यह कहा कि अब जो बात है, रीट भर्ती पेपर भर्ती का मामला, यह किसी कोई पार्टी की विचारधारा का मामला नहीं है। यह समय है कि राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के यह भविष्य से जुड़ा हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सब लोग मिलकर एक प्लेटफार्म पर आकर ऐसा कानून बने और जिन-जिन व्यक्तियों ने इस मामले में चीट किया है, वह सारे के सारे व्यक्ति जेल जाये वरना बाहर आज का युवा यही कह रहा है कि कहीं न कहीं मिलाजुली का खेल इस देश के अन्दर चल रहा है और यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी.बी.आई. को सौंपी जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, नरपत सिंहजी को पांच मिनट के लिए अलाउ करें।

श्री सभापति: मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम पक्ष हो या विपक्ष, हम इस गम्भीर समस्या को राजस्थान की एक गम्भीर समस्या समझकर इसको हल करने का प्रयत्न करें क्योंकि इससे लाखों बच्चे और करोड़ों परिवारों का दर्द देखा नहीं जाता है। सन् 2018 से लेकर इस वैकेंसी को भरने के लिए और खाली पड़े हुए विद्यालयों में बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए एक लम्बी प्रक्रिया के बाद जो स्थिति बनकर आई है, आपने बजट 2019-20 में यह कहा था कि हम 75 हजार लोगों की भर्ती करेंगे, उसमें से यह 21 हजार पद शिक्षकों के थे, जिसकी भर्ती का काम आपने शुरू किया।

मैं यह सोचता हूं कि विषय को थोड़ी सी गम्भीरता से समझें। 19 दिसम्बर को पहली विज्ञप्ति जारी हुई इन पदों को भरने के लिए और अभी हमने जो परीक्षा करवायी है वह सितम्बर 21 को, 26 को और अभी उसमें अपन उलझे हुए हैं कि पता नहीं यह भर्ती कब तक होगी, उस बच्चे को कब अध्यापक मिलेगा, उस बच्चे को कब जिंदगी में सरकारी नौकरी मिलेगी और हमारी कमियों के कारण से जो दुर्गति होकर जो बदनामी होती है, उसको गम्भीरता से लें।

एक इस विषय को यह डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती को रोकने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। नहीं। मैंने यह पहले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आपने उन दोनों को मिलाकर 62 हजार की भर्ती के बारे में अपना मन बनाया, स्वागत। अब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। उसकी तारीख देकर जब भी आपको परीक्षा करवाना है, जिस ढंग से परीक्षा करवाना है लेकिन इस परीक्षा की दुर्गति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के सिस्टम में कुछ विशेष लोगों से राय मशविरा करने के बाद, यू.पी.एस.सी. भी तो इतने लाखों बच्चों की नौकरी करवाती है, इतने सालों से हो रही है। वहां पर पेपर कभी भी आउट नहीं होता है, कभी कोई समस्या नहीं आती तो हम उनका भी सहयोग लें। हम राजस्थान में इतनी बड़ी परीक्षा को किस ढंग से करवायें, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति आकर खड़ी नहीं हो।

अब इसमें आपने यह देखा होगा कि 2019 से शुरू किया और पहली भर्ती का 31 हजार पद भरने के लिए आपने अनाउन्स किया और 2 अगस्त को आपने तारीख तय कर दी। 2 अगस्त को नहीं हो पायी। फिर आपने उसके बारे में 2 सितम्बर तय की, उसमें परीक्षा नहीं हो पायी। उसके बाद फिर आपने फरवरी, 2021 में परीक्षा की डेट तय की, उसमें आप नहीं कर पाये। उसके बाद फिर 25 अप्रैल को की, वह भर्ती नहीं कर पाये। उसके बाद में फिर आपने बढ़ाकर 25 अप्रैल के बाद में आपने 20 जून की तारीख डिक्लेयर की, उसमें यह परीक्षा नहीं करवा पाये। उसके बाद आपने जाकर 25 सितम्बर के दिन 2019 से जिन बच्चों ने अपने फार्म भर रखे थे, उनको इस परीक्षा में बैठने का सुअवसर मिला और राजस्थान की जनता को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस रीट परीक्षा में प्रत्येक गांव और शहर के लोगों ने इन बच्चों को ठहराने से लेकर, इनकी भोजन व्यवस्था से लेकर जो व्यवस्था की वह वास्तव में देखने लायक थी। पहली बार मैंने भी अपने जीवन में उन बच्चों को अपना बच्चा समझकर जिस प्रकार की व्यवस्था की, उसके लिए वास्तव में उन सब लोगों को जिन्होंने यह व्यवस्था की, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं लेकिन परिणाम क्या निकला?

रीट में लेवल एक और दो की परीक्षा हुई। पेपर एक ही जगह से निकला है। स्ट्रांग रूम से निकला है। एक परीक्षा निरस्त हुई और एक परीक्षा निरस्त नहीं हुई। कृपा करके उस पर भी एक निगाह तो डाल दो। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी इसी प्रकार से जो सही हकदार है उनको नहीं मिल पा रहा है और जो हकदार नहीं है, उनको मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा कि गिनीज बुक में लिखना चाहिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़िया लिखा गया? इस गिनीज बुक में 38 लोग अन्दर जेल में हैं, वह भी लिख दो, गिनीज बुक में 38 लोग जेल चले गये। अच्छी भाषा है।

मैं यह सोचता हूं और मैं थोड़ी-सी बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपका अरविन्द कुमार सेंगवा है, इन्होंने एक आदेश निकाला था, इस परीक्षा की व्यवस्था के लिए 12.04.2021 के दिन। नहीं सॉरी, 12.09.2021 को। रीट, 2021 की परीक्षा हेतु जिले में संवेदनशील, अति संवेदनशील केन्द्रों की सूची एवं जिले के प्रश्न पत्र रखवाने हेतु कोषागार, उप कोषागार की सूची एवं रोड चार्ट भिजवाने हेतु।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रीट, 2021 की परीक्षा में सफल आयोजन हेतु संवेदनशील, अति संवेदनशील केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाना प्रस्तावित है। दिनांक 11.09.2021 को रीट कार्यालय में आयोजित बैठक में आपको जिले की परीक्षा केन्द्रों की सूची उपलब्ध करवायी गयी। अत: संवेदनशील, अति संवेदनशील केन्द्रों की सूची परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन करवाकर शीघ्र ही और मेल आई.डी. से भिजवाने का कष्ट करें। अग्रिम कार्यवाही की जा सके। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट को जिले के कोषागार के स्ट्रांग रूम में रखवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा जिन जिलों के लिए जिला मुख्यालय के अतिरिक्त उपखंड तहसील स्तर पर परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं उन केन्द्रों को प्रश्न पत्र उप कोषागार/थानों के मालखाने में सुरक्षित रूप से रखवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

यह आपका उसका आदेश है। यह आदेश क्यों किया उसने? ताकि पेपर की सुरक्षा रहे, इसके लिए किया, लेकिन आपने क्या काम किया? यह प्रश्न, क्यों हम बार-बार आपसे यह मांग कर रहे हैं? कोई आपसे दुश्मनी है इसलिए नहीं कर रहे हैं। आपने इस बार व्यवस्था को चरमरा दिया। जब इतना स्पष्ट आदेश आपके पास था तो अगर 32 जिलों में इस व्यवस्था को करने का काम आपने किया तो यह जयपुर की क्या विशेषता थी, यहां है बिन्दु कि इस जयपुर में ऐसी क्या खासियत थी कि यहां के उस पेपर की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करके आपने एक प्राइवेट लोगों की व्यवस्था किस आर्डर से की, यह आर्डर किसने दिया? वह आर्डर कम से कम आप शिक्षा मंत्रीजी, पढ़ देना कि जयपुर की व्यवस्था के लिए जिन लोगों को आपने लगाया, वह किस आर्डर के तहत और किस व्यक्ति ने उसको लगाया?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं इसलिए आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि रीट परीक्षा के लिए कॉर्डिनेटर, कालेज शिक्षा के रिटायर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गयी। यह किस ताकत से दी गयी थी? यह वह ही पाराशर है न? यह वह ही पाराशर है जो पहले भी पकड़ा गया था, उसी को आपने रीट की जिम्मेदारी भी दी। इसके साथ कि कॉर्डिनेटर सुभाष यादव, बी.एस. बैरवा, ध्यानचंद गोठवाल और रामकृपालजी मीणा को आपने यह इस आपके और मेरी नाक के नीचे वाले सेंटर की जिम्मेदारी इनको दी। ये कौन लोग हैं? यह मीणा कौन है। एक प्राइवेट कालेज चलाने वाले व्यक्ति को जो स्वयं परीक्षा कराता है उसको आपने स्ट्रांग रूम की चाबी देकर रखवाली के लिए लगा दिया और बाड़ ही खेत को खा रही है और आप कह रहे हैं कि जांच नहीं होगी। आप कम से कम कुछ विचार तो करो कि क्या कर रहे हो। बोर्ड का जो चेयरमैन है, उसका आर्डर तो यह कह रहा है कि इस तरह से व्यवस्था करनी है। उसको इग्नोर करके नई व्यवस्था किस व्यक्ति ने की? इसलिए इसकी जांच करना बहुत आवश्यक हो गया है। आपने इसमें जो कॉर्डिनेटर लगाया है, यह आपका 19.02.2021 का आर्डर है, इसमें लिखा है - "with kind sanction of the Chairman, Shri. Ashok Gehlot Ji, is an advisory committee of the Rajasthan Rajiv Gandhi Study Circle is constitute following are nominated members of the Committee." हमारा आपसे बार-बार आग्रह यह है कि जयपुर की व्यवस्था इन कॉर्डिनेटर को, शिक्षाविदों को 19.02.2021 की सूची में अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रोफेसर सतीश कुमार जी का जो आर्डर है, इस आर्डर के अन्दर समाहित लोग हैं। इसलिए आपसे कहना है कि यहां तक जांच करना मतलब अशोक गहलोत की जांच करना, यहां तक जांच करने का मतलब सुभाष गर्ग की जांच करना। यह सजेशन करके इस प्रकार के लोगों को सुरक्षा के लिए लगाया, जहां से यह पेपर चोरी हुआ। आप पक्ष के हो सकते हो, विपक्ष के हो सकते हो लेकिन सच्चाई को अगर आप नजरअन्दाज करोगे तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसका दोषी अगर गुलाब चन्द कटारिया के टाइम पर भी पेपर लीक हुए तो मैं आपको सौगन्ध दिला रहा हूं, आप मेरे समय की परीक्षाओं को भी, मेरे समय में भी यदि हुआ है तो उसको भी जोड़कर सीबीआई को दे दो। अगर उसमें मैं भी दोषी होऊंगा तो सज़ा पा लूंगा। लेकिन इसके कारण से आप ना नहीं कर सकते राजस्थान के उन बच्चों को, कि केवल और केवल इसी परीक्षा केन्द्र पर यही सारे के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सारे शिक्षाविद, नाम तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, उसी के सारे के सारे नॉमिनेटेड लोगों को आपने स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी। यह किस आधार पर दी, थोड़ा सा बता देना।

यही नहीं, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कल्लाजी। ईमानदारी से इतना पोस्टमार्टम करने का हमको न तो दिमाग लगा, न मौका लगा लेकिन जैसे-जैसे परीक्षा के बाद में बढ़ता गया, वैसे-वैसे एक पड़त खोलते गए तो ऐसा लगा कि यह तो महान, योजनाबद्ध तरीके से लूटखोरी का धंधा हुआ है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं बहुत गम्भीर आरोप लगा रहा हूं। इन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्था की, वह आपको बताता हूं। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं। डीपी जारोली साहब हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जो इस सूची में हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल में। परीक्षा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी इनके पास थी। यही है न। प्रदीप पाराशर सेवानिवृत्त कालेज व्याख्याता, क्या काबिलियत है? पहले भी सज़ा पाया हुआ है, चूंकि शिक्षाशास्त्री है इसलिए जयपुर रीजनल कॉर्डिनेटर है, इनको जयपुर जिले की जिम्मेदारी दी। देखा, बाड़ खेत कैसे खाती है। श्री सुभाष यादव, सहायक निदेशक कालेज शिक्षा है, प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य हैं, इसी राजीव गांधी स्टडी सर्किल के। इसको लगाया। श्री बीएस बैरवा सहायक निदेशक, कालेज शिक्षा, इसको भी कॉर्डिनेटर लगाया, वह भी इस सूची में है। ध्यान चन्द गोठवाल, यह भी स्टेट कॉर्डिनेटर है, उसको भी इसमें लगाया है। निजी स्कूल स्टाफ मतलब प्राइवेट स्कूल से सुनिता पंचौली निजी स्कूल चलाती है। सुनिता पंचौली को रीजनल कॉर्डिनेटर, अजमेर आपने लगाया है। देवेन्द्र पाराशर भरतपुर का रीजनल कॉर्डिनेटर लगाया है। इसको आपने अजमेर और धौलपुर की जिम्मेदारी दी है पेपर के बारे में। नदीम चिश्ती को आपने उदयपुर की जिम्मेदारी दी। यह हम क्यों आपसे मांग कर रहे हैं बार-बार कि यह तो सारा ही बण्टाधार करने की व्यवस्था कर दी क्योंकि इतना नीचे तक जाने का न तो हमने सोचा, न हमारे दिमाग ने काम किया कि यह भी कुछ हो सकता है।

रीट जो 2012 में हुई थी, टेट हुई थी उस समय। उस समय यही मंत्री महोदय बोर्ड के चेयरमैन थे, जिनका नाम गर्ग साहब है। आपको सुनकर दु:ख होगा। हो सकता है, आप मेरे से नाराज हो सकते हैं, मेरे से किसी बात में यकीन नहीं हो, कोई बात नहीं लेकिन इनके समय में, इनका एक सहयोगी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

था नरेन्द्र तंवर। नरेन्द्र तंवर के घर पर छापा मारा। वहां पर 50 करोड़ की एफडी उसके घर पर मिली और 10 करोड़ से अधिक करेंसी, रुपया इसके घर में मिला और यह नाक का बाल था सुभाष गर्ग का। बाड़ खेत को यूं खा रही है। आप अक्लमंद कितने भी ज्यादा हो सकते हो। हो सकता है मैं सामान्य आदमी हूं और एक सामान्य अध्यापक रहा हूं। मेरे को कालेज का अनुभव नहीं है लेकिन मन में बहुत पीड़ा होती है। जीके माथुर को भी अभी इस परीक्षा में जिम्मेदारी देकर लगाया है। आपकी सारी उस गैंग को पकड़ा है जो इस प्रकार के धंधे करती हैं।

आपने देखा होगा कि वर्ष 2011 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रद्दी का घोटाला हुआ था, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें नरेन्द्र तंवर और जीके माथुर भी अभियुक्त और जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सुभाष गर्ग साहब जब बोर्ड के अध्यक्ष थे तब यह जो सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस है कलकत्ता की, इनका पेपर वहीं छपा था। टेट का पेपर भी कलकत्ता की उसी सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस में छपा था जहां पेपर सड़कों पर नीलामी के रूप में जब आया था तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे को बाद में जाकर ठण्डे बस्ते में बन्द कर दिया इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इसमें बड़े-बडे लोग हैं। जब तक इसकी जांच सही नहीं होगी तब तक उन बच्चों के मन को संतोष नहीं मिलेगा। हम यहां रफा-दफा कर सकते हैं लेकिन बच्चे के दर्द को वही समझेगा जिसके साथ यह पीड़ा हुई है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में सुभाष गर्ग साहब ने ही बिना किसी के पूछे दखलंदाजी के द्वारा सभी जगह राजीव गांधी स्टडी सर्किल से संबंधित लोग हैं, इनको आपने लगाया।

परीक्षा केन्द पर भी वहीं पर कार्यरत शिक्षकों को आब्जर्वर लगा दिया, परीक्षा जहां हो रही है, वहीं के अध्यापक की, वहीं की परीक्षा की जिम्मेदारी लगा दी। यह कैसे लगा दी। आपका आर्डर तो यह कहता है कि उस जिले का व्यक्ति भी उस परीक्षा केन्द्र पर नहीं लग सकता है। मैं बताता हूं, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में मधु सिंह और वेद प्रकाश को लगाया गया जो उसी कालेज में पढ़ाते हैं। राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में जलालुद्दीन साहब को लगाया। ये उसी कालेज में पढ़ाते हैं। कन्या महाविद्यालय, अजमेर और राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद आदि में आब्जर्वर वहीं की शिक्षकों को लगाया गया है जो आज दिन तक कभी नियम नहीं है लेकिन आपने उनको लगाया है। आप देखो कॉर्डिनेटर के स्वयं के सगे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रिश्तेदारों के कालेजों में परीक्षा केन्द्र बनवाया। इन सब लोगों ने अपने रिश्तेदारों के प्राइवेट कालेजों में परीक्षा केन्द्र बनाया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के सम्भाग समन्वयक भूगोल के सह-आचार्य सुनिता पचौरी को अजमेर जिले का कॉर्डिनेटर बनाया। उन्होंने स्वयं के घर की संस्था सुनिता आईटीआई को भी परीक्षा केन्द्र बनाया। यह किस आधार से बनाया? आपने सारे नियमों को ताक में रखकर जो हालात बनाये, आपने देखा होगा कि टोंक का एक शिक्षा निकेतन टीटी कालेज है, डाक्टर राकेश टांक को आब्जर्वर बनाया जबकि यह कालेज उनकी बेटी का है। निजी कालेजों के परीक्षा केन्द्रों पर राजकीय लोगों को आब्जर्वर लगाने की जगह प्राइवेट कालेजों के भी निजी व्यक्तियों को आब्जर्वर लगाया। निजी संस्था आर्यभट्ट कालेज, प्रमोद सिंह राठौड़, विशाल दत्त, कपिल चौहान, कुसुमलता गहलोत और भरत कुमार को क्रमश: सेन्ट जोसेफ स्कूल, सेन्ट रेशा स्कूल और बालाजी रायल टांक शिक्षा निकेतन द्वितीय, मदर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में आब्जर्वर लगाया। यह किस ताकत से लगाया, क्यों लगाया? वहीं निजी शिक्षण संस्था अग्रवाल कालेज, कुचामन के प्रफुल्ल नरूका को, सावन्त स्कूल संस्थान की शुभ्रा चतुर्वेदी को आपने उस स्कूल में ऑब्जर्वर लगाया है।

इसके अलावा निजी व्यक्तियों को आपने परीक्षा केन्द्र पर अनधिकृत रूप से जाने के लिये अधिकृत किया। घूम-घूमकर इन कालेजों में जाकर परीक्षा की व्यवस्था को इन्होंने देखा है। कोटा केन्द्र के राजीव स्टडी सर्कल के सहायक अनुज विलियम एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, लेकिन रीट परीक्षा के दौरान कई केन्द्रों पर उन्होंने चैकिंग के नाम पर अनधिकृत प्रवेश किया। यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। कई परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा-पत्र की सील खुली हुई मिली थी। कई परीक्षा केन्द्रों पर जो पेपरों के बण्डल गये थे, वह खुले हुए थे, लेकिन हिण्डौन के केन्द्राधीक्षक ने हिम्मत की और उन केन्द्राधीक्षक ने पेपर की खुली सील की शिकायत आपके बोर्ड को भेजी है, जो बोर्ड के पत्र पर लिखा हुआ है। इसका मतलब खुले में पेपर गये हैं। प्रश्नपत्र के निर्माण की प्रक्रिया में भी, यह तो ऐसा मामला है कि मैं सोचता हूं कि इसकी जितनी गहराई में जाओगे, लगेगा कि इस दलदल में राजस्थान फंस गया। आपने देखा होगा कि इस प्रश्न-पत्र की निर्माण प्रक्रिया पर भी बड़े सन्देह का प्रश्न खड़ा होता है। एक साथ सारे प्रश्न-पत्र बना दिये एक हजार क्वेश्चन के और उसी में से छांटकर पेपर बनेगा। यह आज दिन तक किसी परीक्षा में हुआ है क्या कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सारे प्रश्न कौनसे आएंगे इस परीक्षा में। एक हजार प्रश्न के प्रश्न पत्र बनाकर आपने एक मोटा-मोटा मॉडल दे दिया कि इन्हीं में से प्रश्न आएगा। इसीलिये राजेन्द्र जी, जो आप चूरू में कह रहे हो न, एक हजार में से आएंगे तो इसकी फीस लगेगी इतनी, पांच सौ में से आएंगे तो उसकी फीस लगेगी इतनी, सौ क्वेश्वन में से प्रश्न पत्र का जवाब देना है तो उसकी फीस लगेगी अलग। यह अलग-अलग फीस जगजाहिर है, बच्चों का जाकर भेज सकते हो। इस प्रकार का मैं सोचता हूं घपलेबाजी की भी हद हो गयी।

लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऐसे ब्लैक लिस्टेड केन्द्र को परीक्षा केन्द्र बनाया गया जिनको उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के कारण से ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ऐसे भी मामले सामने आये हैं, जिसमें गंगापुरसिटी, यह डी.एस. साइंस एकेडमिक परीक्षा केन्द्र की भूमिका संदिग्ध है। एकेडमिक का संचालक ज्ञानदेव स्कूल चलाता था। फर्जी दस्तावेज से स्कूल का नाम बदलकर गंगापुर में डी.एस. साइंस एकेडमिक खोली और शिकायत के बाद शासन सचिव, स्कूली शिक्षा को जांच में स्कूल फर्जी मिला। शिक्षा सचिव ने स्कूल की मान्यता रद्द की और आदेश दिये, उसके बाद भी उसको सेण्टर बनाया गया। 23 सितम्बर के दिन मंत्री महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसको सज़ा मिलेगी? बच्चों की और राजस्थान की जनता की मांग यह है कि इस प्रकार के अपराधियों को मत बचाओ। वह कौन होगा? वह मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। मैं नहीं कह सकता हूं इस बार प्रकरण में कौन-कौन कहां-कहां इन्वॉल्व हो गया हो, लेकिन उन लोगों को ढूंढना आपका और मेरा राजस्थान की इस जनता की अदालत में हमारी जिम्मेदारी जरूर है। इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते।

आपने देखा 23 सितम्बर, 2021 को रहस्यमय ढंग से मनोहरपुरा-दौसा हाईवे पर रीट प्रश्न-पत्र से भरा कंटेनर पलटा था। कंटेनर में पेपर जा रहे थे न। यह कब तो पलटा और वापस इन प्रश्न-पत्रों को उठाने के लिये कौन आया और कब आया? तब तक यह प्रश्न पत्र किसके जिम्मे पड़े थे? उसी गाड़ी में बंगाल के दो व्यक्ति, जिनके यहां पेपर छपाये थे सरस्वती प्रेस में, उसी प्रेस के दो लोग भी उसी में बैठे हुए थे। ड्राइवर तो मर जाता है पर उन दोनों के खरोच भी नहीं आती है और वह बंगाल चले जाते हैं, यह क्या तमाशा है? यह क्या तमाशा है भाई? यह क्या अजीब दृश्य उपस्थित हुआ है? इसके कारण से उसकी पत्नी ने जो धरना दिया है, वह बिलकुल ठीक दिया है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्योंकि उसकी डैथ के कुछ समय पहले ही उसकी टेलीफोन से बात हुई थी और उसके बाद उसकी डैथ का समाचार मिला। जिस प्रकार से उसकी मृत्यु को बताया गया है, वह संदेहपूर्ण है और मैं सोचता हूं कि कभी भी ऐसा होता है कि कंटेनर में सारे पेपर भेजे और रीट के भेजे, जहां लाखों बच्चों का सवाल है, उसकी सुरक्षा के लिये आगे-पीछे कोई गाड़ी भी नहीं लगायी, कोई पुलिस फोर्स भी उनको नहीं दी। भले ही रास्ते में कोई भी उनको लूट लो, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब यह व्यवस्था करना भी आपके जिम्मे नहीं था तो किसके जिम्मे था?

यह 08.02.2022 को टोंक जिले के थाना नगरकोट के अन्तर्गत जो लोकेश वाला मामला आया है, इसने भी आपको यह बता दिया। अब यह जो आपका स्ट्रांग रूम है, इस स्ट्रांग रूम की जो चाबी होती है, वह दो होती हैं, यह स्ट्रांग रूम कैसे खुला? किसने खोला, यह चाबी किसके पास थी, यह चाबी किस अधिकार से उसके पास थी? उसने यह पेपर 23 तारीख को चुराया और उसके बाद यह जो पांच करोड़ की बात है न, जिसमें एस.ओ.जी. ने एक करोड़ और बीस लाख रुपया बरामद कर लिया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इसका मतलब कोई आदमी पांच करोड़ में सौदा तय करता है तो क्या सब्जी बेचकर पैसा इकट्ठा करेगा? पांच लाख और दस लाख में बाजार में खड़ा होकर पेपर बिक रहा है, पेपर बिक रहा है, पेपर लो, पेपर लो। ऐसा करेगा क्या? यह सारे के सारे जितने भी कोचिंग सेण्टर हैं न, इन कोचिंग सेण्टर से सम्बन्ध होने के कारण इकट्ठा पैसा वहां से मिलने की गुंजाइश थी इसलिए यह सारा कांड हुआ। यह सारा इस कारण से हुआ। न आपका दोष है, न मेरा दोष है, पर जिसका दोष है, वह चाहे कोई भी आपके यहां बैठा हो या बाहर बैठा हो, उसको पकड़ना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर इससे मुकरते हो न तो हम राजस्थान के उन लाखों बच्चों को अपने यहां की उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकेंगे, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं।

अब आप देखो आंसर शीट, गोपनीय शाखा को पता होनी चाहिए। यह गंगापुर कैसे पहुंची पहले। यह कांड वहां से खुला। अगर यह आंसर शीट वहां नहीं मिलती आधे घण्टे पहले और वहां से यह शिकायत दर्ज नहीं होती तब तो यह जांच ही शुरू नहीं होती। यह जांच की गंगापुर के आंसर शीट सहित आधे घण्टे पहले उस सेण्टर पर उपलब्ध हो गयी, इसके कारण से यह शिकायत दर्ज हुई और उसके कारण से एस.ओ.जी. ने काम करना शुरू किया। मैं एस.ओ.जी.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को धन्यवाद देता हूं, मैंने पहले भी दिया है। ऐसा नहीं है एस.ओ.जी. ने मेहनत करके वहां तक पहुंचने का प्रयत्न किया। आज 39 लोगों को जेल में भेजा है, यह आज भी अन्दर है। एक और व्यक्ति कल पकड़ा गया, 38 लोग पहले थे। यह सारे के सारे लोग आज की तारीख में जो पकड़े गये हैं, इनको एस.ओ.जी. ने पकड़ा है, लेकिन यह तार वहां जा रहे हैं सुभाष गर्ग की तरफ, जिन्होंने ये कॉर्डिनेटर लगाये हैं। इसलिये चिल्ला रहे हैं, इसलिए बार-बार चिल्ला रहे हैं और आपका बोर्ड का अध्यक्ष, जब उसे वहां से निलम्बित किया जाता है तो कहता है कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यह जो पेपर जहां जयपुर में सुपुर्द किया था, यह बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं ने सुपुर्द किया इसलिए मेरा क्या दोष है? और उसके बाद वह गायब है। आज दिन तक उसका पता नहीं कि वह हैं कहां? उसको कहां भेज दिया। यह मन में सन्देह पैदा करता है, इस जांच को प्रभावित करने का।

इसी तरह से मनोहरपुरा वाली जो घटना है खुले नहीं आये तो हिण्डौन में खुले हुए की शिकायत क्यों हुई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 03.11.2021 को 36 दिन के भीतर ही लाखों बच्चों का रिजल्ट तैयार कर दिया। यह भी कमाल है कि नहीं है? कितना एफिशिएंट बोर्ड का अध्यक्ष है अपना, धन्यवाद देना चाहिए आपको, मुझको और सबको।

अब मैं आपसे इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि जो हुआ है उसे बोर्ड के रिजल्ट को आपने निरस्त कर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। लेकिन कम से कम उस शीट से उन कोचिंग संस्थाओं की शीट को तो मिलाओ कि किस कोचिंग संस्था से कितने बच्चे पास हुए, कितने नम्बरों से पास हुए, उनकी क्या स्थिति है? तब तो इसको समझने में आसानी रहेगी कि यह जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं, इनका कारण ही यह होता है कि वहां का पास परसेंटेज ज्यादा होने के कारण से हर मां-बाप अपना खेत बेचता है और अपने बच्चों को कोचिंग करने के लिये भेजता है। आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हो। हर आदमी यह चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं न कहीं काम में लग जाए और उसके लिये उसे जो कुछ भी करना पड़ता है, उसने किया और उसके बाद जिस प्रकार की स्थिति आपने लाकर खड़ी की है, मैं सोचता हूं एसओ.जी. के अन्दर रीट पेपर के मामले में अध्यक्ष डी.पी. जारोली बर्खास्त कर दिये गये। पेपर लीक काण्ड के राजनैतिक षड्यन्त्र का आरोप लगाया, जो मैंने आपसे अभी कहा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परीक्षा संकुल में स्ट्रांग रूम में लीक हुआ। यह 3-4 बिन्दु ऐसे मजबूत आये हैं जो इस एसओजी ने निकाल दिये। मैं एसओजी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि एसओजी उस स्ट्रांग रूम से पेपर के चोरी होने पर उस आदमी तक पहुंच गये। उस मीणा को गिरफ्तार कर लिया। मैं यही जानना चाहता हूं कि यह मीणा क्या चीज है जिसको आपने इस पेपर की रखवाली के लिये, उस प्राइवेट कालेज चलाने वाले को स्ट्रांग रुम की चाबी कैसे दी? यह हम समझना चाहते हैं। इस कारण से आपने किस प्रकार के हालात बनाकर के रखे हैं। आपने देखा होगा कि इस मामले में बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार किया, यह आपकी पार्टी का क्या पदाधिकारी है, थोड़ा बता देना। यह बत्तीलाल जी मीणा कौन हैं? इसी तरह से जे.ईएन. पृथ्वीराज मीणा को गिरफ्तार किया। उन्होंने कबूला कि 40 लाख रुपये मैंने पेपर बेचने के लिए इकट्ठे किये थे, फांसी खायी और मरा।

इसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने, पहले शिक्षा मंत्रीजी ने, कान्फ्रेंस में कहा था कि मेरे घर के 13 आदमी परीक्षा में बैठे थे और 13 ही फेल हो गये। नाम तो बता दो कि वह कौन-कौन बैठे हैं? आपके 3 बच्चे तो वैसे ही आर.ए.एस. बन गये थे, अब और बचा क्या? क्या दुर्भाग्य है?

मैं आज ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बाड़मेर निवासी ठेकेदार भजनलाल विश्नोई के पास 24 सितम्बर को रात को ही लीक प्रश्न-पत्र पहुंच गया था या नहीं? यह एसओजी की जांच में है। 24 तारीख की रात को ही पहुंच गया और 25 को परीक्षा थी। 5 करोड़ की बात एसओजी तक पहुंची कि 5 करोड़ स्ट्रांग रूम से पेपर निकालने का पैसा लिया था। अगर उसने 5 करोड़ में लिया है तो वह बेचकर के 5 करोड़ से ज्यादा ही वसूल करेगा। अब तक 42 अधिकारी कर्मियों को निलम्बित किया जा चुका है। इसका मतलब इसमें कुछ सच्चाई तो है ना? अगर उनको निलम्बित किया, उनको गिरफ्तार किया तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है। अगर है तो ठेठ वहां तक पहुंचो, इसका सरगना कौन है जिस सरगना ने इस तरह की गन्दी हरकत की है, शिक्षा के मन्दिर को अपवित्र किया है?

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता कनक्लूड करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि यह शिक्षक का धर्म नहीं हो सकता कि वह चन्द पैसों के टुकड़ों के पीछे उन बच्चों की जिन्दगी को दांव पर लगा दे। यह हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं है?

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत ही दुःख की बात है। आपने देखा होगा कि 1 करोड़ 16 लाख रुपये तो रिकवर भी हो गये। पैसा दिया तभी तो यह रिकवर हुए, अन्यथा कहां से हो सकते थे।

अलवर में रीट में 2-2 समन्वयक क्यों बनाये गये? मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा ब्लैक लिस्टेड प्राइवेट कालेज को भी रीट का केन्द्र क्यों बनाया? यह कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यह बीजेपी, कांग्रेस मत करो। उस बच्चे के साथ अन्याय हो जायेगा। जो भर्ती है उसको आगे बढ़ाओ ताकि उन बेरोजगार बच्चों को अपनी जिन्दगी में कहीं न कहीं काम मिले, लेकिन काम उनको मिले जो योग्य हों। यह चोर रास्ते से घुसने वाले लोगों ने राजस्थान को शर्मसार कर रखा है। मुझे भी इस बात का दुःख है कि कुछ लोग गलत सर्टिफिकेट बनाकर के डिग्रियां ले आते हैं। कुछ लोग गलत मार्कशीट लाकर के, मेरिट में आकर उसके योग्य बन जाते हैं। अगर पिछले 10 सालों का इनका रिकार्ड चैक करो जिनको आपने नौकरी पर लगाकर लगा रखा है, इनका पोस्टमार्टम करो तो मेरी गारंटी है कि 25 से 30 परसेंट लोग वे मिलेंगे जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी हथिया ली है। वह बच्चा रो रहा है जो अपनी गरीबी में, अपने मां-बाप का खेत बेचकर के, पढ़कर के नौकरी प्राप्त करना चाह रहा था। इसको आप अपना सवाल मत बनाओ, जिद का सवाल मत बनाओ। मुख्य मंत्रीजी को कहो। आप और हम जिन गांधीजी के विचारों को मानते हैं, इस प्रकार का घपला हो जाये और हम सब के सब मौन बैठकर के बीजेपी और कांग्रेस में बंटकर के उस बच्चे का अहित करें। यह क्या उस बच्चे के साथ न्याय होगा? इस कारण इन बड़े लोगों की जांच हो। आपकी जांच साल भर में होगी, कोई दिक्कत नहीं। आने दो न, जो भी लफड़े में आएगा, जायेगा अंदर। उसमें मैं भी आ जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा, कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन सच्चाई निकलकर के आनी चाहिये।

दूसरा, शिक्षा मंत्रीजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि परीक्षा को वैल प्रूफ बनाने के लिये आप यूपीएससी के परफेक्ट लोगों को, और भी जहां-जहां जो संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकर के चर्चा करो। इस परीक्षा को कैसे बिखेरा जाये, कैसे जिला लेवल पर इसकी प्रारम्भिक स्क्रूटनी की जाये। उसके बाद सलेक्टेड बच्चों का करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज की तारीख में तो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि हर बच्चे को आप कम्प्यूटर के सामने बैठा सकते हो। ऐसी क्या समस्या है? हर बच्चे को कम्प्यूटर के सामने बैठाकर के एक-एक प्रश्न देते जाओ, 10 सैकण्ड, 12 सैकण्ड जो भी देना हो वह दे दो। एक गायब हो तो दूसरा प्रश्न आये, तीसरा प्रश्न आये, चौथा प्रश्न आये। अगर हमारे मन में बेईमानी नहीं है तो इस तरह परीक्षा हो सकती है। हमने अपने और परायों को सलेक्ट करने का दिमाग बना रखा है तब तो असफल हैं। अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं आज भी हो सकती हैं।

मैं चाहता हूं कि यह परीक्षा जल्दी से जल्दी होकर के उन बेरोजगार बच्चों को अपनी जिन्दगी मिले। इसके लिये जो भी एक्सरसाइज करनी हो, तुरन्त करके, परीक्षा की डेट भी अनाउंस करो। इसको सीबीआई जांच के लिये इसलिए भेजो कि हमारी एसओजी की अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट से ऊपर के आदमी को बुलाकर टार्चर करना या उसे ऊंचा-नीचा करना उसके बस के बाहर है, लेकिन यह जो सीबीआई है, इसने मुझे भी ढाई साल तक रगड़ा है। बिना कसूर के रगड़ा है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको फेस किया।

श्री सभापति: इण्टरवीन नहीं करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसके बाद कोर्ट से जो भी मुझे राहत मिल सकती थी, मिली, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि चौटाला जी को, मुख्य मंत्री को अन्दर बन्द करने की ताकत अगर कोई रखता है तो यह सीबीआई रखती है। इसके कारण मांग करते हैं कि सीबीआई को दो। यह जांच अलग चलती रहेगी। परीक्षा अलग करते रहो ताकि दोनों के बीच में कोई टकराव हो, न इसको रोकने का मत है। मैं बार-बार आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि बड़ेबड़े दिग्गज, सिरफिरे लोग इसमें घुस गये हैं, उनको पकड़कर के जब तक नहीं रगड़ा जायेगा, तब तक बच्चों के मन में सन्तोष नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बी.डी. कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी विपक्ष के नेता, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य और खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रीट के बारे में अपने विचार रखे।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हालांकि मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो मामला सबज्युडिश है। हमारे नियमों में यह प्रावधान है, नियम 50 (2)(7), नियम 131 (2)(7), नियम 33 (2)(7), इन सभी में यह प्रावधान है कि जो मामला हाई कोर्ट में 28 तारीख को 2 रिटों के माध्यम से लम्बित है, उसके ऊपर यहां सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इनको चाहिए तो यह था कि यह सुझाव देते कि आईन्दा आप परीक्षा करें तो इसको इतना फूल प्रूफ सिस्टम से करें ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैंग किसी भी प्रकार से पेपर लीक नहीं कर सके। इनके सुझावों को मैं अभी भी आमन्त्रित करता हूं।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में, आरपीएससी के अध्यक्ष रहे कुमावत जी और डीओपी सैक्रेटरी हेमन्त गेरा, इन 3 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की है। वह 46 दिनों में यह सुझाव देगी कि किस प्रकार से रीट की परीक्षा को प्रभावी बनाया जाये। जो इससे सम्बन्धित कानून है, उस कानून में क्या-क्या प्रावधान किये जायें जिससे आइन्दा जब भी रीट की परीक्षा हो, उसमें किसी भी प्रकार का पेपर का लीकेज नहीं हो। मैं उम्मीद करता था कि इस संबंध में आप चाहें तो उस कमेटी को भी अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि आपके सुझावों को उसमें इनकारपोरेट किया जा सके।

जहां तक लोक सभा का प्रश्न है, लोक सभा में भी, राज्य सभा में भी यह प्रावधान है कि कोई भी मामला किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में कौल एण्ड शकधर में भी यह स्पष्ट लिखा है, पीठासीन अधिकारियों की एक समिति ने सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाये थे, उन सुझावों में खास तौर से जो मामले न्यायालय में लम्बित हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती।

सरकार ने रीट की परीक्षा के लिये निश्चित रूप से प्रबन्ध किये। माननीय विपक्ष के नेता बता रहे थे कि तारीखें बदलीं। आप जानते हैं कि राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड की बीमारी भयंकर रूप से चल रही थी। उसके कारण स्कूलें बंद, बाजार बंद, आपने देखा होगा कि जगह-जगह लॉकडाउन की स्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में कई बार नहीं चाहते हुए भी, आप इस बात से सहमत होंगे कि हमको परीक्षा की तिथियां बढ़ानी पड़ीं। यह कोई जान-बूझकर नहीं बढ़ायी गयीं। देश, काल और परिस्थितिवश हमें यह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तारीखें बढ़ानी पड़ीं, जिसका आप सबको भान है लेकिन जब परीक्षा करायी गयी, उसमें भी मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि राजस्थान की जनता ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की अपील पर सब जगह खाने-पीने की व्यवस्था की गयी। 13 करोड़ रुपये में बोर्ड ने मुफ्त बसों की व्यवस्था करके उनको वहां पहुंचाया। ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सब तरीके से माकूल व्यवस्था करके यह परीक्षा करायी गयी।

कुल मिलाकर इस परीक्षा में सबका, पक्ष और विपक्ष का सहयोग रहा है, इसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि नेशनल कौंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम पात्रता निर्धारित की गयी, जिसमें शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्य योग्यता रखी गयी। इसमें शिक्षक भर्ती 2012-13 में दो परीक्षाएं आरटीईटी एवं भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती थी। पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से जिलेवार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करवाया जाकर जिलेवार चयन एवं नियुक्तियां दिये जाने की कार्यवाही की गयी। प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांकों में आरटीईटी 2011-12 के प्राप्त अंकों का 20 प्रतिशत जोड़ते हुए जिलेवार मेरिट तैयार की जाती थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 15 अक्टूबर, 2015 के आधार पर अध्यापक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा का नाम बदलकर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रखने का निर्णय 2015 में लिया गया। वर्ष 2017 में अध्यापक लेवल वन की भर्ती हेतु रीट 2017 एवं रीट 2015 मेरिट बनायी जाकर भर्ती हेतु कार्यवाही की गयी। अध्यापक लेवल दो की भर्ती हेतु रीट 2015, 2017 तथा आरटीईटी 2011-12 की परीक्षाओं में से अधिकतम प्राप्तांक का 70 प्रतिशत एवं स्नातक डिग्री में प्राप्त कुल प्राप्तांक का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय वरीयता सूची से भर्ती की कार्यवाही की गयी। रीट परीक्षा 2021 दिनांक 26 सितम्बर, 2021 को आयोजित की गयी। लेवल टू, कक्षा 6 से 8 हेतु प्रातः 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लेवल वन, कक्षा 1 से 5 हेतु दोपहर 2.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक आयोजित की गयी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश का जैसा मैंने बताया कि उनके ठहरने की, खाने की और यातायात व्यवस्था के लिये अनुकूल व्यवस्था की गयी। दिनांक 07.02.2022 को जब समय-समय पर लोगों से यह मांग आयी कि इस परीक्षा में कुछ धांधली हुई है तो उन्होंने एसओजी के माध्यम से एक स्वतंत्र टीम गठित करके उसको जांच दी गयी। एसओजी ने बहुत त्वरित गति से कार्य किया। विपक्ष के नेता महोदय, आप इस बात से एग्री होंगे कि एसओजी की जो रिपोर्ट आयी थी, उसकी शुरू-शुरू में आपने तारीफ की थी कि एसओजी ने त्वरित कार्यवाही की। उस एसओजी की त्वरित कार्यवाही के कारण ही 38 आदमियों का जिक्र चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कि 38 आदमियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे आगे भी माननीय गृह मंत्रीजी बताएंगे। कुल मिलाकर लेवल वन की परीक्षा में कोई पेपर आउट नहीं हुआ। उस परीक्षा में जो 15 हजार परीक्षार्थी सफल हुए, उन लोगों को हम निश्चित रूप से मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करके नौकरी देंगे। केवल 16 हजार परीक्षार्थी जो एल टू की परीक्षा में बैठे थे उसमें पेपर कुछ लोगों के पास लीक हुआ, उसके कारण मन्त्रिमण्डल की 07.02.2022 को बैठक हुई, उसमें रीट के परीक्षा परिणाम के आधार पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान को एल वन की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए निर्णय किया और उसके बाद मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रीट की एल टू की परीक्षा को निरस्त किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि यूपी में टेट, सुपर टेट की परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण दिनांक 20.11.2021 को परीक्षा निरस्त की गयी। बाद में जनवरी 2022 में पुन: परीक्षा आयोजित की गयी। हरियाणा में 2015 में टेट की परीक्षा में पेपर आउट हुआ और परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई। केन्द्र सरकार की यूजीसी, नेट परीक्षा 2021 की हिन्दी की परीक्षा में मुख्य आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। दिनांक 28.12.2021 को पेपर लीक हुआ, केन्द्र सरकार की एसएसजी सीजीएल 2017, संयुक्त स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा, टियर प्रथम परीक्षा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा निरस्त नहीं करने के निर्देश दिये, लेकिन पेपर अगस्त 2017 में लीक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हो गया था। केन्द्र सरकार की अखिल भारतीय स्तर पर थल सेना के लिये सामान्य ड्यूटी सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 में हुई परीक्षा निरस्त की गयी। उत्तर प्रदेश, यूपी टेट जिसका मैंने बताया कि नवम्बर 2021 में हुई परीक्षा निरस्त की गयी। हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल की परीक्षा अगस्त, 2021 में हुई और उसमें मुख्य आरोपी हरियाणा आरएसी पांचवीं बटालियन के एक सहायक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखण्ड में भी और गुजरात में भी दिसम्बर, 2021 में गुजरात अधीनस्थ चयन बोर्ड की मुख्य क्लर्क की परीक्षा आयोजित की गयी, वह निरस्त की गयी। राजस्थान में आरएएस परीक्षा 2013 में पेपर लीक हुआ, दिनांक 11.07.2014 को परीक्षा निरस्त की गयी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018, दिनांक 11.03.2018 परीक्षा निरस्त की गयी। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013, 02.08.2015 दिनांक 03.06.2016 को परीक्षा निरस्त की गयी। क्लर्क ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 दिनांक 11.01.2014 को पेपर लीक हुआ और दिसम्बर 2015 में परीक्षा निरस्त की गयी। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 दिनांक 24.01.2016 को पेपर लीक हुआ और परीक्षा निरस्त की गयी। ये सब आपके कार्यकाल की परीक्षाएं हैं।

विपक्ष के नेता महोदय, एक गैंग बन गई है। आपको याद होगा, मैं 1997 से 2003 में शिक्षा मंत्री था, उस समय आठवीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था और माननीय विपक्ष के नेता महोदय, भैरोंसिंह जी शेखावत थे, उन्होंने मेरे इस्तीफे की मांग की, मैं मेरा इस्तीफा मुख्य मंत्रीजी को देकर आया था, फिर बाद में उन्होंने ही कहा कि इस कानून को कठोर बनाओ और आप बना सकते हो। मैंने इसी विधान सभा से उस समय जो सज़ा के प्रावधान थे, वो बढ़ाये थे और सख्त बनाये थे लेकिन उनको और सख्त बनाने की आवश्यकता है इसीलिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने विजय कुमारजी व्यास की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनायी है। यह समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और इतना कड़ा कानून बनाया जायेगा कि मैं समझता हूं कि आईन्दा किसी भी व्यक्ति या गैंग की हिम्मत या ताकत नहीं होगी कि वो पेपर लीक या आउट करे। यदि करेंगे तो निश्चित रूप से जेल की सींखचों में जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी कैबिनेट में 30 हजार पद बढ़ाकर राजस्थान के बेरोजगार लोगों को सौगात दी। माननीय सभापति महोदय, 30 पद बढ़ाये हैं, कुल मिलाकर 15 हजार तो एल वन में एक तरह से सलेक्ट हो जायेंगे बाकी जो 47,000 जो भी रहेंगे वो पद बहुत जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कानून को सख्त बनाकर, प्रक्रिया को कम्पलीट करके जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने प्राइवेट संस्था के लोगों को और इनको क्यों लगाया, इस पर विस्तार से हमारे गृह मंत्रीजी, श्री शान्ती कुमारजी धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्रीजी, जो गृह विभाग का काम भी देखते हैं, वो बताएंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आपके वक्त में भी प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को लगाया जाता था। डाक्टर मुरारी लाल गुप्ता, रामावतार जाट, निजी कालेज में कार्यरत एनएस नाथावतजी, इन सबको समन्वयक बनाया गया था। इस परीक्षा में भी करीब-करीब जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 39 जिला समन्वयक तो वही थे जो 2016 में बनाये गये थे। आपने बार-बार आरजीएससी के बारे में बताया। आरजीएससी का कोई एक व्यक्ति सदस्य है और उसने कोई कर दिया तो पूरी संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। जिसने किया है वह उसका फल भोगेगा।

(समय: 13.00 बजे)

एसओजी बिलकुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एसओजी ने जो अब तक जांच की है, वह बहुत सही कदमों पर चल रही है और निश्चित रूप से, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो उसकी गिरफ्त में आयेगा, उसे सज़ा देगी। हमारे मुख्य मंत्रीजी इस मामले में बहुत सख्त हैं, वे किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो-जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भ्रान्ति नहीं रहनी चाहिए।

आपने एक प्रश्न उठाया कि जयपुर में ही रीट के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में क्यों रखे गये। जहां-जहां ट्रेजरी में जगह नहीं थी, वहां जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई थी, उसके अनुमोदन के उपरान्त ही श्री महेश सीनियर सैकंडरी स्कूल (जोधपुर), सीकर कल्याण सैकंडरी स्कूल (सीकर), धौलपुर राजकीय पॉलीटेक्नीक कालेज (धौलपुर), शिक्षा संकुल (जयपुर), जे.पी. जानू सीनियर सैकंडरी स्कूल (झुंझुनू) में जिला स्तरीय समिति जो बनी हुई थी, उसके अनुमोदन के बाद इन जगहों पर पेपर रखे गये थे।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 26 लाख अभ्यर्थी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

परीक्षा में सम्मिलित हुए। आप अपनी बात में सुधार कर लें, 20 लाख 52 हजार 733 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आपने अब तक 67 हजार 249 लोगों को रोजगार दिया है। माननीय सदस्य, आप करेक्ट कर लें, लगभग एक लाख लोगों को अब तक हम तीन वर्षों में रोजगार दे चुके हैं और एक लाख लोगों को अगले दो वर्षों में रोजगार देने की हमारी पूरी तैयारी है, बशर्ते कहीं कोर्ट का अथवा कहीं किसी का स्टे वगैरह नहीं हो। सभापति महोदय, लगभग एक लाख लोगों को रोजगार देने की हमारी तैयारी है।

खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठायीं, कुछ बातें तो रेलेवेंट ही नहीं थीं। अब यहां रीट पर चर्चा हो रही है और ये विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का कोई मकसद अभी है ही नहीं। आपने जहां तक 30 हजार पद बढ़ाने की बात की, निश्चित रूप से, आपका कम से कम यह तो है कि आप कई बार ''सत्यम परम धीमहि'' में विश्वास रखते हैं, सत्य का आप कई बार समर्थन भी करते हैं। 30 हजार पद बढ़ाकर हमने यह बता दिया है कि अभी तो 21 हजार लोगों की परीक्षा हुई थी, अब लगभग 46 हजार 500 लोगों की परीक्षा होगी और उसमें राजस्थान के बेरोजगार लोगों को काम दिया जायेगा, रोजगार दिया जायेगा और अध्यापकों की रिक्तियों को भरा जायेगा।

आपने और जो कुछ मुद्दे रखे थे, मैं समझता हूं कि हमारे शान्ती धारीवाल जी से सम्बन्धित हैं, उनका जवाब वे देंगे, लेकिन एक बात मैं आज सदन को विश्वास में रखकर कहना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से और हमारा जो पूरा मंत्रिमण्डल है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में ऐसा कानून लायेगा, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके और आईन्दा जो भी परीक्षा होगी, उसे हम फुलप्रूफ सिस्टम से कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर कहना चाहता हूं, यह जो 12 सितम्बर का आपके बोर्ड के अध्यक्ष और सैक्रेटरी ने आदेश जारी किया कि पेपर आप कहां रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे, पुलिस की कस्टडी होगी, जयपुर में क्या विशेषता थी कि यहां न पुलिस को इन्वॉल्व किया, न अधिकारियों को इन्वॉल्व किया और घर ही घर के लोगों को चाबी पकड़ा दी, यह बताएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने बताया, जहां ट्रेजरी में जगह नहीं थी, पांच स्थानों पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद स्थान की कमी के कारण...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये चार लोग लगाने वाला आदमी कौन है, वह आर्डर पढ़ दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): देखिये, जिला परीक्षा संचालन समिति में कलेक्टर, एडीएम, एसपी, बोर्ड का प्रतिनिधि, डीईओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि थे। इनके अनुमोदन के बाद...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माफ करें, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं...

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, Let me complete first.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बात को घुमाइये मत। मैं यह कह रहा हूं, केवल इन चार को लगाने का आदेश इस सदन के पटल पर रख दें तो कम से कम सच्चाई सामने आ जाये। इन चार को लगाने वाला आदेश किसने दिया?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, जहां ट्रेजरी में जगह नहीं थी, वहां जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, जयपुर में शिक्षा संकुल, जोधपुर में, धौलपुर में पांच स्थानों के नाम बताये, वहां पेपर स्थान की कमी के कारण रखे गये थे और वहां पुलिस की व्यवस्था थी, कम से कम तीन आदमी वहां ड्यूटी पर थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यहां पुलिस क्यों नहीं थी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): यहां पर भी थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं थी। आप क्यों असत्य बोल रहे हैं? यहां नहीं थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): धारीवाल जी बता देंगे पूरी डिटेल।

श्री सभापति: धारीवाल जी का भी रिप्लाई आ जाये, आपने भी अपनी बात कही। प्लीज विराजिये। श्री धारीवाल जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मुद्दा यह है कि सीबीआई को जांच दी जाये

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

या न दी जाये। अभी फिलहाल एसओजी की जांच चल रही है। मुझे आप यह बता दें कि आप इन्वेस्टिगेशन क्यों चेंज करवाना चाहते हैं? क्या एसओजी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है? यह आपने कहीं पर भी नहीं बताया। कहीं पर भी आपने यह बात नहीं बतायी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने तर्कों के आधार पर बताया। जांच कहां से कहां जा रही है, यह बताया हमने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। प्लीज सहयोग करें। आसन की व्यवस्था थी कि "ना पक्ष" की तरफ से ये लोग बोलेंगे और इधर से ये लोग बोलेंगे। आप लोग जब बोले, किसी ने इंटरवीन नहीं किया। अब इधर से जो भी आदमी बात कहना चाह रहे हैं, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। कृपया सहयोग करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो कुछ बोला, हमने बड़े ध्यान से सुना। मेहरबानी करके इतना माद्दा रखें कि मेरी भी बात आप आराम से सुन लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये तो अभी भागेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ी गम्भीरता रखें। बीच में इंटरवीन न करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं, जिनके आधार पर जांच की जा सकती है? आप नाम ले रहे हैं फलाने का, इसका-उसका, ये-वो, है क्या सबूत आपके पास कोई? सबूत हो तो एसओजी को दे दीजिये। अगर एसओजी जांच न करे, फिर आप जांच बदलने की मांग करते हैं तो बिलकुल वाजिब है। आप राजीव गांधी सर्किल के बाबत बात कर रहे हैं। 17 साल से यह संस्था काम कर रही है। एक बार भी आप बता दें कि एक आदमी भी कभी किसी क्राइम में पकड़ा गया हो इसका, एक भी बार बता दें।

आपने बताया कि प्रदीप पाराशर को किसी मामले में सज़ा हो गयी। किस मामले में सज़ा हो गयी, यह बता दें। बताएं आप। जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं कि साहब, प्रदीप पाराशर को तो पहले सज़ा हो चुकी। कुल-मिलाकर मैं जो समझा हूं, सीबीआई से जांच कराने का मुख्य उद्देश्य आपका यह है कि वह आये, यहां के स्ट्रांग रूम्स सील कर दे, यहां के दफ्तर सील कर दे, यहां के बोर्ड के दफ्तर को सील कर दे और फिर दिल्ली बैठ जाये। क्यों? वह कैसे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करेगी? वह ऐसे कि सब लोग जानते हैं कि सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, "सीबीआई तो पिंजरे का तोता है"। आप इसलिए सीबीआई को जांच दिलवाना चाहते हैं ताकि जांच आपके हाथ में आ जाये।

एसओजी के खिलाफ आरोप आपने एक भी नहीं लगाया। न ही आपने यह बताया कि एसओजी की जांच में क्या खामी रह गयी, बल्कि तारीफ की है आपने, वह भी एक बार नहीं, दो-दो बार। आज आप उसकी जांच बदलवाना चाहते हैं, उसे बेइज्जत करना चाहते हैं। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एसओजी का सारा स्ट्रेस आज कहीं हैं तो रीट की जांच पर है। पूरी ताकत लगा रखी है एसओजी ने और वह जल्दी ही खुलासा कर देगी। उसने मुख्य आरोपियों को पकड़ भी लिया। सीबीआई तो भण्डारा है, सीबीआई को जांच देने का मतलब तो गड्ढे में जांच को फेंकना है।

आपके समय की बात बता रहा हूं। आज तो आप कहते हो कि सीबीआई को दे दो। आपके समय, बीजेपी के समय पेपर लीक के कुल 25 मुकदमे दर्ज हुए। वे जांचें आपने एसओजी को क्यों दी? अगर एसओजी बेईमान संस्था है, उसकी कार्यकुशलता ठीक नहीं है तो एसओजी को आपने जांच क्यों दी, सीबीआई को देते? आरएएस का एग्जाम 2014, आरजेएस का एग्जाम 2014, एलडीसी का एग्जाम 2014, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम के 7 मुकदमे 2017, जेल प्रहरी परीक्षा के दो मुकदमे 2018, ये सारे के सारे आपने एसओजी को दिये। क्यों दिये एसओजी को अगर बेकार संस्था थी? रीट के 2016 और 2018 में जो दो पेपर लीक हुए उसको एसओजी को न देकर आपने साधारण पुलिस से जांच करवाना उचित समझा। एसओजी तक को नहीं दिये। 2016 और 2018 में रीट के दो पेपर आउट हुए और जांच कौन कर रहा है? कोतवाल घासीलाल।

इसके अलावा भी आप देखिए कि आपकी कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में हुई, सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में हुई, जेल प्रहरी परीक्षा के 5 मुकदमे 2016 में, आईटीआई सैकण्ड सेमेस्टर परीक्षा 2017 में, एसएससी क्लर्क एग्जामिनेशन हुआ 2018 में, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई 2018 में, इनकी भी जांच आपने साधारण पुलिस को दे दी। चौमूं का कोतवाल जांच कर रहा है।

अभी कल्ला साहब ने आपको बता ही दिया। केन्द्रीय सरकार तक ने,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उनके तीन-तीन बार पेपर आउट हुए पर सिर्फ एक बार जांच सीबीआई को दी जिसका आज तक सीबीआई के द्वारा फैसला नहीं हुआ, आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। उन दो मामलों में क्यों नहीं दी? आपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड वगैरह का सब कुछ बता दिया। मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य के बड़े भाई जो आज सांसद हैं, हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने लोक सभा में एक सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने दिया जो कि उस वक्त प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे। उन्होंने पूछा कि पिछले दस वर्षों में दिल्ली पुलिस (विशेष), मतलब वही सीबीआई का, सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश कितने मुकदमों में की गयी। कुल मिलाकर उन्होंने जवाब दिया कि 12 मुकदमे पिछले दस वर्षों में सीबीआई को भेजे गये। 12 में हालत क्या रही कि 10 तो उन्होंने पंजीकृत, रजिस्टर किये और कुल मिलाकर 37 मुकदमे दस में दायर किये अलग-अलग आदमियों पर अलग-अलग। जिसकी डिटेल उन्होंने यह बतायी कि जांच चरण में, इन्वेस्टिगेशन में तो सिर्फ दो हैं और सात बन्द कर दिये। दस में से सात तो सीबीआई ने बन्द ही कर दिये और विचारण चरण, मतलब ट्रायल स्टेज पर 27 हैं और एक दोषमुक्त कर दिया। कुल मिलाकर दस साल में 12 मुकदमे दिये जिनमें सिर्फ दस को रजिस्टर किया, सात में तो क्लोजर ही दे दिया। अब क्या विश्वास करें इस पर?

इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेंगे, यहां पर शायद 24-25 लाख बैठे थे। कितने बैठे थे? बीस लाख बावन हजार, अच्छा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले मथुरा, गाजियाबाद और बुलन्दशहर के कई वाट्सएप ग्रुपों पर पेपर वायरल हो गया। परीक्षा 28 नवम्बर, 2021 को होनी थी और उसी दिन पेपर आउट हो गया। इसकी जांच, अपोजिशन चिल्लाता रहा, लाल टोपी वाला चिल्लाता रहा, कांग्रेस चिल्लाती रही, सब चिल्लाते रहे कि सीबीआई को दे दो, सीबीआई को मत दो, दूसरी संस्था को दो, लेकिन दूसरी संस्था को भी नहीं दिया। दिया किसको? एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स। एसआईटी नहीं बनायी, उसको दे दिया। 21 लाख लोगों ने फार्म भरे थे उसमें और यहां 24-25 लाख का मामला है, बराबर-बराबर का मामला था। आप जो बार-बार बेरोजगारों का कह रहे थे तो यह राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भी शायद आपके दिल में दर्द होगा।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट अक्सर बड़े मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है। मांग की जाती है कि सीबीआई को दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, सीबीआई को नहीं देंगे, एसआईटी गठित करेंगे। चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, कोई सा भी मामला हो, वे सीबीआई को नहीं देते हैं, एसआईटी गठित करते हैं। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में वे पूरा न्याय नहीं मानते। वे साफ-साफ कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा जांच में हमेशा कमी छोड़ दी जाती है इसीलिए एसआईटी का गठन कई मामलों में राज्य सरकार भी करती है, केन्द्र सरकार भी करती है। सुप्रीम कोर्ट का, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विशेष जांच दल, आमतौर पर एक अवकाश प्राप्त जज नियुक्त किया जाता है जो इस विशेष जांच की अगुआई करता है। वह अकेले भी हो सकता है और उसके साथ कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी हो सकती है। इसे ऐसी विशेष एजेंसी माना जाता है जो किसी के दबाव में आये बगैर हाई प्रोफाइल मामलों और लोगों के खिलाफ जांच का काम कर सकती है। ये विशेष अधिकार सम्पन्न होते हैं, उनकी जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। ये दल जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ जांच के मामलों में सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करते हैं।

आप यह भी देखिये कि केन्द्र में पूर्व गृह मंत्री थे स्वामी चिन्मयानन्द, केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने एसआईटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यू.पी. सरकार को कि एसआईटी गठित करो तो एसआईटी गठित करनी पड़ी किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। 1984 के दंगों की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई से नहीं कराएंगे हम, एसआईटी से कराएंगे। यह तो रेपुटेशन है सीबीआई की और आप सीबीआई के पीछे पड़े हुए हो कि सीबीआई को दे दो क्योंकि आपके मन में कुछ और ही बात है, और ही प्लानिंग है जो मैं आपको बता चुका हूं। बहुत मामला चला था काला धन, काला धन और काला धन जांच के लिए भी एसआईटी का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गुजरात के दंगों में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही एसआईटी का गठन हुआ।

अब मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप भी मंत्री थे, भैरोंसिंह जी के टाइम पर शिक्षा मंत्री थे शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है और माननीय उप नेता महोदय उस वक्त हैल्थ मिनिस्टर थे और जे.सी. बोस छात्रावास में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बलात्कार का मामला हुआ था। हम कांग्रेस के सदस्यों ने जोस्शोर से इस मामले को उठाया था और बहुत गम्भीरता के साथ इस मामले पर सदन में काफी चर्चा भी हुई थी। लेकिन एक चर्चा चली कि रोहिताश्व जी, जो उस वक्त आपके साथ ही मंत्रिमण्डल के सदस्य थे, के लड़के के कारण अनुसन्धान नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके लड़के का नाम उसमें आ गया, चर्चा में है।

जब इस प्रकार से चर्चा चलाकर उस मामले को हाई कोर्ट ने सीबीआई में दे दिया और आज मैं कहता हूं कि वह मामला, ये भैरोंसिंह जी कह रहे हैं, आदरणीय भैरोंसिंह जी के वर्ड बोल रहा हूं मैं, 'आज मैं कहता हूं कि अगर वह मामला सीबीआई में नहीं जाता तो वह जो शिवानी का काण्ड हुआ था, इस काण्ड को लेकर इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकती थी, लेकिन वह नहीं कर पायी, इसलिए नहीं कर पायी, इसलिए नहीं कर पायी कि उस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है'। जब भैरोंसिंह जी जवाब दे रहे थे, उसके पहले हमारे नेता परसराम जी मदेरणा ने यह सवाल उठाया था और सीबीआई की बात कही थी कि सीबीआई, वे बोलते हैं आगे, परसराम जी ने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीबीआई में.. यह भैरोंसिंह जी कह रहे हैं, परसराम जी से, मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सीबीआई में कोई विलायत से आदमी नहीं आये हैं, कोई विलायत से उतरकर यहां पर आ गये हों सीबीआई में, कोई आसमान से आये हों, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान पुलिस के लोग ही सीबीआई में हैं, अन्य राज्यों के लोग भी सीबीआई में हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका और स्तर क्या है, उस शिवानी काण्ड में आज तक चालान नहीं हुआ। आज तक चालान नहीं हुआ। सीबीआई में मामला चला गया तो हमको निश्चित रूप से नुकसान होगा। ये आदरणीय भैरोंसिंह जी का कहा हुआ है, आपको तारीख भी बता देता हूं, 9 सितम्बर, 1997, राजस्थान विधान सभा पेज नम्बर 462-463।

अब आपको सीबीआई के बाबत आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने जो कहा, उसकी लाइन सुनाता हूं। Congress has misused and politicized all constitutional bodies; these elections fought by CBI and the only candidate congress. कांग्रेस तो कैंडिडेट खड़ा करती है, चुनाव का प्रचार तो सीबीआई करती है, उनका कहना यह था। दूसरी बार उन्होंने कहा CBI has become Congress Bureau of Investigation. Nation has no faith in

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

it. ये प्रधान मंत्रीजी की ओपिनियन बताई है मैंने आपको, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है और चुनाव तो सीबीआई लड़ती है, कांग्रेस तो सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करती है। ये देखिए आप प्रधान मंत्रीजी का फोटो है, आप जो बता रहे हो। वह कागज मुझे दे दो, मेरा कागज ले लो, ये आपके पास आ जायेगा, आप अपने ड्राइंग रूम में लगा देना इसको।

अब सवाल यह आता है कि बार-बार आपने यह कहा कि एसओजी ठीक है, कर रही है काम, लेकिन ये उन लोगों तक नहीं पहुंच सकती, इसकी औकात इतनी नहीं है कि यह ऊपर तक पहुंच जाए। मेरा निवेदन यह है कि ये एसओजी ही है, जिसने एक ही नहीं, मुख्य मंत्री, राजस्थान, विधायक महेश जोशी, विधायक रमेश चन्द मीना, विधायक आलोक बेनीवाल, विधायक ओम प्रकाश हुड़ला, विधायक श्री कान्ति प्रसाद, विधायक खुशवीरसिंह, विधायक बलजीत यादव, विधायक बाबूलाल नागर, विधायक महादेव सिंह खण्डेला, विधायक रमीला खड़िया, विधायक राजकुमार गौड़, विधायक रामकेश मीना, विधायक लक्ष्मण जी मीणा, विधायक संयम जी लोढ़ा, विधायक सुरेश जी टाक और विधायक महेन्द्रजीत सिंह जी मालवीया इनको नोटिस दिये हैं, किसी की हिम्मत थी क्या जो मुख्य मंत्रीजी को नोटिस दे दे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो नोटिस विथ-ड्रॉ कैसे किये? आप मिसलीड कर रहे हो इसको, मिसलीड कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो उसको।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, आसन सक्षम है। विराजिए आप लोग, अपने आप व्यवस्था करेगा। माननीय श्री धारीवाल जी। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो बार-बार में?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कुल मिलाकर के 18 आदमियों को मुख्य मंत्री समेत, किसी की ताकत है, एसओजी ने नोटिस-चार्जशीट दी। हबीब खां के खिलाफ चार्जशीज पेश हुई, हबीब खां गौरान, विधायक भंवर लाल जी और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया। इसमें एतराज हो सकता है आपको, लेकिन किया। राजीव रंजन, आईएएस को मुलजिम माना, हाई कोर्ट से जमानत हो गई, वह अलग बात है, लेकिन उनको उस तक तो मुलजिम माना और तफ्तीश जारी है, बड़े-बड़े काम किये हैं, एसओजी ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये आपकी सरकार को बचाने का काम कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फिर वही बात, बरदाश्त तो होती नहीं है।

श्री सभापति: बीच में नहीं, बीच में नहीं, माननीय उप नेता महोदय, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, हम भी एजुकेटेड होते हैं आपसे, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मिसलीड कर रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, सुनिये आप, कृपया धैर्य से सुनिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध...

श्री सभापति: पर्यटकों की तरह से आते हो और आकर के डिस्टर्ब करने लग जाते हो। सदन में बैठते नहीं, पर्यटक की तरह से आते हैं और जब सदन चल रहा होता है तो बीच-बीच में अपनी बात कहते हैं। माननीय श्री धारीवाल जी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें, वे सक्षम हैं। धारीवाल जी को आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री धारीवाल जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध समाधि लिये बैठे थे और रोज एक व्यक्ति आता था और उनको बुरी-बुरी अश्लील गालियां देकर जाता था तो महात्मा बुद्ध के जो भक्त थे, उन्होंने एक रोज उनसे पूछा कि भगवान, ये रोज आता है और इस तरह से गालियां देकर जाता है, हमें बरदाश्त नहीं होता तो महात्मा बुद्ध का जवाब यह था कि वह बोलता है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता तो स्वीकार न करने से बात वहां की वहां पहुंच जाती है।

रीट का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के द्वारा कराया जाता है, यह तो आप सभी जानते हैं। एक प्रश्न उठाया गया, बार-बार उठाया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को पहली बार, पहली बार बोर्ड ने जिला समन्वयक, कॉर्डिनेटर कहते हैं न, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर और सह-समन्वयक लगाया गया, यह पूर्णतया असत्य है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप आज इस बात को साबित कर दो कि पहली बार ऐसा हुआ है।

बीजेपी के शासन में 2016, 2018 में रीट की परीक्षा हुई, तब भी सेवानिवृत्त शिक्षक, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे तथा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बीजेपी और आरएसएस के अनुषंगी संगठनों के आफिस बियरर सदस्य रहे, उनको परीक्षा में लगाया गया था। उनको परीक्षा में लगाया गया था 2016 और 2018 में। सेवानिवृत्त डा. मुरारी लाल गुप्ता, 2014 में सेवानिवृत्त हो गये, उनको 2016 और 2018 में डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, नीमकाथाना, सीकर में लगाया गया। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश पदाधिकारी भी रहे हैं।

दूसरा और सुनिए आप। डा. रामअवतार जाट, सेवानिवृत्ति वर्ष 2016, रीट 2018 में श्रीमाधोपुर, सीकर में डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर बनाये गये। तीसरा, निजी कालेज में कार्यरत, प्राइवेट कालेज में जैसे रामदयाल था न, ये रामदयाल का दूसरा भाई, निजी कालेज में कार्यरत डा. एस.एन. नाथावत, जो अभी प्राचार्य के पद पर भगवान दास तोदी कालेज में कार्यरत हैं, को रीट परीक्षा 2016, 2018 में जिला समन्वयक, लक्ष्मणगढ़, सीकर में बनाया गया था। तथ्य जो सदन में बोलो वह तो सत्य बोलो। अगर हमारी गलती है तो हम मानेंगे। हमने पाराशर जैसे आदमियों को लगा दिया जिससे आज हमें नीचा देखना पड़ रहा है। हम मानते हैं कि यह गलती हुई है लेकिन खुद भी तो स्वीकार करो। जब भी बोर्ड कोई परीक्षा कराता है, आप कहते हैं न कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो यह अब क्यों कर दिया? जब भी बोर्ड कोई परीक्षा कराता है तो पहले बोर्ड पहले वाले बोर्ड के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गई थी उसको मानता है। वह क्या परम्परा थी उसी तरीके से वह कार्य करने की प्रक्रिया को तय करता है। बोर्ड द्वारा सरकारी कालेज में सेवानिवृत्त प्रदीप पाराशर को जिला समन्वयक और निजी कालेज के शिक्षक ध्यान चन्द गोठवाल को सह समन्वयक लगाया गया था। यह हो सकता है मैंने पहले भी स्वीकार किया है, यह हो सकता है प्रदीप पाराशर संगठन का सदस्य है, किन्तु एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे संगठन को बदनाम नहीं कर सकते, एक व्यक्ति की वजह से। राजीव गांधी सर्किल क्या-क्या काम किये हैं उसने, कितनी सेमिनार, कितनी वेबिनार की है, किस तरीके के काम जो किये हैं, वह इतिहास में लिखने के काबिल हैं। बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। बीजेपी के नेताओं का यह आरोप कि आरजीएस के लोगों को रीट ड्यूटी में क्यों लगाया गया, इसके बारे में बता चुका हूं। जैसा अभी कल्ला साहब ने बताया था कि 39 जिला समन्वयक वो ही थे जिनको कि 2016 और 2018 में लगाया गया और 22 जो अतिरिक्त लगाये गये वो भी आरएसएस संगठन से जुड़े हुए और एबीवीपी से जुड़े हुए सदस्य थे। प्रश्न यह उठता है कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जयपुर में रीट के प्रश्न का, आपने बार-बार यह सवाल उठाया कि जयपुर में क्यों रखा गया? जयपुर में रीट के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में ही क्यों रखे गये जबकि अन्य जगह कोषागार और उप कोषागार में रखे गये? यह सही नहीं है। पहले भी और अब भी रीट के प्रश्न अन्य जगह पर रखे गये थे। प्रश्न पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण उप कोषागार में जगह नहीं थी, जैसा आपको बता दिया कि 5 स्थानों पर इस प्रकार से हुए। पुलिस गार्ड की व्यवस्था की गयी थी।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी संस्था को आप एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पर पूरी संस्था को बदनाम करना चाहो, तब तो फिर आपकी आरएसएस तो बदनाम हो चुकी। निम्बाराम, क्या हुआ था, 259 करोड़ रुपये का पेमेन्ट बीवीजी को दिलाने के लिए बीस करोड़ रुपये क्या नहीं मांगे गये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, तथ्यों से परे जाकर जिस प्रकार की बचकानी बात कर रहे हैं। ये यही चाहते हैं कि ऐसी बात करें कि हम विरोध करें। ये यही चाहते हैं।

श्री सभापति: बीच में अलाउ नहीं होगा। विराजिए आप। आसन पैरों पर है, विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी मामला जांच में है वह न्यायालय में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए आप। विराजिए आसन को अपनी व्यवस्था देने दीजिये। प्लीज सहयोग करिये। दोनों पक्षों की तरफ के आप लोगों ने नाम लिये। आपने भी शुरुआत की नाम ले-लेकर आपने शुरुआत की। मैंने आपको नहीं टोका क्योंकि यह आसन की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजेन्द्र जी राठौड़, सतीश जी पूनियां और बेनीवाल साहब बोलेंगे। आपको मैंने बीच में इंटरवीन किया? आप लोगों ने सबके नाम लिये। सबके नाम लिये आपने जबकि आप भी इस परम्परा को जानते हैं आपसे ज्यादा और कौन जानेगा, जो व्यक्ति सदन में अपना रिप्लाई नहीं दे सकता, आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। मेरे से ज्यादा कौन जानेगा आपको इस बात के लिए, लेकिन आप लोगों ने नाम लिए, बाकायदा नाम लिए, यह चोरी में पकड़ा जाता, यह उसमें पकड़ा जाता, यह उसके टाइम में हुए।

(श्री सभापति)

मैं व्यवस्था देता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं इस पर निर्णय करेंगे कि जो-जो भी नाम इधर-उधर से लिए हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था करेंगे और जो नाम आपने लिए, एक भी पक्ष इधर से नहीं बोला। अब यह जो भी कुछ कह रहे हैं आप शान्तिपूर्वक सुनें। बड़ी मुश्किल से आज सदन व्यवस्थित हुआ है। सदन में सार्थक चर्चा हो रही है। सदन में चर्चा होने दें, तथ्य सामने आने दें। आज कोई अन्तिम बात तो है नहीं कि आप बात कह करके यहां से चले जाएंगे। यह सदन चलेगा, आपस में चर्चा होगी, संवाद होगा तभी कोई सार्थक परिणाम निकलेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से व्यवस्था थी दो घण्टे की। दो घण्टे से ऊपर हो गए क्योंकि बीच में कुछ व्यवधान रहे। अब कृपया आप व्यवस्थित सदन चलने दें।

माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं। यह जो जयपुर में शिक्षा संकुल में जिन चार लोगों को आपने लगाया, उनको लगाने का आदेश निकालने वाला व्यक्ति कौन था? सारी 32 जगहों पर तो आपने प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को भी उनकी रक्षा के लिए लगाया था। क्या उस स्थान पर भी पुलिस की रक्षा में कोई आदमी वहां तैनात था? क्या वहां कोई आर.ए.एस., आई.ए.एस. या किसी व्यक्ति को भी उसके साथ लगाया हुआ था? क्या स्ट्रांग रूम की चाबी इन दोनों व्यक्तियों के पास थी और इन्होंने इसको खोला? मुख्य बात जो आ रही है वह इस बात पर आ रही है इस पर कोई जवाब नहीं है। एसओजी मुझे मुलजिम बनाये या आपको, अगर मैं कोई एफ.आई.आर. लिखाऊं कि आपने यह किया तो एसओजी दर्ज नहीं करेगी क्या? दर्ज करने के बाद वह एसओजी जांच में कहां तक पहुंचती है वह एसओजी का काम है। यह काम तो दर्ज कराने वाले व्यक्ति का है जो शिकायत दर्ज करायी वह उसने लिख लिया, उसमें क्या दिक्कत थी। मैं सोचता हूं कि ये इधर-उधर की बहानेबाजी नहीं, सीधा आओ, इस सेंटर पर इन चार लोगों के हाथ में यह सारा काम किस आर्डर से, किस अधिकारी ने दिया और इसमें बोर्ड के अध्यक्ष का क्या रोल है? यह बताओ।

श्री सभापति: श्री धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात चल रही थी निम्बाराम की। निम्बाराम जी को बुलाया

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

एसीबी ने, नहीं गये। कोर्ट से आर्डर करवाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जाओ। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये रीट पर बोल रहे हैं? सभापति महोदय, रीट पर बोल रहे हैं? कुछ तो करो साहब, डिरेल्ड होकर कहां जा रहे हैं ये।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। आपने बात सीबीआई की खड़ी की, सीबीआई की जो परिस्थितियां हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कृपया शान्तिपूर्वक सुनें। बार-बार आग्रह कर रहा हूं। कृपया शान्तिपूर्वक सुनें। मुझे चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। श्री धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब ये एक हरीश लड़का है, आरएएस का इम्तिहान देना चाहता था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकंड मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैंने सवाल अभी इतना ही पूछा है कि आपने..

श्री सभापति: बीच में नहीं। कटारिया साहब, प्लीज। सहयोग करें। ऐसे फिर क्वेश्चन आंसर होगा तो फिर इसका निदान ही नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने पूछा उसका भी जवाब दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): केवल मैंने इतना ही प्रश्न पूछा, उसका भी जवाब दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां जवाब दूंगा।

श्री सभापति: जवाब दे रहे हैं। कन्क्लूड नहीं किया है अभी इन्होंने। आप सुनिये तो सही।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं जवाब दूंगा लेकिन मुझे मेरी बात तो कहने दीजिये। आपने जो पूछा उसका जवाब दूंगा मैं। हरीश लड़का आरएएस का इम्तिहान देना चाहता था उसने अपने चाचा, चाचा का नाम था ठकराराम, यह आरएसएस का कार्यकर्ता है ठकराराम, उससे कहा कि चाचा कुछ जुगाड़ बैठाओ, पास करवाओ। उसने कहा कि ठीक है करते हैं देखो। यह ठकराराम बाड़मेर में प्राइवेट स्कूल चलाता है। ठकराराम ने जोगाराम से कान्टेक्ट किया, वह भी आरएसएस का आदमी। किशनाराम, आरएसएस द्वारा संचालित आदर्श

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

विद्या मन्दिर में टीचर है जोधपुर में, उसने बीजेपी के पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम जी से कान्टेक्ट किया, तीनों में बाकायदा व्हाट्सएप पर बातें हुई और तय हो गया कि बीस लाख रुपये दे दो, पास करवा देंगे। वह पास नहीं हुआ। पास नहीं हुआ तो ये दोनों के दोनों पहुंच गये उसके पास कि बीस लाख रुपये वापस ला। बीस लाख रुपये लेकर के जब ये जाने लगे बाड़मेर जोधपुर से तो बीच में ही पकड़े गये। पुलिस ने पकड़ लिया और 19 लाख और कुछ पैसे, बाकी चाट-पकौड़ी में खर्च हो गए होंगे वो सब वसूल पा लिये। ये सब आरएसएस के ही लोग हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का एक आदमी तो बता दो। इस पाराशर के अलावा एक आदमी तो बता दो।

रीट की परीक्षा जो 2016 और 2018 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर, जयपुर में स्ट्रांग रूम बनाकर लगाई गई थी। स्ट्रांग रूम वहां बनाया था, यह तो शिक्षा संकुल में बनाया है। आपने एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बना दिया था। आप बार-बार पूछ रहे हैं कि यह किसका आर्डर था? यह आर्डर था अतर सिंह नेहरा जो जिला कलेक्टर थे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस जिद को छोड़ो, सीबीआई के माजने मैंने आपको पूरे सुना दिए और कभी फुर्सत मिलेगी तो और सुना दूंगा। उसका पीछा छोड़ो और एसओजी पर आप विश्वास करो। निश्चित तौर पर वो एसओजी है जिसने कि चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस दे दिया था और 18-20 माननीय सदस्यों को दे दिया था। यह डरने वाला नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, विश्वास रखिए। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। (व्यवधान) चर्चा समाप्त।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उपनेता महोदय, जो आसन की व्यवस्था है दो घंटे चर्चा की, चर्चा समाप्त, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा...(व्यवधान) मैंने आगे का बिजनस ले लिया है, कृपया सहयोग करें। (व्यवधान) प्लीज विराजिए, विराजिए, विराजिए आप। प्लीज, सहयोग करें। आप लोगों की ही यह व्यवस्था थी, आसन और आपके बीच में चर्चा हुई, चर्चा में निर्णय हुआ कि दो घंटे की चर्चा होगी। आप भी बोल लिए,

(श्री सभापति)

आप भी बोल लिए और आसन ने यह व्यवस्था दे दी, चर्चा समाप्त। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से बारां जिले को औद्योगिक निवेश के लाभ से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में नार्दन बाईपास का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से आबूरोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 के प्रश्न पत्र चोरी होने की सीबीआई से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट परीक्षा तथा सरकारी नौकरी भर्ती की प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को लेकर बेरोजगारों द्वारा विधान सभा के सामने प्रदर्शन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री गिरधारीलाल महिया, सदस्य की ओर से प्रदेश भर में समस्त किसानों द्वारा मांग पत्र जमा करवाये जाने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोकर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल महिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री सभापति)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की तहसील रामगढ़ शेखावाटी (सीकर) के किसानों को फसल खराबा की पुन: समीक्षा करवाकर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से अलवर उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को अपग्रेड कर क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय घोषित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के चिकित्सालयों में सफाई कर्मियों के भुगतान तथा सफाई व्यवस्था में हो रही अनियमितता से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के गांवों को परस्पर सड़कों से जोड़ने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में तहसील स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आबादी क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से मारवाड़ में पर्यटन स्थलों के विकास एवं रियासत कालीन हवाई पट्टियों का जीर्णोद्धार कर हवाई सेवा प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से नीमकाथाना में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पीने का पानी तथा यमुना से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री सभापति)

(11) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड में नवीन एम्बुलेंस संचालित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से बालोतरा को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी। श्री गिरधारीलाल जी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों द्वारा मांग पत्र जमा कराने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन में दिक्कत

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने नियम 50 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बीकानेर जिले में, पूरे राजस्थान में कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोटिस भरे हुए दो-दो साल हो गए हैं। बीकानेर जिले में कृषि कुओं की बहुसंख्या को देखते हुए सामान नहीं मिलने की वजह से आज भी किसान को बिजली के कनेक्शन में दिक्कतें आ रही हैं। माननीय सभापति महोदय, सदन एक महत्वपूर्ण स्थल होता है। प्रतिपक्ष जो बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है, अलग तरह की बात कर रहा है। किसानों की, जवानों की, बेरोजगारों की बात होनी चाहिये थी। आज किसान कृषि कनेक्शनों के लिए, आज कोई सदस्य किसान की बात रखना चाहता है तो ये बीच में व्यवधान पैदा करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे बीकानेर जिले में कृषि कनेक्शनों की बहुसंख्या को देखते हुए लम्बे समय से कनेक्शन लम्बित पड़े हैं। राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि आप आने वाली फसल से पहले पहले एग्रीकल्चर के कनेक्शनों के लिए सामान उपलब्ध कराएं। माननीय सभापति महोदय, आज किसान इस सदन से आस लगाये बैठा है कि बजट सत्र चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से हमारी नीतियां बनेंगी। मगर प्रतिपक्ष ने एक ही राग लगा रखी है कि सीबीआई से जांच कराएं, जबकि पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चा हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं कि सदन को चलने दें शान्ति से चलने दें।

(श्री गिरधारीलाल)

आसन ने चर्चा करवा दी फिर भी प्रतिपक्ष जनता की मांग को सदन में रखने के लिए बाधित कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय से इस प्रजातंत्र में चर्चा की मांग की, जबकि संसदीय मंत्री महोदय ने क्लीयर कह दिया था कि कोर्ट में केस चलता है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी बड़ा मन बनाकर कि चर्चा हो इसलिए समय दिया, फिर भी प्रतिपक्ष अड़ा हुआ है। जनता की मांग जो एग्रीकल्चर पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए। मैं पुन: मांग करता हूं प्रतिपक्ष के साथियों, खाली सीबीआई से काम नहीं चलेगा। एक मांग को छोड़ो, पूरा सदन देख रहा है। आपको राजनीति का लाभ नहीं मिलेगा। आप देखते हो कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिले...(व्यवधान) यह हमारे संसदीय मंत्री महोदय ने क्लीयर कह दिया था फिर भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं मांग करता हूं कि जो किसान आपसे आस लगाये बैठा है, उसे आप निश्चित रूप से समय पर कनेक्शन दिलाएंगे। ऐसे लोग जो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, इस सूरत में जो लोग इनको भेज रहे हैं कि ये हमारे लिए चर्चा करेंगे, बोलने वालों की सुनेंगे, मगर राजस्थान के अन्दर उन्होंने एक ही टारगेट बना लिया है कि हम राजनीतिक लाभ के लिए करेंगे, चाहे छात्र को लाभ मिले या न मिले, किसान को लाभ मिले या न मिले, हम तो आरएसएस के फंडे को चलाएंगे। इनका आका आरएसएस है, बीजेपी नहीं है, इसलिए आरएसएस के फंडे को चलाएंगे, किसान की बात को नहीं चलाएंगे। सभापति महोदय, इनका आका आरएसएस है। इनके मंत्री, केन्द्रीय मंत्री, ये उनके घर जाते हैं वैधानिक पद पर होते हुए भी। यह आर.एस.एस. के इशारे पर हो रहा है, यह पार्टी के इशारे पर नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रजातंत्र के अन्दर इतना मौका देने के बाद, भगवान इनको सद्‌बुद्धि दे ताकि ये सदन को चलने दें। मैं अपने क्षेत्र और राजस्थान के किसान की मांग करता हूं कि समय रहते हुए किसानों को कनेक्शन दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की सात अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जी एण्ड टी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 22.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में नियम 75ए जोड़ा गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जी एण्ड टी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 25.10.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जी एण्ड टी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.8(3)एफडी/एसपीएफसी/विविध/सुलभ/2021 दिनांक 23.12.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जी एण्ड टी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 12.01.2022 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में संशोधन किया गया है; एवं
7. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जी एण्ड टी-एसपीएफसी/2017

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिनांक 25.01.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: श्री परसादी लाल मीणा।

आबकारी विभाग

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की 01 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/एक्स/2021 पार्ट-I दिनांक 06.10.2021 जिसके द्वारा होटल/क्लब बार के लिए अतिरिक्त बार काउंटर पर देय 10% लाइसेंस फीस को वर्ष 2021-22 के लिए माफ किया गया है।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

उपभोक्ता मामले विभाग

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग की 03 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ89(9)/सीए/सीपी/2020/III दिनांक 17.01.2022 जिसके द्वारा पेशेवर अधिवक्ता के जिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर दिये जाने वाले समेकित वेतन का निर्धारण किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)/खा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 30.11.2021 जिसके द्वारा सुश्री उर्मिला वर्मा को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक) नियुक्त किया गया है; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ89(22)/खा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 30.11.2021 जिसके द्वारा श्री निर्मल सिंह मेडतवाल को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक) नियुक्त किया गया है।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

उद्योग विभाग

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की 01 अधिसूचना सदन की मेज पर रखती हूं:-

अधिसूचना संख्या: प.14(5)उद्योग/1/2012 पार्ट दिनांक 23.09.2021 जिसके द्वारा अनुदान वसूली के मामलों में इकाइयों को राहत प्रदान करने हेतु एमनेस्टी स्कीम, 2021 लागू की गई है।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-28 की उप धारा 2 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी, जयपुर के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20)

2. रियल एस्टेट एक्ट 2016 की धारा 77(4) के अन्तर्गत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी, जयपुर के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20;

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (वर्ष 2020-21)

4. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 के अध्याय-4 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2020-21;

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21।

श्री सभापति: श्री लाल चन्द कटारिया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित छह प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

1. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

2. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021;

(श्री लालचन्द कटारिया)

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

3. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021;

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

4. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021;

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

5. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021; एवं

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री अमीन खां।

समिति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्र. सं. 2 व 3)

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति, 2021-22, समिति के द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: याचिका का उपस्थापन, श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित)।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद, श्री गणेश घोघरा।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन तीन सालों में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल करवायीं। कई क्षेत्रों में काम हुए। राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, वे गरीबों के मसीहा हैं। उनको आम गरीब जनता अशोक महान के नाम से जानती है। जिस तरह से कोरोना में सरकार ने कार्य किया, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कोरोना महामारी में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री रात-दिन चिंतित थे। इन्होंने किसी को भूखा सोने नहीं दिया और इधर बीजेपी के लोग, इनके मोदी जी जो कि मोमबत्तियां जलवा रहे थे, ढोल पिटवा रहे थे, थालियां बजवा रहे थे। कांग्रेस के जो भी नेता थे, उन्होंने घर-घर जाकर मदद की, लोगों को सामग्री पहुंचायी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों में छिपकर बैठे हुए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमारे यहां पर जांचें नहीं होती थीं। जांचें बाहर हो रही थीं। अब हमारे यहां पर हर पीएचसी, सीएचसी पर कोरोना की जांच होती है। आरटी-पीसीआर टैस्ट भी निःशुल्क हो रहा है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात बोर्डर पर रतनपुर से लगा हुआ है। इस कोरोना काल में मुख्य मंत्री जी ने जो काम किया है, ऐसा काम हिन्दुस्तान के किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया है और न ही कोई कर सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रतनपुर बोर्डर से लोग पैदल चलकर आ रहे थे, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने वहां के एसडीएम, उपखण्ड अधिकारी को पाबन्द किया और वहां पर चाय-पानी और खाने की व्यवस्था की और उनको गन्तव्य स्थान पर बसों में बैठाकर भिजवाने का काम किया। ये हैं अशोक महान, ये हैं अशोक गहलोत। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल असत्य बोलने का कार्य करते हैं, जोर से बोलने का काम करते हैं। इनके राज्यों में कई घोटाले हुए, आज तक इनके एक मंत्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इनका एक मंत्री जेल में

(श्री गणेश घोघरा)

नहीं गया। कांग्रेस के शासन में जिसने घोटाला किया, उसको सज़ा मिली। ये असत्य लोग हैं, जोर से बोलते हैं। इन्होंने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया। इनका कार्य एक ही है, लोगों को गुमराह करो। गहलोत साहब की सरकार थी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाया था। इनकी सरकार ने खाली राजीव गांधी का नाम ब्रश लगाकर, कलर लगाकर मिटाने का कार्य किया। राजीव गांधी हमारे दिल में बसते हैं। उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य किये हैं। इस कोरोना काल में कई परिवार उजड़ गये, कई बच्चे अनाथ हो गये। ऐसे संकटकाल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया, सबके भोजन की व्यवस्था की। इन्दिरा रसोई चालू की जो कि एक वरदान साबित हुई। 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन दिया। उसके बाद भी कोरोना काल में इन्दिरा रसोई योजना में नि:शुल्क खाने की व्यवस्था की। आक्सीजन की कमी हो गयी थी, आक्सीजन सिलेण्डर नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे यूथ कांग्रेस के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.वी. श्रीनिवास जी आक्सीजन मैन बनकर, पूरे हिन्दुस्तान में जहां-जहां कमियां थीं, उन्होंने वहां खूब सारी सेवा की। बीजेपी के लोग और मोदी जी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया कि ये लोग आक्सीजन कहां से ला रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने काम किया। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है।

(समय: 14.00 बजे)

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज हर व्यक्ति को, हर वर्ग को दिया है। ये संजीवनी जड़ी-बूटी बनकर हमारे क्षेत्र में कार्य किया है। हमारा टीएसपी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहां पर गरीब लोग रहते हैं। उनके पास पांच सौ - हजार रुपये भी नहीं होते। वे मजदूरी करते हैं, कमाकर लाते हैं और कमाकर खाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी हास्पिटल और कुछ प्राइवेट हास्पिटल मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जोड़े हैं तो काफी लोगों को फायदा मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इस योजना से पूरे राजस्थान में हर गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस योजना से 788 सरकारी व 639 निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। हमारे

(श्री गणेश घोघरा)

वहां लोग किसी के पास मांगने जाते हैं, पैसा नहीं देते, पहले जमीन गिरवी रखवाते हैं या कहते हैं गहने गिरवी रख जाओ तो हम आपको 25 हजार देंगे, 20 हजार देंगे तो वह इलाज करा पाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से काफी लोगों को फायदा मिला है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान के साथ-साथ दूसरे राज्य के मरीज भी हमारे यहां आये। उन्होंने भी इलाज करवाया और सरकार की योजना का भरपूर फायदा लिया। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी। दूसरे राज्य के लोग एम.पी. से, हरियाणा से और आसपास से, जहां से भी आए, उनका भी हमने नि:शुल्क और कम पैसों में इलाज किया। यह है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की योजना। प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कालेज खोलने की तर्ज पर नर्सिंग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया। यह बहुत ही सराहनीय है। इसी के साथ 'प्रशासन शहरों के संग' और 'गांवों के संग' शिविर अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा गया। यह एक वरदान साबित हुआ, एक गरीब का सहारा बना। पेंशन बढ़ाई, जिसको 500 रुपये मिल रहे थे, उसकी 750 की, जिसको 750 मिल रहे थे, उसको 1000 दिए गए, जिसको 100 मिल रहे थे, उसको 1500 रुपया दिया गया। यह है अशोक गहलोत जी की योजना, अशोक गहलोत जी का काम और भारतीय जनता पार्टी वाले यहां पर खाली नारे लगाने, असत्य बोलने, जोर से बोलने और कुछ काम नहीं है इनका।

सभापति महोदय, विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। टी एस पी क्षेत्र से हमारे युवाओं की मांग थी, सामाजिक संगठनों की मांग थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को अवकाश घोषित हो। हमारी सरकार ने सुनी और मुख्य मंत्रीजी ने 9 अगस्त को अवकाश घोषित किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसानों ने जो सरकारी बैंकों से ऋण लिया था, जो मिनी बैंकों से ऋण लिया था, उसका सरकार ने 8 हजार 181 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये गये। साथ ही गत सरकार के समय से लम्बित 6 हजार करोड़ रुपये का भी भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का किसानों को ऋण माफ किया कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने।

(श्री गणेश घोघरा)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया। पांच वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में 877 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जा चुके हैं। 166 पशु चिकित्सा उप केन्द्र पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये गये।

इस तरह से राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं। तीन वर्ष में इतना काम किया कोरोनाकाल होते हुए भी जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले पांच साल में कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात 'प्रशासन गांवों के संग', 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान में जो वर्षों से बैठे हुए थे, वर्षों से उनकी मांग थी, कई पीढ़ियां निकल गईं कि मुझे मेरे मकान का पट्टा मिल जाए, मैं बिलानाम भूमि पर बैठा हुआ हूं वनाधिकार भूमि पर बैठा हुआ हूं तो मुझे जमीन का पट्टा मिले मुझे जमीन का खातेदारी हक मिले। इस प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में काफी लोगों को फायदा मिला और उनका हक और अधिकार मिला। यह बहुत बड़ी मांग है। भारतीय जनता पार्टी की पांच साल सरकार थी, किसी को एक पट्टा भी नहीं दिया, एक भूमि का आबंटन भी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले खाली असत्य बोलने का काम करते हैं। न तो इनके 15 लाख रुपये आए, न 2 करोड़ नौकरियां मिलीं और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ केन्द्र में शोषण कर रही है। उनको जमीन से हटा रही है, उनका शोषण कर रही है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, इस योजना में अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंदों को नि:शुल्क भोजन पैकेट वितरित किये गये। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली गयी। यह पूरे राजस्थान में गरीब माता-पिता के लिए एक वरदान साबित हुई। गरीब का बच्चा भी आज अंग्रेजी पढ़ सकता है। गरीब इतना पैसा नहीं दे सकता है कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके। इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ब्लाक पर खोलने की वजह से हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में कई आदिवासी बच्चों ने इन स्कूलों में एडमिशन लिया। हर वर्ग के बच्चों ने एडमिशन लिया। यह

(श्री गणेश घोघरा)

बहुत अच्छी योजना है। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमारे जो गरीब भाई थे, उनको फायदा हुआ, उनके बच्चों को फायदा हुआ। यह सोच अगर कोई रख सकता है तो कांग्रेस पार्टी रख सकती है, कांग्रेस की सरकार रख सकती है, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी रख सकते हैं। मैं इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे टीएस.पी. क्षेत्र में, जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र में अंग्रेजी मीडियम स्कूल हमारी भावना के अनुरूप खोला और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

इसी के साथ स्थानीय स्तर पर कन्या महाविद्यालय के अभाव में अनेक बालिकाएं, जो 40-40, 50-50 किलोमीटर से आती हैं, उनके लिए 500 बच्चियों पर एक महाविद्यालय खोला जाएगा। यह बहुत सराहनीय कदम है। कई बच्चियां बारहवीं करने के बाद शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। बीच में अध्ययन छोड़ देती हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि जहां जिस स्कूल में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 लड़कियों से अधिक नामांकन होगा, वह स्वत: ही कालेज में परिवर्तित हो जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में हमारे रामसागड़ा, वह भी काफी दूर है, बिछीवाड़ा पंचायत समिति में वहां कालेज खोल दिया जाए तो हमारी बच्चियों को काफी फायदा मिलेगा। इधर पालदेवल में भी एक महाविद्यालय खोल दिया जाए तो हमारे यहां भी बच्चियों को फायदा मिलेगा। उनको बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। यहां के लोगों की मांग भी है। दूर होने की वजह से, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, साधन समय पर नहीं मिलने पर बच्चियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। यह 500 का जो स्कूल में रखा है, मुख्य मंत्रीजी का बहुत सराहनीय कदम है। बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा तीन साल में किसी ने काम नहीं किया। लेकिन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जो वादे किये, उनको पूरा किया। इसी को कहते हैं अशोक महान, अशोक गहलोत, जो किताबों में पढ़ते थे हम अशोक एक महान सम्राट हुआ करता था। उसने जगह-जगह सराय खुलवाए, उसने कई रोड बनवाए, वृक्षारोपण किए, ऐसे कई जनहित के काम किये। उसी तरह, राजस्थान में अशोक महान जैसे हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने तीन साल में काफी काम किये। ऐसा पूरे हिन्दुस्तान में किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया। मुझे उन पर गर्व है। ऐसे मुख्य मंत्री हमको कभी नहीं मिलेंगे, जो सबको साथ लेकर चलते हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, 5 करोड़ की मिसिंग लिंक दी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह बीजेपी का

(श्री गणेश घोघरा)

एमएलए है, यह इस पार्टी का एमएलए है। उन्होंने 5 करोड़ रुपये, विधायक को अपने विधान सभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिसिंग लिंक रोड दी। इससे बड़ा दिलदार, दरियादिल आदमी, ऐसा मुख्य मंत्री कभी नहीं मिलेगा और हो भी नहीं सकता।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2019-20 व 2020-21 के 23 हजार 167 विद्यार्थियों को 11 करोड़ 48 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में वर्ष 2019-20 की 2 हजार 436 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गयीं।

हमारे टीएसपी क्षेत्र में दूर-दूर से बच्चियां आती हैं। सभी वर्गों को स्कूटी वितरित की गयी। वीरबाला कालीबाई, जो अपने गुरुजी को बचाने के लिए अपने खेत से घास की गठरी लेकर आ रही थी, अंग्रेज उनको घसीटकर ले जा रहे थे, उसने अपनी दरांती से अपने गुरूजी को बचाने के लिए, उनकी रस्सी काटी। वह है कालीबाई भील कलासुआ, जो रास्तापाल की रहने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां भी स्कूलों को बंद कर दिया। उनको दूसरी स्कूल में मर्ज कर दिया। यह शिक्षा के हितैषी नहीं हैं। यह युवाओं के हितैषी नहीं हैं। यह केवल राजनीति करना चाहते हैं और अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कोरम नहीं होगा अगर हम वाकआउट कर जाएंगे तो। (व्यवधान) कोरम नहीं होगा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए, आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मदरसा बोर्ड एक्ट बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोरम नहीं है ...(व्यवधान) हम वाकआउट करके जा रहे हैं।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी, माननीय मंत्रीजी से व सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मेरे यहां भी अल्पसंख्यक

(श्री गणेश घोघरा)

काफी गरीब बच्चे हैं, वहां एक छात्रावास खोला जाए। मदरसों में आधुनिकीकरण किया जाकर उसको आगे बढ़ाया जाए।

हमारी सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपये व्यय करके बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अन्त्योदय के लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गयी। माननीय सभापति महोदय, हमारे टीएसपी क्षेत्र में पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग उससे अड़ते नहीं थे। वे जानते थे कि अपन इसकी अगर मदद करेंगे तो पुलिस वाले हमारा नाम FIR में लिख देंगे। हमको या तो मुलजिम बना देंगे या हमको पेशी करनी पड़ेगी और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल नहीं ले जाते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह योजना निकाली है, कोई भी व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त है, उसको समय पर अस्पताल ले जाता है, उसका जीवन बच जाता है। उसके परिवार वाले भी दुआ देंगे, उसके माता-पिता भी दुआ देंगे। सरकार की ओर से उसको 5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यह बहुत बड़ा काम है। मैं सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

दिव्यांगों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा का विस्तार करते हुए 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजन का भी निगम की साधारण, द्रुतगामी एवं रात्रि सेवा बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रारम्भ की गयी। दिव्यांगों को आने-जाने में तकलीफ नहीं हो, उनको सुविधा मिले, पैसे नहीं लगें, उनको निःशुल्क यात्रा के लिए सोचा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी हर विधान सभा क्षेत्र में 50-50 दिव्यांगों को स्कूटी दी। जो बेरोजगार हैं, प्राइवेट रोजगार के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दिया, मुख्य मंत्रीजी के नारे लगाए, कि पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा काम किया, दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी वितरण की गयी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई वर्षों से कृषि महाविद्यालय की मांग थी। सीएम साहब ने हमको कृषि महाविद्यालय की घोषणा की। उसके बाद तीरंदाजी एकेडमी भी उन्होंने वहां खोल दी। मेरे विधान

(श्री गणेश घोघरा)

सभा क्षेत्र में लॉ कालेज भी खोल दिया। महाविद्यालय, एनीकट, पुल, सड़कें, स्कूल क्रमोन्नत, पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीएचसी, सीएचसी, इन तीन साल में काफी काम लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। हर विधान सभा क्षेत्र में हर एमएलए को जो मांगा वह दिया है। ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मैं पहली बार यहां एमएलए बनकर आया हूं, लेकिन माननीय लोकप्रिय अशोक गहलोत जी ने सबका ध्यान रखा, 36 कौम का ध्यान रखा। अमीर हो, गरीब हो, युवाओं को नौकरियां दीं। युवाओं के लिए भी चिन्तित हैं। कई तरह की कई योजनाएं हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, इनके नेतृत्व में मैं कहना चाहता हूं, हम वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और गहलोत जी को वापस मुख्य मंत्री बनाएंगे। मुझे यहां बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, डोटासरा साहब ने जो प्रस्ताव रखा, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधारकर जो अभिभाषण दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं।

महामहिम ने 56 पेज के अभिभाषण में, राजस्थान की एक-एक चीज को डिटेल, अलग-अलग बताते हुए राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की तारीफ, शासन की जो कारगुजारी पेश की, उसका हम धन्यवाद देते हैं।

सबसे बड़ा वह आदमी है, जिसमें किसी धन-दौलत, सत्ता का अहम व घमण्ड नहीं हो। राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत एक गांधीवादी हकीकत का सही आदमी है। इनको तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने का भी कोई फख्र महसूस अंजान आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री को बार-बार बधाई और धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किसी भी जाति के खिलाफ कोई कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं की। किसी भी जाति या समुदाय को दबाने की भी कभी कोशिश नहीं की। बेईमानी से तो हमेशा कई कोस दूर रहे, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

राजस्थान में सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान और रेगिस्तानी

(श्री अमीन खां)

इलाक़ों में शिक्षा की कमजोरी रही। उन इलाक़ों में भी सैकड़ों स्कूलें खोलीं और क्रमोन्नत हुईं, इसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंकों से जो फसली ऋण लिए जाते हैं, लाखों-करोड़ों रुपयों का किसानों का कर्जा माफ किया, जिससे किसानों को राहत मिली।

गरीब से गरीब इंसान जो चाहे शहर में, चाहे गांवों में, चाहे ढाणी में दूरदराज रहता है, ऐसे शख्सों का चयन करके भी एक रुपये किलो का गेहूं और अनेक प्रकार की कई सहायता आसानी से वितरण की जिससे राजस्थान में कभी इन तीन सालों में एक भी इंसान एक रात भी भूखा नहीं सोया, यह राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं इस मौके पर राज्यपाल महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अति कृपा करके इस सदन में पधारकर सरकार के काम-काज का अच्छी तरह से लेखा-जोखा पेश किया, उनका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ, आधे से ज्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में, सीमावर्ती एरिया में कई ऐसी जगहें थीं जहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक कोई पैदल या आदमी किसी तरह से चलता था और प्यास की वजह से मर जाता था। इन्दिरा गांधी नहर का पानी जैसलमेर के अन्तिम छोर तक पहुंचा। आज जिस जगह पर एक आदमी प्यास से मर सकता था, उस जगह पर हजारों-लाखों क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, एक खुशहाली जाहिर दिखती है।

सीमावर्ती एरिये में जहां जमीन के नीचे मीठे पानी का भी अभाव है, उस एरिये में नर्मदा प्रोजेक्ट स्वीकृत करके वहां पर लोगों को पानी पिलाने की जो कार्यवाही शुरू की है, यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। वहां पर हजारों आदमियों को नहर का मीठा पानी आसानी से मिलेगा, लोग मुख्य मंत्रीजी का गुण गायेंगे।

इलाज के मामले में भी हर तीन-साढ़े तीन हजार की आबादी पर एक सब-सेंटर भी खोला गया है और पच्चीस-तीस हजार की आबादी पर एक पी.एच.सी. भी खोली है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पिछले दो साल में दुनिया की बीमारी, इस देश की ही नहीं, भयंकर महामारी इस कोरोना में मुख्य मंत्रीजी ने माकूल और शानदार इंतजाम किया। राजस्थान के किसी जिले में और किसी इलाके में कोई भी इंसान की बरबादी या परेशानी होने का मौका नहीं दिया गया, सबकी दवाइयों का मुफ्त में इंतजाम किया गया। डाक्टर्स,

(श्री अमीन खां)

नर्सिंग स्टाफ का हर जगह माकूल इंतजाम रखा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

(समय: 14:23 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जिसने अपने राज्य में तीन सालों में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी और शानदार और ईमानदारी से इंतजाम रखा, जिससे हर समुदाय और हर वर्ग को अच्छी तरह से इंसाफ मिला और उनको धन्धा/रोजगार मिलने का भी मौका मिला।

मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री ने जिस तरह से गांवों के कामों में अच्छा इंतजाम किया, रेगिस्तानी इलाके में जहां पर दूरदराज सैकड़ों किलोमीटर पर गांव और ढाणी बसी हुई थी, पिछले पंचायत के पुनर्गठन में, छोटी-छोटी आबादी पर नयी पंचायतों का गठन किया। आज उन जगह एक-एक पंचायत में 40-40, 45-45 लाख का शानदार पंचायत भवन बन चुके हैं और दूसरे भवन भी बन रहे हैं जिसमें पटवारी का कार्यालय भी उसी भवन में, पंचायत का कार्यालय भी उसी भवन में और तहसीलदार का भी विजिट, बी.डी.ओ. का विजिट दौरा हो तो उसकी भी उस कार्यालय में गुंजाइश रखी है। आज से पहले ऐसे पंचायत भवन कभी नहीं बने। यह मुख्य मंत्री को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इलाका पूरे हिन्दुस्तान में शिक्षा के स्तर में परम्परा का जो इन्तजाम था, उससे नीचा है। उसकी नीचाई का यह कारण है कि रेगिस्तानी इलाके में पढ़ाई कमजोर रही है। सुखाड़ियाजी के राज के वक्त की बात है, उन्होंने राजस्थान के 11 रेगिस्तानी जिलों में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पाबन्दी लगा रखी थी इसलिए शिक्षा और मेडिकल का स्टाफ मिलता था। पिछले बी.जे.पी. के शासन में उस पाबन्दी को हटा दिया गया। उसके हटने के बाद में आज वहां स्थिति शिक्षा और मेडिकल की खराब हो रही है क्योंकि हजारों लोग तबादला होकर झुन्झुनूं, सीकर, नागौर, भरतपुर, अलवर चले गये।

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मास्टरों के 776 पद खाली हैं। आप अनुमान लगा सकते हो कि जिस क्षेत्र में सात सौ-आठ सौ मास्टरों के पद खाली हैं तो वहां पर शिक्षा का हाल किस प्रकार चलेगा? हमारे गांव में बोर्डर

(श्री अमीन खां)

के गडरा रोड ब्लाक में देताणी गांव में मॉडल स्कूल है, उस मॉडल स्कूल में 28 पद स्वीकृत हैं, 28 में से 15 पद खाली हैं। अनुमान करें कि यह किस बात की मॉडल स्कूल है? इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र को स्पेशल सुविधाएं देने की विशेष कृपा करें ताकि जो गरीब इंसान दबा हुआ है अक्ल से, इल्म से, दीन से, वह आगे आ सके। यही बात कहता हुआ पुन: मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि यहां पर पधारकर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, जिससे हमें संतोष है। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे भी बोलने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ तब से विधान सभा में लगातार हंगामा होता रहा। हम भी इस हंगामे को देखते रहे और जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस लोकतंत्र के माध्यम से हमें मिल रही हैं, उसका हम किस तरह से सदुपयोग करें और किस तरह से दुरुपयोग करें, हमें अपने आप में यह झांक कर देखना होगा और अगर यही हालात रहे तो देश के अन्दर लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में रीट की परीक्षा को लेकर जो धरना, आन्दोलन, नारे हाउस के अन्दर लगाये जा रहे थे, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार पर जिस तरह के आरोप लगाये जा रहे थे और जब आपने व्यवस्था दी, व्यवस्था में दोनों पक्षों को अपनी-अपनी बात रखने का जो अवसर दिया और उससे यह स्पष्ट हो गया, विपक्ष सकते में आ गया कि अगर हम शायद यह व्यवस्था नहीं लेते तो हमारे पास में विरोध करने का मुद्दा था। अब वे थक कर बाहर चले गये, उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे धारीवाल साहब न जाने कौन से साबुन का उपयोग करते हैं, क्या लाजवाब जवाब दिया उन्होंने। एक-एक बिन्दु का जवाब उन्होंने जिस तरीके से दिया, चाहे सी.बी.आई. की मांग को लेकर हो और चाहे किसी तरह की एस.ओ.जी. की बात को लेकर हो, जिस तरीके से धारीवाल साहब का जवाब था, उससे विपक्ष निरुत्तर हो गया। वे माननीय मुख्य मंत्री महोदय पर

(श्री खुशवीरसिंह)

जो आरोप लगाते हैं, मुख्य मंत्री महोदय एक गांधीवादी विचारों के व्यक्ति हैं कि तीसरी बार मुख्य मंत्री रहते हुए कभी उनके दिल और दिमाग में पद का अहम नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे 500 वर्ष पुरानी वह घटना याद आती है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब शेरशाह सूरी ने पाली के जैतारण कस्बे में मारवाड़ पर आक्रमण किया। उस वक्त दो भाई थे जैता और कूपा सोजत में। उन्होंने सोचा कि 80 हजार सेना के साथ में शेरशाह सूरी हमारे मुट्ठी भर लोगों के साथ किस तरह के हालात करेगा, उन्होंने सोचा कि हम पलायन कर दें। गांवों की कुछ महिलाएं अपने आप में यह विश्वास जाहिर कर रही थीं कि जब तक जैता और कूपा जीवन्त हैं तब तक हमारी शेरशाह सूरी की सेना के सैनिक अंगुली तक नहीं उठा सकते हैं। इस विश्वास के साथ वे दोनों भाई 8 हजार सैनिकों के साथ में, जिसका नाम आज भी जैता रण है, 8 हजार सैनिकों के साथ में 80 हजार सेना के सामने, पहला युद्ध है विश्व का कि 8 हजार सैनिक शहीद हो गए। सिर्फ और सिर्फ इतने से विश्वास पर कि उन महिलाओं ने कहा कि हमारी इज्जत और आबरू की रक्षा कौन करेगा। यह विश्वास आज मैं मुख्य मंत्री पर करता हूं। जब तक अशोक गहलोत हैं राजस्थान के अन्दर, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। यह मैं कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो विकास करवाया, उस पर सार्थक चर्चा करते। आज ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी बजाय विपक्ष आकर यह सार्थक मांग करता कि इस बारे में कैसे कठोर कानून बनाया जाय। किसी भी सदस्य ने कठोर कानून बनाने को लेकर एक शब्द भी बात नहीं की। उनको मालूम है, हम अगर हमारे गिरहबान में झांक कर देखेंगे तो हमारे क्या हालात हो जाएंगे। यह मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष बंटे हुए हैं और इसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना होगा, अन्यथा यह लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। कुछ लोगों की नजरें इस लोकतंत्र पर हैं कि लोकतंत्र की क्या-क्या कमियां हम निकालें। मैं चाहूंगा कि ऐसी सार्थक चर्चा हो और इस चर्चा के माध्यम से किस तरह कानून सख्त बने। चाहे कोई कानून हो। मैं सिर्फ रीट परीक्षा के लिए ही कानून की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरह के कानून जो देश के अन्दर जिस

(श्री खुशवीरसिंह)

तरह आज मिलावट के प्रति, जिस तरह से जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया जा रहा है, इसके लिए भी कानून को और सख्त करने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम किसी तरह से गरीबों का हित कर सकते हैं। हम किस तरह से किसानों को सुविधा दे सकते हैं। हम उन युवाओं को, हमारे ऊपर लाखों युवाओं की नजरें हैं, उन युवाओं को न्याय किस तरह दिला सकें और इस मानसिकता से युवाओं को किस तरह दूर कर सकें कि उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ हमने इस तरह से मात्र नौकरी पर ही डाल दी है। हमें सोचना होगा कि उन युवाओं की सोच को बदलना होगा और नौकरी के अतिरिक्त हम किस तरह व्यवसाय कर सकें, रोजगार किस तरह से पैदा कर सकें। उसकी ओर भी सदन को सोचना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने इतने काम करवाए, इतने काम करवाए, मेरे क्षेत्र में मैं कह सकता हूं, प्रदेश के बारे में तो माननीय राज्यपाल महोदय की यह पुस्तिका, अगर विपक्ष आराम से महामहिम को सुन लेते तो शायद इनको इतना विरोध करने का मुद्दा भी नहीं होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सौगात दी है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, वे सौगातें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र में 70 सालों के इतिहास में किसी ने कल्पना नहीं की होगी, वे काम करके दिखाए हैं। चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, सबसे पिछड़ा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र था। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार-चार हाईवे की स्वीकृति जारी कर दी। नये स्टेट हाईवे घोषित किये। मेगा हाईवे की स्वीकृति जारी कर दी और सड़कों का जाल बिछा दिया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां कुछ छुटभैया नेता जेजेएम, जल जीवन मिशन के तहत बातें करते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र में जो स्वीकतियां जारी हुई करोड़ों रुपयों की, वह तो केन्द्र सरकार का पैसा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद भी आज जिस तरह से केन्द्र को हमें जो सहायता देनी चाहिए थी, 90 प्रतिशत सहायता केन्द्र को देनी थी, केन्द्र ने हठधर्मिता के साथ वह राशि 50 प्रतिशत कर दी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और विपक्ष के उन सार्थियों को कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें फैलाते हैं। यह तो केन्द्र का पैसा है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि माननीय

(श्री खुशवीरसिंह)

मुख्य मंत्री महोदय ने दिल्ली जाकर 50 प्रतिशत राशि पहले वहां जमा करवायी। उसके बाद में उन्होंने स्वीकृति जारी की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोरोना के अन्दर केन्द्र ने हमारे हाल पर छोड़ दिया था उन मजदूर भाइयों को, जो मुम्बई से चल कर मेरे गांव के लोग पैदल चलकर आए। आठ-आठ, दस-दस दिन के अन्दर वहां पहुंचे हैं। प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि टिकट पकड़ा दिया उनको, आपने तो कुछ नहीं किया। आज सुविधाजनक यात्रा करवाकर उनको गन्तव्य तक उन मजदूरों को भेजा। अगर वहां आप उनकी व्यवस्था करते, उनके रहने के कैम्प लगा देते, खाने की व्यवस्था कर देते तो बात समझ में आती। मुख्य मंत्रीजी ने कोरोनाकाल में जो प्रबन्धन किया है, वास्तव में अद्वितीय प्रबन्धन है। कल्पना से परे है। ऐसा प्रबन्धन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। ऐसा प्रबन्धन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के अन्दर किया है। इनके पास कोई विरोध करने का मुद्दा ही नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जब पहली बार बने, उस समय जो अकाल प्रबन्धन किया, वहां के लोगों ने एक नहीं, पांच-पांच, सात-सात वर्षों तक उस गेहूं का सेवन किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने पहली बार जब निःशुल्क दवा योजना लागू की, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, पहला प्रदेश था राजस्थान जहां विश्व के देशों के लोग देखने हेतु आकर गए कि यह क्या व्यवस्था और किस तरह से यह चल रही है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की है। हम शिविरों में जाते थे और एक-एक शिविर में दो-दो सौ, चार-चार सौ लोग अपना चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा करवाते थे। उसमें सबसे बड़ी बात यह रही है कि सरकारी अस्पतालों के साथ में निजी अस्पतालों में छूट दी गयी है। उससे कई लोग जीवन बचा पाये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। आक्सीजन की कमी को भी हमने महसूस किया है कोरोना काल के अन्दर। बिना आक्सीजन तड़पते हमने उन मरीजों को भी देखा है, उनके परिवार वालों को टीवी के माध्यम से हमने देखा है और मुख्य मंत्री महोदय ने, 500 से ज्यादा आक्सीजन की यूनिट्स अस्पतालों में आज लग चुकी हैं। मेरे गांव जोजावर में सीएचसी पर आक्सीजन यूनिट लग चुकी है। चार सौ बैड पर आक्सीजन की सप्लाई करने की व्यवस्था वहां आज हो चुकी है।

(श्री खुशवीरसिंह)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो कार्य अस्पताल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में किये हैं, वास्तव में आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा, वह किया। मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी मिलकर, आज हमारे पच्चीस सांसद हैं दिल्ली के अन्दर, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि एनएफएसए की जो सहायता मिलती है, उन गरीब परिवारों को, उसकी केन्द्र सरकार से बात कर छूट दिलवायें और जो जरूरतमंद परिवार वंचित रह गये, उन परिवारों के नाम जुड़ने चाहिये। उनको भी दो रुपये किलो गेहूं उपलब्ध होना चाहिये। यह मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा। यह सहायता राशि भी आज हम दिलवायें ताकि जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचा सकें।

अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना लागू हुई थी। मेरा एक सुझाव है कि इस योजना को जिन ग्राम पंचायतों ने अधिग्रहण कर लिया, उसका जो बिजली का बिल आता है, वह बिल की राशि पहले तो पुनर्भरण की जाती थी लेकिन पिछले पांच-सात वर्ष से वह बन्द कर दी गयी है। मैं चाहूंगा कि पंचायतों के विकास की राशि उन ग्राम पंचायतों तक पहुंच रही है, चाहे एसएफसी या 15वें वित्त आयोग की राशि, उसके बावजूद भी स्टेट फण्ड पूरा का पूरा बिजली के बिल में जा रहा है। विकास में एक पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके बारे में भी हमें विचार करना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जब पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2013 की भर्ती की थी पंचायती राज में, उन लोगों की संविदा के आधार पर भर्ती हुई थी। हमारे माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपन ने भी वादा किया था कि उनको हम स्थाई कर देंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा और इस तरह अपनी सरकार के अंदर उनको किस तरह से स्थाई कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समाजों के बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पिछड़े समाज हैं और अति पिछड़े समाज की श्रेणी से वे वंचित रह गये हैं। वे लगातार पिछले चार-पांच माह से सभी विधायकों के पास पहुंचकर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के विधायकों के पास पहुंचकर अपनी मांग को रखने की बात कर रहे हैं और वे यह कह रहे हैं कि हम अति

(श्री खुशवीरसिंह)

पिछड़ा वर्ग में हैं, लेकिन हम वंचित रह गये हैं। मैं सरकार के माध्यम से उनके लिए मांग करना चाहता हूं कि मिरासी, ढाढ़ी, लंगा, मांगणियार, राणा, दमामी जातियों को विशेष आरक्षण दिया जाये ताकि जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनको भी लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा कि देश का पहला कम्युनिटी लेपर्ड कंजर्वेशन जवाई, पाली जिले में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर इतने लेपर्ड हैं, लेकिन वहां पर वन विभाग का किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं, क्योंकि वहां वन विभाग नहीं है, सरकारी भूमि है, खातेदारी भूमि है, उसके अन्दर चरागाह भूमि में वह लेपर्ड कंजर्वेशन है। शुरू में लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन आज यह हालात हो गये हैं कि वहां आम जन की आय बढ़ गयी है और टूरिज्म की इतनी अपार सम्भावनाएं हो गयी हैं, वहां सैकड़ों होटल आ चुके हैं और लोगों के लिये रोजगार बढ़ने लग गया है। लेकिन एक खतरा मंडराने लगा है कि जो हमारे लेपर्ड है, वह 70 प्रतिशत लेपर्ड कैटल पर निर्भर थे। हमारी भेड़, बकरी और अन्य पशुओं पर निर्भर थे, लेकिन शनैः-शनैः हमारी जो कैटल है, वह कम होती जा रही है। जो पशुपालक परिवार थे, उन्होंने अपना व्यवसाय बदल दिया है और उसकी वजह से आज ये हालात हो गये हैं कि आने वाले पांच साल या ज्यादा से ज्यादा आठ साल तक यह लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व रह पायेगा। इसके लिये मेरा सुझाव है कि वहां पर हमें अंग्रेजी बबूल को निकालकर चरागाह भूमि में से, सरकारी भूमि में से वहां पर हमें ग्रासलैण्ड डवलप करने होंगे और ग्रासलैण्ड डवलप करने के बाद में हमें जो वन्य जीव है, जो उनके लिये एक बेस है, उनको हमें छोड़ना होगा, तभी वे सरवाइव कर पायेंगे, अन्यथा आने वाले पांच-सात सालों में यह सिमट जायेगा। यह इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राशन डीलरों के पास में जो राशन सामग्री सप्लाई की जा रही थी, वह हमारे क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही थी। सहकारी समितियों का जय सहकार का जो नारा है 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' लेकिन आज हालात ये हो गये हैं कि इन सहकारी समितियों के पास तनख्वाह देने के लिये पैसे नहीं रहे हैं और निगम के माध्यम से यह राशन सामग्री सप्लाई करवायी जा रही है और निगम ने क्या किया कि ठेकेदारों को उससे

(श्री खुशवीरसिंह)

30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत ऊंची दर में जो हमारी सहकारी समितियां सप्लाई कर रही थीं, उससे ऊंची दर पर उन्होंने ठेका दे दिया और ठेकेदारों की कई शिकायतें भी आयी हैं, अखबारों में भी छपी हैं। माल कम पहुंचना, ऊंची दर पर देना, तो मैं इसके लिए सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आपने भी एक वक्तव्य दिया था कि इसको हम सहकारिता के माध्यम से पुन: प्रारम्भ करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं तो सरकार का यह अहम उपक्रम आज बन्द हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। अब मैं पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू.डी. की सड़कें स्वीकृत होती हैं, उसमें ठेकेदार दो चीजें करते हैं, एक तो पूल बनता है, पूल बनने के बाद में एक व्यक्ति ठेका लेता है और वह मर्जी आये तो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है और उसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इतनी कम दर में डीएल.सी. लेते हैं कि काम करा नहीं पाते। ऐसी स्थिति में आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन ऐसी अहम सड़कें माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा की सड़कें हैं, परन्तु अभी तक वे प्रारम्भ नहीं हो पायी हैं। कुछ हुई हैं तो बहुत धीमी गति से हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि 10 प्रतिशत से अधिक राशि अगर कम जाती है तो पूरी की पूरी राशि पहले ठेकेदार जमा करवाये और उसके बाद में वह कार्य प्रारम्भ करवाये, तभी हमारे वह काम हो पायेंगे, अन्यथा हमारी सरकार की उपलब्धियां हम नहीं बता पायेंगे हमारे कार्यकाल के अन्दर। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बात करें।

दूसरी बात शराब की कहूंगा। मेरे यहां कई गांवों के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शराबबन्दी होनी चाहिये, हम इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इसके लिये विधान सभा में भी अपनी बात को रखूंगा। लेकिन मैं इतना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जहां शराबबन्दी हुई है बिहार हो, चाहे गुजरात हो, उनका भी हमें सोचना होगा कि वहां पर किस तरह से क्या हालात हैं, यह मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शराब के जो अधिकृत दुकानदार हैं, उन दुकानदारों पर से बाध्यता हटायी जाये कि इतनी शराब तो उठानी ही पड़ेगी। वह बाध्यता हटनी चाहिये अन्यथा ऐसी परिस्थिति में वह कम दर में भी शराब बेचते हैं और शराब की बिक्री बढ़ने से हालात बिगड़ जाते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके

(श्री खुशवीरसिंह)

लिये कुछ नीति बनाने के बारे में माननीय मंत्री महोदय, आपको विचार करना होगा, हमें बदलाव करना होगा।

दूसरी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एम.जी.एस.वाई. की कुछ सड़कें हैं, जिसकी 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है और केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देती है। लेकिन उन सड़कों का अभी तक भी नवीनीकरण नहीं हो पाया है। केन्द्र सरकार ने पता नहीं किस कारण से उसको रोक रखा है।

मैं इसके साथ ही कुछ हमारी विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार बिजली मीटर की रीडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, वे मनमर्जी से यूनिट लगाकर भेज देते हैं और बिल थमा देते हैं। उस परिस्थिति के अंदर उपभोक्ताओं को बार-बार ए.ईएन. आफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो उपभोक्ता है, उनको मजबूर और विवश होकर अधिक राशि के बिल भरने पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी मंत्री महोदय, आप गौर फरमाएं और इस व्यवस्था को किस तरह से सुधार सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो एक वक्तव्य दिया था 2016 में, कि चन्द मिनटों में हमारे ये जो नोट हैं, वे कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जायेंगे। वह टी.वी. न्यूज मैंने भी देखी थी। वह इसलिए किया है कि हम काला धन समाप्त कर देंगे, हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे और आज हालात यह हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि घर-घर नकली नोट छपने लग गये। रोज अख़बार देखते हैं, अख़बार के मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपती है कि जो युवा हैं आजकल के, वे प्रिण्टर से नकली नोट छापने लग गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो देश के अन्दर नैतिकता का पतन आया है, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। रोज अख़बार के अन्दर खबर पढ़ते हैं कि एक नाबालिग के साथ में बलात्कार हो गया है और उसके नीचे लिखा होता है कि पोर्न मूवी देखी जाती थी और पोर्न मूवी का आदी होने की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसके बारे में निवेदन है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं मेरे क्षेत्र की एक बात करना चाहता हूं। आज से छह माह पूर्व मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक ऐसी पोर्न मूवी बनाकर वायरल कर दिया और अपने आपको

(श्री खुशवीरसिंह)

वह बहुत बड़ा समझने लग गया। जब पुलिस को मैंने इत्तिला दी तो पुलिस वालों ने उससे सांठ-गांठ करके वहीं खतम कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरह से लोग जो अपना चेहरा दिखाकर ऐसी मूवी को जो वायरल करते हैं और समाज के अन्दर वह अपने आपको बड़ा समझने लगते हैं।

(समय: 14:45 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसके लिए पक्ष और विपक्ष को एक होना होगा और सख्त से सख्त कानून हमें बनाना होगा। यह जगजाहिर है, हम सभी जानते हैं, हमारे सबके मोबाइल के अन्दर इस तरह के मैसेज आते हैं। हम देखते हैं, लेकिन इसके बारे में सदन को सीरियसली लेकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी और इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपसे हमें उम्मीद की किरण नजर आती है कि उस लड़के ने मां और बेटी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सख्त कानून, कड़ा कानून बनना चाहिए। उस कानून के माध्यम से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तभी रीट की परीक्षा हो, इस तरीके के कुकर्मों की बात हो, चाहे किसी प्रकार की मिलावट की बात हो, बन्द हो सकेगी।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, जो कल्पना किसी ने की नहीं थी, वह साकार करके दिखायी है। जब किसान अकाल की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से जो लोन लेता है और वह नहीं जमा करा पाता है तो चंद रुपयों के लिये बैंक वाले पहुंच जाते हैं। उसके घर के सामने ढोल बजाते हैं। उसकी तौहीन करते हैं। उसकी बेइज्जती करते हैं। जिन लोगों के करोड़ों रुपये बकाया हैं, वे आज ऐशो-आराम कर रहे हैं। यह सोच हमारे गांधीवादी नेता अशोक गहलोत जी की है कि उन्होंने लघु और सीमान्त काश्तकारों के लिये कानून में तय कर दिया कि उनके विरुद्ध कुर्की नहीं हो सकती है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि आपने किसान से, आपने गरीब से, आपने उन लोगों से कभी धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने उन सीनियर सिटिजंस

(श्री खुशवीरसिंह)

के लिये, उन बुजुर्गों के लिये धार्मिक यात्रा नि:शुल्क कर दी, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो-जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, उनकी कल्पना से परे काम करके हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने दिखाया है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी मांग पर पिछली बार एसीएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट देसूरी और रानी में खुलवाया था। हमारे कृषि मंत्री जी ने और पशुपालन मंत्री जी ने पशुपालकों के लिये भी पशु केन्द्र खोलकर कई सौगातें दी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां जितने भी सब सेण्टर्स बने हैं, स्वास्थ्य विभाग के हों, पशुपालन के हों, इनमें पोस्टें खाली पड़ी हैं। उन पोस्टों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाये ताकि आम जन को हम उसका लाभ दिला पायें।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और कांग्रेस की तुलना टुकड़े-टुकड़े गैंग से कर डाली। हो सकता है उनकी सोच में सही हों। उनकी बात भी सही है कि आजादी से पूर्व यह देश टुकड़ों-टुकड़ों में बंटा हुआ था। इस देश को अगर किसी ने एक किया है तो इस कांग्रेस ने किया है। मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया के तहत जो हमारा भारत बंटा हुआ था, उसको आजाद कराने और एक करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। 51 प्रतिशत क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया अलग-अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था और 49 प्रतिशत क्षेत्र में देशी रियासतें थीं। मैं रियासतों के उन शासकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। वे उस 49 प्रतिशत क्षेत्र में स्वतंत्र थे। हर रूप से स्वतंत्र थे। उनकी मुद्रा थी। उनकी आर्मी थी। उनकी विदेश नीति थी। उसके बावजूद उन्होंने भी इस भारत निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। उस टुकड़े-टुकड़े भारत को एक या तो कांग्रेस ने किया है या उन रजवाड़ों ने किया है। उन रजवाड़ों की यूएनओ में मान्यता थी कि वह जहां चाहे वहां रह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा एक ही धर्म है और वह राष्ट्र धर्म है। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस राष्ट्र को कर दिया। मैं विपक्ष को और प्रधान मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि टुकड़ेटुकड़े भारत को एक करने का काम या तो उन देशी रजवाड़ों ने या हमारी इस महान कांग्रेस ने किया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो।

आज जिस तरह के हालात हैं, उनमें आप अलग-अलग राज्यों में बांटने की बात करते हो। भाषाओं के आधार पर इस देश को बांटने की बात

(श्री खुशवीरसिंह)

कर रहे हो। धर्म के आधार पर आप इस देश को बांटने की बात कर रहे हो। हमारी कांग्रेस ने कभी धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगा है। क्या सभी के वही ठेकेदार हैं? हम आस्थावान हैं।

सभापति महोदय, मैं आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्री जी को जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है। जो अब बजट आने वाला है, उसमें हमें जो सौगातें मिलेंगी उसका पूर्व आभास हमारे विपक्ष के साथियों को हो गया है। उनको पता चल गया है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपना पिटारा इस राजस्थान की गरीब जनता के लिए दिल खोलकर के खोलेंगे। किसानों के लिये, मजदूरों के लिये, जो क्षेत्र विकास से वंचित थे उनके विकास के लिये खोलेंगे। जितने भी प्रस्ताव मेरे क्षेत्र के थे, वे माननीय मुख्य मंत्री महोदय को समर्पित कर दिये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमारी सभी स्वीकृतियां करेंगे। मेरा निर्वाचन क्षेत्र आज जिले की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है जो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सड़कों की दृष्टि से हो, चाहे पेयजल की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र में सौगातें ही सौगातें दी हैं।

इस अवसर पर मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। एक मिनट विराजिये।

सभापति तालिका

जे.पी. चन्देलिया, श्री, सदस्य का सभापति तालिका के लिए मनोनयन

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सदस्य विधान सभा के स्थान पर श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य विधान सभा को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया है।

श्री गिरधारीलाल।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा रखे गये सरकार के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

बिन्दु संख्या 5 कोरोना महामारी में प्रदेश में कोरोना योद्धाओं ने बेहतर ढंग से काम किया। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मगर मैं सरकार का ध्यान कोरोना महामारी में फ्रण्ट लाइन पर रहकर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तरफ दिलाना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने फ्रण्ट लाइन वर्कर्स के लिए 5 लाख तक के बीमे का प्रावधान किया है। कोविड स्वास्थ्य सहायक जो फ्रण्ट लाइन पर रहकर काम करता है, उनके लिये एक रुपये बीमे का प्रावधान राजस्थान सरकार ने नहीं किया। हम आग्रह करेंगे कि सरकार कोविड स्वास्थ्य सहायकों को भी 5 लाख की बीमा राशि का कवर दे और इनको स्थाई किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कोविड प्रबन्धन में राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया लेकिन हमें केरल से सीख लेनी चाहिए। हैल्थ के क्षेत्र में कोरोना से लम्बे समय तक लड़ने में केरल को देश में एक नम्बर पर ला दिया। राजस्थान सरकार से भी आस और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रदेश में भी हमारे स्वास्थ्य तन्त्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 38, प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कैंसर, डायबिटीज आदि गम्भीर बीमारियों को शामिल करना बेहतर कदम है। किन्तु मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में 30 जनवरी, 2001 से आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतिम चरण में कैंसर, ल्यूकेमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों हेतु उपयोगी दवाइयों को आवश्यक दवाइयों की सूची से हटाया गया है।

सभापति महोदय, इससे पूर्व दवाई की एक डोज राजस्थान सरकार की तरफ से रोगियों को नि:शुल्क दी जाती थी। इस दवा को दवाइयों की सूची में से हटाने से कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित रोगी आर्थिक व मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। राजस्थान सरकार बड़ी चिन्तनशील

(श्री गिरधारीलाल)

है। इसकी ड्रिप बाजार में साढ़े 8 हजार रुपये से लेकर के 12 हजार रुपये तक में बिकती है।

(समय: 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में एक रास्ता दिखाया है। मेरा राजस्थान सरकार से यही अनुरोध है कि इस एल्मुकैंसर बीमारी की जीवन रक्षक दवाई निरीलोटिडियम को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान भारत राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय बीमा योजना में शामिल किया जाये ताकि प्रदेश के गरीब कैंसर मरीज अधिक से अधिक लाभ ले सकें, ये मैं सरकार से उम्मीद भी करता हूं और आस भी करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 75, सहकारी समितियों द्वारा किसानों ने जो लोन ले लिया है, उसका सरकार बीमा अभी नहीं करवा पायी है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी लोन लेने वाले किसानों का बीमा किया जाये। कृषि ऋण की राशि बढ़ा बिन्दु संख्या 116 तक, माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मनरेगा के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 221 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करे।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 163, मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन तो जरूर जारी किये हैं मगर वर्तमान में राजस्थान सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत रेट देश में सबसे ज्यादा है, जिससे आम आदमी की जेब पर अधिक भार पड़ता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि घरेलू बिजली दर पर थोड़ा सहानुभूति जताते हुए ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाये। सरकार ने उपभोक्ताओं को इस कोरोना महामारी में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं इसलिए घरेलू उपभोक्ता बिजली में भी सब्सिडी की व्यवस्था करे।

माननीय सभापति महोदय, पूरा राजस्थान और विशेषकर हमारा बीकानेर जिला, चाहे चूरू हो, कृषि में सामान्य, विशेष व बून्द-बून्द सिंचाई श्रेणी में कनेक्शन चाहने वाले किसानों ने आठ महीने पहले डिमाण्ड नोटिस जमा करवाये थे और आज भी वो कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। यह किसानों की सरकार है और नौजवानों की सरकार है और किसानों की बात को अति संवेदनशीलता से लेती है, बून्द-बून्द सिंचाई वाले कनेक्शनों को सामान्य कनेक्शन में बदलने के लिए बहुत सारे आन्दोलन चले, भाजपा सरकार के

(श्री गिरधारीलाल)

समय आन्दोलन के दबाव में उन्होंने एक कनेक्शन बून्द-बून्द सिंचाई कनेक्शन तीन साल में सामान्य कनेक्शन होता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं अगर इस अवधि को एक या दो साल या तुरन्त प्रभाव से कर देते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता धन्यवाद देगी और हमेशा के लिए याद रखेगी। भाजपा ने कहा था कि हमने सारे कनेक्शन सामान्य में कर दिये हैं लेकिन बून्द-बून्द श्रेणी कनेक्शन के लिए आज भी किसान को छत्तीस हजार रुपये का 9 महीने का बिल भरना पड़ता है। उस सूरत में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बून्द-बून्द श्रेणी कनेक्शनों पर विशेष तौर पर गौर किया जाये। हमारा क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जहां एक समय में एक खसरे में ट्यूब पम्प की योजना चली थी। हमारे इलाके में जब बीजेपी के राज में यह चलायी गयी थी, हमने विरोध भी किया था कि एक खसरे में ट्यूब पम्प केवल लोड बढ़ाकर करेंगे तो इसमें किसान ट्यूबवैल नहीं चला पायेगा लेकिन जहां पर पानी ऊपर है वहां पर यह योजना निश्चित रूप से सफल है पर बीकानेर, चूरू में इस योजना में जिसको दो साल हो गये हैं, एक खसरे में ट्यूब पम्प वालों को, अपनी सरकार को बजट के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कनेक्शन को, जो दो साल हो गये हैं, तीन साल हो गये हैं, उनको दो कनेक्शन मानते हुए एक अलग से ट्रांसफार्मर दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से यही आग्रह है कि बिन्दु संख्या 168, जल जीवन मिशन के तहत श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए पेयजल योजना स्वीकृत है। इस क्षेत्र में पीने के पानी के लिए मुख्य नहर से प्रोजेक्ट बनाया गया था। विशेषकर हमारे अति संवदेनशील मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना के लिए बैठक बुलाकर तमाम प्रतिभागियों से राय भी ली थी, 465 हैड से पानी की योजना बनी थी, वहां जमीन भी एक्वायर हो गयी फिर अब उसको कंवरसेन लिफ्ट योजना से जोड़ा जा रहा है। वहां पर पहले ही कम पड़ रहा है, वहां डूंगरगढ़ के 95 गांव हैं, लूणकरणसर के 12 गांव हैं, इस योजना को जोड़ने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुख्य नहर से जहां 465 से यह योजना शुरू की जा रही थी पीने के पानी की जल जीवन मिशन में, उसी पर विचार किया जाये अन्यथा वहां तो पहले से पानी की कमी है, 500 क्यूसेक्स पानी मिल रहा है तो पानी में और कमी आयेगी। इससे क्षेत्र के किसानों में रोष भी होगा इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह मेरा सरकार से आग्रह है।

(श्री गिरधारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, छोटी वितरिकाओं की वजह से वहां पर पानी की पहले से ही दिक्कत है, तो अभी जल जीवन मिशन योजना के इंजीनियर मलकीसर से पानी लेकर लिफ्ट योजना से कालू होते हुए 12 गांव डूंगरगढ़, लूणकरणसर के होते हुए ले रहे हैं। माननीय सभापति महोदय यहां पर पीने के पानी के लिए मुख्य नहर से पानी लाने की अच्छी योजना बनायी जायेगी तो आपको लम्बे समय तक याद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में देलवा से रादड़िया, सूरसर से मूणसर, बेरासर से अणकीसर, सादासर से सादनवासी, कई सड़कें मंजूर हुई हैं, कई बकाया हैं जिन पर आज तक काम चालू नहीं हुआ है। निश्चित रूप से मैं आस करता हूं कि बहुत सारी सड़कों के टेंडर हो गये विभाग की कमजोरी की वजह से अभी तक उन पर कार्य चालू नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान केन्द्र के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं, जैसा आज हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे, हल्ला मचा रहे थे सदन में, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट लेकर आयी है, वह पूरी तरह से गरीब, मजदूर, किसान, आम जन विरोधी है क्योंकि इस बजट में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में 25 हजार करोड़ रुपये यानी 25.5 प्रतिशत की कटौती की गयी है। ऐसी पहली बार पिछले बजट में हुई। गांव के गरीब को मिलने वाले पैसे में केन्द्र सरकार ने डाका डाला, जहां पूरे देश में समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद पर आन्दोलन चल रहा है। ग्यारह महीने किसानों ने आन्दोलन चलाया एमएसपी के लिए, तीन काले कानून सरकार लायी उसके लिए, वहीं केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की खरीद के माध्यम से 28.1 प्रतिशत भारी कटौती की है जबकि केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करनी की बात कर रही थी। जब दुबारा सरकार आयी तो कह रहे थे कि किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, किसान की लागत जो फसल की आती है आज भी लागत पूरी नहीं मिल पा रही है। 2014 से पहले केन्द्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री थे तो राजस्थान में हमारे इलाके में जितनी किसान फसल पैदा करता था वह सपोर्ट प्राइस पर पूरी खरीदी जाती थी, पर 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार केन्द्र में बनी तो मात्र 25 परसेंट, 100 क्विंटल फसल यदि होती है खेत के अन्दर तो 25 क्विंटल एमएसपी पर खरीद की जा रही है।

(श्री गिरधारीलाल)

आज हमारे बीकानेर जिले में हो, चाहे जोधपुर में हो, नागौर में हो, मात्र 25 क्विंटल के नाम से केन्द्र की मोदी सरकार आने के बाद किसानों के साथ कुठाराघात हुआ है, जबकि किसान की बात कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में किसानों को 6 हजार के हिसाब से 75 हजार करोड़ रुपये देने थे। इनके लिए सरकार ने मात्र 66 करोड़ रुपये का ही प्रावधान रखा है, जबकि 70 हजार करोड़ रुपये की कटौती केन्द्रीय सरकार ने इस बजट में की है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार ने वित्त वर्ष के लिए फसल बीमा योजना में 500 करोड़ रुपये की भारी कटौती की है। केन्द्र सरकार ने वर्तमान बजट में मछली पालन करने वाले किसानों के बजट में 26 हजार करोड़ की कटौती की है, यानी 18 प्रतिशत की भारी कटौती। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने खाद्य संचय और भण्डारण में 28 प्रतिशत की भारी कटौती की है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान घरेलू गैस सिलेंडरों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारी माताओं-बहनों की आंखें फूट रही हैं धुएं से, उन्हें कठिनाई हो रही है, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, मगर आज गैस सिलेंडर के दाम चौगुने हो गये हैं। गरीब आज भी घरों में चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो गैस का सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? केन्द्र सरकार की कुनीतियों के कारण आज गरीब के सामने ये हालात बन गये हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी में इस वित्त वर्ष में 60 प्रतिशत की कटौती की गयी है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की आमजन विरोधी नीतियों का परिणाम यह है कि देश में खेती में लगे किसानों की व्यक्तिगत आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन है। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने मजदूरों के लिए श्रम पोर्टल तो जारी किया, मगर उसमें एक भी रुपये का मजदूरों के लिए प्रावधान नहीं किया। आज तक एक रुपया नहीं आया इस पोर्टल के द्वारा, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया बजट देश के गरीब, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला बजट था। सभापति महोदय, केन्द्र की बीजेपी सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की, जिससे भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे पैसे वाली राजनीतिक पार्टी बन गयी।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, ध्यान देने योग्य है, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2020 में ही जो चन्दा भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने इकट्ठा किया है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सभापति महोदय, उस फंड में करीब 49 हजार करोड़ की राशि एकत्रित की गयी। भारत की सबसे धनवान पार्टी बन गयी। देश में कुल चन्दे का 70 परसेंट अकेली भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया और उस इलेक्टोरल फंड में एक नियम और डाल दिया कि कोई बता नहीं सकता कि किसका चन्दा आया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से आज देश का लोकतंत्र खतरे में है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और जगह दिलाना चाहता हूं। पी.एम. केयर्स फंड के तहत 10 हजार 990 करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये। मात्र 3 हजार 976 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उन्होंने पी.एम. केयर्स फंड के नाम पर पैसे इकट्ठे किये और राजनीतिक चुनाव लड़ने में लगाये। केन्द्र सरकार ने घोटालों का रिकार्ड बनाया है। एबीजी शिपयार्ड कम्पनी ने अकेले ही 22 हजार 842 करोड़ रुपये का घोटाला किया, जिसकी एफआईआर खुद केन्द्र सरकार ने पांच साल बाद दर्ज करवायी, जिसमें 28 बैंकों का पैसा लूटा गया। सात साल में कुल 5 लाख 35 हजार करोड़ के घोटाले केन्द्र की मोदी सरकार ने किये।

सभापति महोदय, बड़े पूंजीपतियों के 21 लाख करोड़ रुपये केन्द्र की मोदी सरकार ने एनपीए के तहत माफ किये। किसान लगातार आन्दोलन कर रहा है पर आज भी उसका एक भी पैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ नहीं किया गया है। सभापति महोदय, 11 महीनों तक किसानों का आन्दोलन चला और आज भी किसानों का आन्दोलन कुचलने का प्रयास करने वाला मिश्रा मंत्रिमण्डल में बना हुआ है। उसने चार दिन पहले धमकी दी थी कि मैं सिर्फ गृह मंत्री नहीं हूं, मैं पहले कुछ और भी था। आज भी वह मोदी सरकार के मंत्रिमण्डल में है। उन्होंने किसान आन्दोलन को कुचलने का काम किया। चार किसानों को कुचला, एक पत्रकार को कुचला और दस किसान घायल हुए। हमारी केन्द्र सरकार देशभक्ति के नाम से गुमराह कर रही है।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो राजनीति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश बांटने का काम कर रही है। आज हालात ऐसे हैं, जो भाई-भतीजावाद की बात करते हैं कि यह कांग्रेस भाई-भतीजावाद की पार्टी है, बीजेपी वाले बताएं, मैं बता देता हूं, आज

(श्री गिरधारीलाल)

भी कहीं भाई-भतीजावाद सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप कहीं भी जाकर देख लें। मैं नाम गिना सकता हूं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी है, वहां निश्चित रूप से सैकड़ों आदमी परिवारवाद से अछूते नहीं रहेंगे। जहां भी पिताजी को मिलेगा, वहां बेटे को मिलेगा।

राहुल गांधी जी ने कहा था, भारत दो भागों में है- एक गरीब, एक अमीर। दो भारत बसते हैं, मगर मीडिया के साथी, मीडिया के लोग उनकी अलग व्याख्या करते हैं। निश्चित रूप से पूरा संसार दो भागों में है- अमीर और गरीब। निश्चित रूप से उसकी व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। जो सच्ची बात कहता है, चाहे लुटियंस मीडिया हो, चाहे आरएसएस-बीजेपी का हो, सारे अलग तरीके से व्याख्या करते हैं।

सभापति महोदय, मैं अन्त में यही कहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारेंगे। इनकी बौखलाहट बता रही है। योगी जी कह रहे हैं, भोगी जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से इनकी राजस्थान में, जन हितैषी जहां स्कूल हैं, जहां गांव में गरीब बसते हैं, वहां जो स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बन्द कर दिये थे उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े पर निश्चित रूप से हमें खोलना चाहिए।

मेरे सुझाव में बिजली का मुद्दा सबसे ज्यादा है। लगातार गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जिनके कम लोड है उनके तो कुदरती ही कम है मगर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, चूरू जिलों में बड़े लोड हैं और उनमें 70 परसेंट से ज्यादा सब्सिडी अपनी गवर्नमेंट दे रही है, तो अगर इस बजट में विचार किया जाए कि जैसे पंजाब में कांग्रेस ने घोषणा की है वैसे आज इस आने वाले बजट में हम घोषणा करें कि हम किसान को जो वर्तमान में सब्सिडी दे रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सपने देख रहे हैं वे सपने ही रह जाएंगे। किसान, मजदूर, महिला, पीड़ित, दलित, शोषित की बात करते हैं और अगर निश्चित रूप से यह नीति लागू करेंगे तो लोग आशा करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देख चुके हैं। आप आज चाहे विरोध के नाम पर देख लो, चाहे बिजली के नाम पर देख लो, बिजली में इनके टाइम 2005 में 40 परसेंट रेट बढ़ायी थी, तब जयपुर में आठ दिन आन्दोलन चला था, उसके बाद में महारानी ने घरेलू भी बढ़ायी, और भी बढ़ायी मगर हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने आते ही कहा था कि हम किसान की बिजली के

(श्री गिरधारीलाल)

दाम नहीं बढ़ाएंगे, उसमें आज लगातार दूसरा पीरियड हो गया पर आज तक कृषि में बिजली के दाम नहीं बढ़ाये हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वह उसका उल्टा करती है, किसान की नहीं सोचती, मजदूर की नहीं सोचती, आम उपभोक्ता की नहीं सोची। ये निश्चित रूप से नारेबाजी करने में विश्वास रखते हैं, असत्य बोलने में विश्वास रखते हैं और इनका यही डैली का काम है।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यही कहूंगा कि गांवगांव में जहां पानी की जरूरत हो, हमारे क्षेत्र के कल्ला जी बैठे हैं, ये पीएचईडी मंत्री थे, सबसे ज्यादा मेरे इलाके में ट्यूबवैल स्वीकृत हुए हैं मगर वे धीमी गति से खुद रहे हैं। मंजूर तो आपने कर दिये मगर धीमी गति से खुद रहे हैं इसलिए बारबार वहां से फोन आता है कि पानी की दिक्कत है, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो आपने योजना लागू कर दी, पैसे दे दिये पर एक ठेकेदार की कमी की वजह से हमें उनकी बात सुननी पड़ रही है। अभी दो महीने पानी के हैं तो निश्चित रूप से पानी की कोई एमएलए मांग कर रहा है, जन-प्रतिनिधि मांग कर रहा है तो पानी की जरूरत के लिए सरकार से इस अभिभाषण के तहत आग्रह कर रहे हैं कि आने वाले बजट में वह व्यवस्था करे।

ऊर्जा मंत्री भाटी साहब आ गये हैं, हमारा इलाका एक ही है और बीकानेर जिले में आने वाले टाइम में ढाणियों में कनेक्शन देने की बात की थी बीजेपी गवर्नमेंट ने और जाते-जाते उन्होंने बन्द कर दिया। आज वहां डिमांड नोटिस जमा भी है और अब उनको वापस कह रहे हैं कि आप पैसे उठा लो पर वह किसान जो खेत में बैठा है, तो उसके लिए ऐसी योजना बनायें जिससे जो दूर-दराज आम किसान ढाणियों में बैठे हैं उनको कनेक्शन मिले जिससे उनके बच्चे पढ़ सकें, बच्चे अपनी शिक्षा ले सकें। इसलिए निश्चित रूप से आपसे बड़ी आशा है और यह लम्बे समय से मांग चल रही है विशेष रूप से भाटी जी के क्षेत्र में, गोविन्द राम जी के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, बीकानेर इलाके में, पूरे राजस्थान में कि अगर सिंगल फेज लाइट को एग्रीकल्चर से जोड़ दिया जाये तो आने वाले समय में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ रहने वाले प्रतिनिधियों और गवर्नमेंट को कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, पूरे इलाके का कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आने वाला रिजल्ट हमारे पक्ष में आयेगा अगर ये तीन-चार बातें लागू कर देते हैं और हम इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बजट में करेंगे तो।

(श्री गिरधारीलाल)

जहां पीएचसी खोलनी है, जहां सीएचसी खोलनी है वहां जैसा भी हो, जैसे मेरे क्षेत्र में अभी मात्र दो पीएचसी हैं जबकि बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में कम से कम एक पीएचसी तो इस कार्यकाल में निश्चित रूप से दें। पिछले समय में मुझे एक पीएचसी मिली थी। सीएचसी के लिए मैं पुन: जनता की मांग को देखते हुए इस बजट के माध्यम से मांग करूंगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देंगे।

अभी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय भी दिया, महाविद्यालय भी दिये हैं। अभी हमने एक दानदाता को तैयार किया है कि जमीन का एमओयू होना बाकी है, वह दानदाता बजट देने को तैयार है। अभी वहां पर ट्रोमा सेंटर की मांग चल रही है, गवर्नमेंट ने ट्रोमा सेंटर के लिए बात उठायी है और उस दानदाता का ट्रोमा सेंटर के जमीन देने के लिए भी एमओयू हुआ है और महाविद्यालय के लिए एमओयू साथ में हुआ है। जब भाटी जी उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उनसे मेरी बात भी हुई थी तो यह प्रगति पर है और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा, आपका है।

अब सिर्फ 22 महीने बचे हैं और ये बीजेपी वाले हल्ला करते रहेंगे, सीबीआई मांग करते रहेंगे पर ये तो यह चाहते हैं कि ये बच्चे नौकरी नहीं लगें और हम विरोध करेंगे और इनको तो ऐसा ही करना है। सरकार ने जिस गति से, तेजी से जो परीक्षा रद्द की है वह स्वागत योग्य है लेकिन जितनी जल्दी हो सके, जितना कम समय लगे, जांचें होती रहेंगी परन्तु परीक्षा कराने की व्यवस्था अपनी गवर्नमेंट करे जिससे निश्चित रूप से नौजवानों में, विद्यार्थियों में अलग सन्देश जायेगा। यह कहते हुए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

इस 56 पृष्ठ की किताब में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, गरीबों के हितैषी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा किये गये कामों का व्याख्यान है। माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल से पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिन्दुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड जिस कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जिनको राजस्थान की जनता ने तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने का मौका दिया, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

किस प्रकार बचाया जा सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए निरोगी राजस्थान का सपना देखा। निरोगी राजस्थान के तहत आज पूरे राजस्थान में, चाहे मेडिकल कालेज की बात करो, सीएचसी की बात करो, पीएचसी की बात करो, उप स्वास्थ्य केन्द्र की बात करो, नर्सिंग स्टाफ लगाने की बात करो, महिला चिकित्सक लगाने की बात करो या नि:शुल्क दवा देने की बात करो, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं राजस्थान में की हैं उसका न तो किसी मुख्य मंत्री ने सपना देखा होगा और न कोई मुख्य मंत्री इस प्रकार का सपना देख सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जो एक गरीब की पीड़ा को समझ सकते हैं, एक किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं, एक मजदूर की पीड़ा को समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि जिस परिवार में व्यक्ति बीमार होता है उस परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति टूट जाती है। जो 200-300 रुपये की मजदूरी करता है, अगर उसका बच्चा या उसकी बेटी या उसकी बहू आईसीयू में रखी जाती है तो 10 से 15 हजार रुपये रोज के उससे वसूल किये जाते हैं और उसके पूरे साल की जो कमाई होती है वह तीन दिन में खतम हो जाती है। इसी के तहत उन्होंने सपना देखा और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की। उस मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का उस परिवार में चाहे बच्चा हो या बहू हो, बेटी हो या बेटा हो, सबका इलाज करवाया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब कोराना महामारी आयी तब देश के प्रधान मंत्री को चिन्ता नहीं थी, राजस्थान के 25 सांसदों को चिन्ता नहीं थी। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री को चिन्ता थी कि मेरे आठ करोड़ लोगों को किस प्रकार बचाया जा सके और उन्होंने चाहे कोरोना की पहली लहर की बात करें, चाहे दूसरी लहर की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात करें, चाहे दवाइयों की बात करें या फिर कोरोना महामारी में जो अपने रोजगार को छोड़कर, अपने गांव में अपनी जान बचाने के लिए जाने वाले व्यक्ति को, जो अपनी बच्ची को कांख में लेकर, अपने बिस्तर को माथे पर रखकर बिना चप्पल के सड़कों पर चल रहा था, तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने कहा, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, आप सबकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान की सीमा से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात का हो, उसको यहां पर पैदल चलने नहीं दिया जायेगा और जिस एसडीएम कार्यालय के

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

अन्दर या जिस जिला कलेक्टर के अधीन अगर कोई व्यक्ति जो राहगीर है, अगर पैदल जाते हुए निकला तो उसकी जिम्मेदारी उस एसडीएम और कलेक्टर की होगी। इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें धर्म और जाति की कर सकते हैं, लेकिन उस महामारी में इनका न कोई सांसद नजर आया, न इनका कोई विधायक नजर आया, अगर वहां पर कोई काम कर रहा था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहा था, कांग्रेस का विधायक काम कर रहा था। इसलिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन साल में जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, 143 कालेज और बालिका कालेज खोले गये। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हमारे बच्चों के अन्दर संस्कार नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी तो उनका जीवन नारकीय हो जायेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अंग्रेजी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, जहां पर पांच हजार की पापुलेशन है और जहां पर दो स्कूल हैं, वहां पर एक स्कूल को इंग्लिश माध्यम से खोलने का काम किया और आज वह स्कूल संचालित है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करें या पेयजल की बात करें, सड़क की बात करें, हर जिले में बड़ी-बड़ी सड़कों की बात करें, राजस्थान में जिस प्रकार से लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपये नई सड़कें बनाने के लिए दिये, उसकी बात करें या जो सड़कें जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत की बात करें। कभी उन्होंने दिल को छोटा नहीं किया, जो विधायकों ने मांगा वह उन्होंने देने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार राजस्थान विधान सभा के बजट में देखा, चाहे वह नगरपालिका हो, नगर परिषद् हो, नगर निगम हो, वहां की जो जीर्ण-शीर्ण सड़कें हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए 5-5, 7-7, 8-8 करोड़ रुपये देकर उनको दुरुस्त कराने का कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया।

राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान में तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं और तीनों ही बार उन्होंने एक

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

चीज की है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चले, प्रशासन गांवों के संग अभियान चले। ये अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था, गांव की चौपाल पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, गांव में निवास करने वाले गरीब व्यक्ति को पट्टा मिले, गांव में निवास करने वाले व्यक्ति को पेंशन मिले, गांव में निवास करने वाला व्यक्ति जो लम्बे समय से सरकारी जमीन पर बैठा हुआ है, उसका नियमन हो, पेंशन मिले, उसको स्कूटी मिले, उसको साइकिल मिले और उसकी जो जमाबन्दी है, उसके खाते की दुरुस्ती का काम है, उसका जो खाते बंटवारे का काम है, वह सारा इस चौपाल पर बैठकर किया जाये और इसी के तहत उन्होंने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इस राजस्थान विधान सभा के पूर्व सदस्य और कोटा से आने वाले विधायक सम्माननीय राजावत जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं राजस्थान की विधान सभा में दो बार विधायक रहा हूं और वसुन्धरा जी के दो बार मुख्य मंत्री के कार्यकाल में भी विधायक रहा हूं, लेकिन सौभाग्य नहीं मिला कि मुझे पट्टा मिले, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब और स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी, जिन्होंने मुझे घर आकर मेरे मकान का पट्टा दिया, यह काम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में किया जा रहा है।

साथ ही, किसानों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस की यूपीए की पहली सरकार हो, चाहे यूपीए की दूसरी सरकार हो, जिसने हिन्दुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया और उसके बाद दूसरा कर्जा माफ करने का काम किया तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया।

सभापति महोदय, आपको कहते हुए शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजस्थान के आठ करोड़ लोगों ने हम 200 व्यक्तियों को यहां पर भेजा और इसलिए भेजा कि आप वहां बैठकर नौजवान को रोजगार देने की बात करें, आप वहां पर बैठकर किसान के उत्थान की बात करें, आप वहां पर बैठकर गांवों की सड़क बनाने की बात करें, आप वहां पर बैठकर गरीब का चूल्हा किस प्रकार चले इसकी बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, केन्द्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर केवल रीट को लेकर बैठे हुए हैं। उनको राजस्थान के आठ करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

चिन्ता नहीं है। उनको तो चिन्ता है, जो नरेन्द्र मोदी ने, अमित शाह ने और इनके जे.पी. नड्डा ने आदेश दिये, उसकी पालना यहां पर बैठकर करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको 2013 से 2018 के बारे में बताना चाहूंगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी थीं और जिस प्रकार से राजस्थान में चाहे भ्रष्टाचार का नंगा नाच चला हो, चाहे कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हो, जब ये उसी विधान सभा में मंत्रिमण्डल में बैठे हुए थे, तब इनका मुंह नहीं खुला, लेकिन आज तीन साल में राजस्थान में चाहे विकास की बात करें, नौजवान को रोजगार देने की बात करें या अन्य नि:शुल्क गेहूं देने की बात करें, ये सारे काम किसी ने किये हैं तो अशोक गहलोत ने किये हैं। अशोक गहलोत का सपना है कि राजस्थान के आठ करोड़ लोग हैं, उनमें कोई भी भूखा नहीं रहे और उसी के तहत इन्दिरा रसोई के माध्यम से उन्होंने हर नगरपालिका क्षेत्र में, हर नगर परिषद् क्षेत्र में, हर नगर निगम क्षेत्र में इन्दिरा रसोई चालू की है और वहां पर आठ रुपये में उस व्यक्ति को भरपूर पेट भर भोजन मिले और उसको किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये हैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कृषि की बात करें, पशुओं की बात करें, इन्सान वोट देता है, इन्सान के बारे में हर कोई सोच सकता है लेकिन पशु वोट नहीं देता, पशु के बारे में कोई नहीं सोच सकता है, लेकिन अगर पशुओं के बारे में सोचा है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सोचा है। उन्होंने लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा दवाइयां और जांचें पशुओं के लिए नि:शुल्क देने का प्रयास किया। साथ ही, जिन्होंने गौवंश के लिए अनुदान चालू किया, अशोक गहलोत जी पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने पिछले कार्यकाल में चालू किया था। जो 16 रुपये छोटे पशुओं पर मिलता था उसको अभी हाल ही में 20 रुपये किया गया और जो 32 रुपये बड़े पशुओं पर मिलता था उसको 40 रुपये किया गया। साथ ही, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दी गौशाला खोलने की जो घोषणा की, वह आने वाले समय में जब सार्थक रूप में होगी तो हमारे सामने नजर आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, श्मशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के निर्माण की कभी बात नहीं करते। आपने कहा था कि जब

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कहा था एक नये हिन्दुस्तान का निर्माण करना होगा, कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है, इस देश को बरबाद कर दिया है, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, पूछना चाहूंगा केन्द्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो 2014 से पहले की परिसम्पत्तियां हैं, चाहे रेलवे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, सड़कों की बात करें, बड़ी-बड़ी नहरों की बात करें, ये सारी सम्पत्तियां कांग्रेस ने बनाई हैं, जब 1947 में देश आजाद हुआ था इस देश में एक सुई नहीं बनती थी लेकिन 70 साल में जो विकास हुआ है वह कांग्रेस पार्टी ने किया और पिछले आठ साल में आपने केवल उन परिसम्पत्तियों को बेचने का काम किया है। जो बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, चाहे बड़ी-बड़ी नहरों का हो, चाहे बड़े-बड़े डैम की बात हो, बड़ी-बड़ी सड़कों की बात हो, रेलवे का विस्तार करने की बात हो, नौजवान को रोजगार देने की बात हो, ये सारे काम कांग्रेस ने किये थे और जो कांग्रेस ने चालू किये। आज आठ साल के अन्दर आप उन कामों के फीते काटने का काम कर रहे हो, लेकिन आपने कोई बड़ा काम नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन मिलती है।

(समय: 15.38 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

अभी कोरोना काल में हमारे परिजनों की, किसी की मौत हो गई है तो वह राजस्थान का लोकप्रिय मुख्य मंत्री है, जिसने कहा था कि कोरोना काल के अन्दर किसी की मौत हुई है तो उसको आर्थिक सहायता दी जायेगी। उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी, उसकी पत्नी को 1,500 रुपये पेंशन राजस्थान सरकार देगी, उसको सारी योजनाओं का लाभ देगी। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार ने केवल असत्य सपने दिखाने का काम किया है, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ देने का काम नहीं किया गया है और जब बजट पढ़ा जाता है तो टीवी पर डिबेट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता आते हैं और बजट में जो घोषणा होती है, उसको इस प्रकार से मुंगेरी लाल के सपने के रूप में दिखाया जाता है, जैसे यह सारा बजट हमारे लिये है लेकिन एक साल पूरा होने के बाद फिर दूसरी बार मुंगेरी लाल के सपने दिखाये जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो बिजली की व्यवस्था है, हमारे

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

लोकप्रिय मुख्य मंत्री जानते हैं, किसान खेती करता है और जब वह रात में खेत में जाता है, कड़कड़ाती सर्दी पड़ती है, पाणत करते हुए कभी उसको बिच्छू काटता है, कभी उसको सांप काटता है, कभी तेज सर्दी की वजह से उसकी मौत हो जाती है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सपना देखा कि मैं मेरे कार्यकाल में किसान को दिन में बिजली देने का काम करूंगा। वह काम करके राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने दिखाया। आने वाले समय में राजस्थान के किसान को रात में बिजली लेने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान बहुत मेहनत करता है और उसको बिजली सस्ती मिले, इसके लिए उसको हर महीने 1000 रुपये अनुदान देकर एक साल में 12,000 रुपये अनुदान देने का काम किया है, यह है राजस्थान का लोकप्रिय मुख्य मंत्री।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की बात करें, क्योंकि पेयजल एक महत्वपूर्ण चीज है, हम हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं और हमारे जिले में 618 किलोमीटर की नदियां बहकर निकलती हैं चाहे परवन हो, पार्वती हो, कालीसिंध हो। बरसात के समय में हमारे जिले में चारों तरफ बाढ़ होती है। राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री हमारे यहां से पांच बार सांसद रही हैं और उनका बेटा पांचवीं बार सांसद है और वह दो बार मुख्य मंत्री रही हैं लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह 618 किलोमीटर की नदियां बहती हैं, इनके एनीकट बनाये जायें, इनकी वृहद पेयजल योजनाएं बनाई जाएं लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को जब हमने हमारी पीड़ा बतायी कि हम हाड़ौती के उस जिले से आते हैं जहां से 618 किलोमीटर की नदियां बहती हैं, आप यहां पर एनीकट बनाइए, यहां पर बड़ी परियोजनाएं बनाएं तो आपने साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की परवन वृहद् सिंचाई योजना सैंक्शन की और आज उसका काम चल रहा है और उससे झालावाड़ जिला और कोटा जिला और बारां जिले के लगभग 18 गांवों को पेयजल मिलेगा और 800 गांव के लोगों को उससे सिंचाई एवं पेयजल मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारी चंबल नदी पर, हमारी कालीसिंध नदी पर, हमारी पार्वती नदी पर बड़े-बड़े एनीकटों का काम चल रहा है और मैं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जल जीवन मिशन योजना है यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इससे गांव में निवास करने वाले गरीब व्यक्तियों का

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

भला हो सकता है, क्योंकि आज के समय में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं इसलिये उनको उन बीमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये ताकि गांव में निवास करने वाला गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो उसको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा सकें। अभी तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वह बहुत धीमी है इसलिए मेरा सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: प्लीज कनक्लूड करिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): ...इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस योजना को व्यक्तिगत रूप से देखें, इसकी मॉनिटरिंग करें और हमारे कार्यकाल में ही इस योजना को पूरा करवाने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास इतना भण्डार है कहने के लिए क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 3 साल में ऐसा कोई काम विधायकों का नहीं छोड़ा है जो विधायकों को कहते हुए शर्म आती हो लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से उसको पीछे छुपा लेते हैं लेकिन उसको बोलने की उनकी क्षमता नहीं है जबकि राजस्थान की विधान सभा में लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब यहां पर बोलते हैं तो वह केवल कांग्रेस के विधायकों के लिए नहीं करते हैं, पूरे राजस्थान की विधान सभा के 200 सदस्यों के लिए करते हैं चाहे वह सड़क की बात हो, हैण्डपम्पों की बात हो, मोटर की बात हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य सुरक्षा मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका पोर्टल पिछले 3 साल से बंद है, उसमें गांव में निवास करने वाला व्यक्ति जो दिन भर मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई खेत में मजदूरी का काम करता है, आज भी उसमें उन व्यक्तियों का नाम नहीं है। मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि इस पोर्टल को जैसे-तैसे खुलवाकर जो पात्र लोग अभी छूटे हुए हैं उन पात्र लोगों के नाम उसमें जोड़े जाएं क्योंकि जो सरकार ने मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना लागू की है उसमें यह शर्त लगाई गई है कि वही व्यक्ति उसमें शामिल किये जायेंगे जिसको गेहूं मिलता है, जिसको पेंशन मिलती है, जो उस श्रेणी में आता है लेकिन वह बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है या झाड़ू लगाता है या गड्ढा खोदता है आज भी ऐसे कई हजारों लोग पूरे राजस्थान में से उस खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने स्कूटी योजना जो विकलांगों के लिए लागू की है, मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो टारगेट आपने दिया है वह बहुत कम है और विकलांग लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई 70% कई 80% है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो समाज कल्याण का बजट है उसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसा विकलांगों को स्कूटी देने में दिया जाए ताकि वह आपका गुणगान कर सके और आने वाले 2023 में अगर कोई आपका सबसे ज्यादा प्रचार करेगा तो वह विकलांग व्यक्ति करेगा क्योंकि वह बेचारा पैरों से चल नहीं पाता है, हाथों से खा नहीं पाता है, वह दूसरे के सहारे रहता है। वह एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता। वह घर से अस्पताल नहीं जा सकता। अगर आप उसको चलने का सहारा देंगे तो उसकी दुआएं आपके काम आयेंगी और 2023 में लगातार आप चौथी बार राजस्थान के मुख्य मंत्री बनेंगे, यह मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जब-जब भी कोई नयी योजना लाने का काम किया, उसको पूरे हिन्दुस्तान की जनता ने देखने का काम किया, उसी की नकल करने के लिए अन्य राज्यों के लोग यहां पर आकर उस पर शोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बात गरीब की नहीं है, बात मजदूर की नहीं है, बात नौजवान के रोजगार की नहीं है, बात लखपति आदमी की नहीं है या व्यापारी की बात नहीं है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के बारे में अगर कोई सोचता है तो वह राजस्थान का लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत सोचता है। कोरोना महामारी के दौरान जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने सोचा मजदूरी बंद हो चुकी है, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है तो उसके खाते में उन्होंने 5,500 रुपये कोरोना काल के दौरान डालकर उसका चूल्हा जलाने का काम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने वाले बहुत हैं, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, बोलने वाले आज सत्ता पक्ष के हैं, हमारा नंबर तो बहुत कम आता है वैसे भी।

श्री सभापति: बोलिये, प्लीज बोलिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, चाहे पंचायतों के पुनर्गठन करने की बात हो, नयी पंचायत समितियां बनाने की बात हो या नयी नगरपालिकायें बनाने का काम हो, यह कोई काम किया है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। आज जिन शहरों की पोपुलेशन 30-30 हजार थी, 40-40 हजार थी वहां पर 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतें हुआ करती थीं, आज वहां पर नगरपालिकायें बनाकर वहां के डवलपमेंट करने का कोई सपना देखा है तो वह राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने देखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी राजस्थान में 17 नगरपालिकायें बनायी हैं, मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा लेकिन वहां पर स्टाफ की कमी है चाहे वह सफाई कर्मचारी की बात हो या अन्य स्टाफ की बात हो, इसलिये आप बजट घोषणा में उन नगरपालिकाओं में बजट का प्रावधान करें नये पदों के लिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे बारां जिले की कुछ चीजें हैं जो मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहूंगा। मेरा बारां जिला, जिला मुख्यालय से मैं आता हूं, पूरे राजस्थान की नगर परिषदों में और नगर निगमों में टाउन हाल है या आडिटोरियम बने हुए हैं लेकिन मेरे बारां जिला मुख्यालय में नगर परिषद् होने के बाद भी, जिला मुख्यालय होने के बाद भी, वहां की लगभग पौने दो लाख की पोपुलेशन होने के बाद भी वहां पर ऐसा कोई आडिटोरियम या टाउन हाल नहीं है इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट की घोषणा में वहां पर एक आडिटोरियम की घोषणा की जाए।

साथ ही हमारा जो जिला है, जहां पर बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, चाहे अडानी की बात करो, मोतीपुरा तापीय बिजली घर की बात करो, एनटीपीसी अन्ता की बात करो, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है हाड़ौती में तो वह बारां जिले में होता है लेकिन वहां से जो लाइनें निकलती हैं उनसे कई खतरा होने की संभावना होती है, इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो लाइनें किसानों के खेतों से, मकानों के पास से निकलती हैं उनकी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि तार टूटने से जो दुर्घटनायें होती हैं उससे कोई जनहानि न हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले में एक और विधान सभा क्षेत्र है किशनगंज शाहबाद जहां पर लगभग 70% आदिवासी लोग रहते हैं और वह केवल राजस्थान में बारां जिले में रहते हैं, उनकी जो जीवनचर्या है वह

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

केवल खेती पर और वन पर ही निर्भर करती है। वहां पर विकास की इतनी अपार संभावनायें हैं कि वहां पर जो भी सरकार के द्वारा सड़कें घोषित की जाती हैं, चाहे वहां पर बिजली घर बनाया जाता है, 33 केवी ग्रिड का पावर हाउस बनाया जाता है, स्कूल खोले जाते हैं लेकिन वहां का 80% इलाका वन विभाग के अधीन आता है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे जिले में पूरे राजस्थान का 32% फोरेस्ट आता है और जब हमारी जो बड़ी योजनायें आती हैं तो उस फोरेस्ट की क्लीयरेंस के कारण हमारे जो काम सैंक्शन होते हैं वह रुक जाते हैं, इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकार की एक कार्ययोजना तैयार की जाये जो गांव को सड़क से जोड़ता हो, गांव में बिजली जाती हो या गांव में पेयजल की लाइन हो इन सारे कामों के लिये उस योजना के तहत क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं पड़े।

सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद और मैं राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हाकम अली जी।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो इस बार सरकार बनी है इस सरकार ने ऐसे कार्य किये हैं जो राजस्थान में पहली बार संपादित किये गये हैं। सरकार के कार्य ही बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेसी सरकार कितनी प्रतिबद्धता से प्रदेश का विकास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में बहुत सारे नवाचार किये गये, जिनमें कुछ के बारे में आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा।

महोदय, मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के खनन मजदूरों सहित अन्य मजदूरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में सोचते हुए प्रभावित क्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले नागरिकों के लिये जारी की गई सिलिकोसिस नीति से सिलिकोसिस रोग से पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए यह नीति लागू की गई। नई नीति से सिलिकोसिस पीड़ितों का पुनर्वास आसान होगा। हमारी सरकार ने आदिवासियों

(श्री हाकम अली खां)

की भावनाओं को ध्यान में रखकर राज्य में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जो सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राशन प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

महोदय, हमारी सरकार खेलों के प्रति भी बहुत सारे नवाचार कर रही है। इनमें राज्य में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का अभूतपूर्व आयोजन हुआ, जिसमें 18 खेलों में 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल, ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रदेश के लगभग 26 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे गांवों से प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी।

महोदय, हर आदमी का प्रथम प्रयास होता है कि पहला सुख निरोगी काया। इसके लिए शुद्ध वातावरण चाहिये। महोदय, विश्व व्यापी कोरोना जैसी महामारी के समय में जब हर आदमी शुद्ध वातावरण में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर औषधियों की व्यवस्था में लगे हुए थे, आवश्यकता हुई तो हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तथा सरकार ने आमजन को औषधीय पौधे उपलब्ध कराने हेतु घर-घर औषधि योजना की शुरुआत की, जिसके अन्तर्गत दूर-दराज गांव, ढाणियों में भी औषधीय गुणों से भरपूर पौधे उपलब्ध कराये गये तथा सबको इन औषधीय पौधों के गुणों के बारे में जागृत किया गया। इन पौधों से प्राप्त औषधियों ने हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही मनोबल भी बढ़ाया। पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए पहली बार जिला पर्यावरण योजना बनायी जाकर लागू की जा रही है।

महोदय, हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी संकल्पबद्ध है। महोदय, पहले राज्य कर्मचारियों को जहां मेडिकल बिल पास कराने के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, वहीं अब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु आरजीएचएस योजना प्रारम्भ की, जिसमें राज्य कर्मचारियों एवं अन्य को आरजीएचएस के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। अब इन्हें मेडिकल बिल पास कराने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। इससे इनकी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। यह सरकार का कार्मिकों को राहत प्रदान करने वाला कल्याणकारी सराहनीय कदम है। विशेष योग्यजन

(श्री हाकम अली खां)

कर्मचारियों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया, यह भी एक विशेष कार्य है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि के क्षेत्र में भी नवाचार के नये आयाम स्थापित किये हैं। सभापति महोदय, किसान को माई-बाप कहा जाता है। हमारा नारा 'जय जवान जय किसान' को सही मायने में साकार करने एवं किसानों के बेहतर भविष्य के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अन्नदाता के बेहतर भविष्य एवं उनके हितों की रक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में हमारी सरकार किसान हित को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी कृषि बजट पृथक से प्रस्तुत करने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के किसान भाइयों के हित में पहली बार कृषि बजट के साथ ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं और किसानों को सशक्त बनाने का काम किया है। यह सरकार का किसान हित में बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं स्वयं किसान होने के नाते राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

संवेदनशील गहलोत सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में 8 हजार 100 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये गये। साथ ही हमने गत भाजपा सरकार के समय से लम्बित 6 हजार करोड़ रुपये का भी भुगतान किया और कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किये। गत तीन वर्षों में 36 हजार 357 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन एवं 362 करोड़ 70 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये। किसानों को शोषण से मुक्ति हो और उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हर पंचायत मुख्यालय पर नई सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 418 पैक्स ग्राम, सेवा सहकारी समितियां एवं 45 लैमपस के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है जिससे किसानों को राहत मिली है। कृषि विद्युत कनेक्शन पर 5 वर्षों तक बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध हमारी किसान हितकारी सरकार ने लिया है। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है एवं राज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है।

(श्री हाकम अली खां)

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में 2,05,509 और प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में 16,142 बिजली समस्याओं का समाधान तत्काल मौके पर कर परिवादियों को राहत प्रदान की। वहीं हमारी सरकार किसानों को राहत स्वरूप कृषि कार्य हेतु दिन के उजाले में बिजली आपूर्ति करने हेतु प्रतिबद्ध है। महोदय, हमारे किसानों को इससे पहले कृषि कार्यों हेतु बिजली अधिकतर रात्रि के समय दी जाती रही है, जिसके कारण सर्द रात में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा कई बार किसान भाई रात के अंधेरे में जब पानी की लाइन बदलते हैं तब बिजली के करंट के चपेट में आने के साथ ही जहरीले जानवरों के डसने आदि से अनहोनी होने का खतरा भी बना रहता था। अब राज्य की गहलोत सरकार ने किसानों की समस्या व सुरक्षा को ध्यान में रखकर किसानों को दिन के दो ब्लाक में कृषि कार्य के लिए बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वर्तमान में प्रथम चरण में 16 जिलों के किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जा रही है तथा अन्य सभी जिलों को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में शामिल कर राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जायेगी।

महोदय, गत तीन वर्षों में 2 लाख 41 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये। किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बिजली के लिए 1,749 फीडरों के पृथक्कीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही गत तीन वर्ष में राज्य के किसानों को बिजली बिलों में 44 हजार 490 करोड़ का अनुदान देकर राहत प्रदान की, यह किसान हितैषी सरकार का एक सराहनीय कार्य है।

महोदय, राजस्थान में वर्ष 2020-21 में करीब 26 लाख फसल बीमा पालिसियों पर 3 हजार 518 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। कोरोना के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए समर्थन मूल्य पर रबी विपणन वर्ष 2021-22 में रिकार्ड 23 लाख 40 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर लगभग 2 लाख 27 हजार किसानों को राज्य सरकार ने लाभान्वित किया है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। महोदय, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन दो तहसील बनी हुई हैं, तहसील फतेहपुर एवं तहसील रामगढ़ शेखावाटी। इन दोनों तहसीलों की सीमाएं आपस में सटी हुई हैं तथा रामगढ़ तहसील में आने वाले कई गांव फतेहपुर तहसील मुख्यालय से महज 2 से 3

(श्री हाकम अली खां)

किलोमीटर की दूरी पर हैं। सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। जल स्रोतों की कमी के चलते यहां मुख्य रूप से किसान केवल खरीफ की फसल पर निर्भर रहते हैं तथा इसी से किसानों की रोजी रोटी चलती है। खरीफ फसल 2020 के समय 11 जून, 2020 से क्षेत्र में लगातार टिड्डी दल सक्रिय रहे, जिससे किसानों को काफी आर्थिक व मानसिक नुकसान झेलना पड़ा था एवं खरीफ फसल 2021 के समय मौसम में आये अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव व भारी अतिवृष्टि के कारण प्रदेशभर में खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ। इस समय विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर भी पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वहीं लगातार दो वर्षों में हुए आय के एक मात्र स्रोत खरीफ की फसल के खराबे ने किसानों को हताश कर दिया। सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता के कारण अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के कारण किसानों को अनुदान के रूप में राहत प्रदान करने हेतु सर्वे करवाया। राज्य सरकार द्वारा सर्वे करवाये जाने पर विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की एक तहसील फतेहपुर से फसल खराबे की रिपोर्ट प्रपत्र 7D में दर्ज कर सरकार को भिजवायी गई, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है परन्तु इसी क्षेत्र में आने वाली दूसरी तहसील रामगढ़ शेखावाटी में कार्मिकों की लापरवाही के चलते यहां फसल खराबे की रिपोर्ट प्रपत्र 7D में दर्ज नहीं की गई व कर्मचारियों ने कार्यभार से बचने के लिए राज्य सरकार को फसल खराबे की सही जानकारी नहीं दी, जिसके कारण क्षेत्र के किसान राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से वंचित रह जायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान हित में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की तहसील रामगढ़ शेखावाटी (सीकर) के किसानों को फसल खराबे की पुन: समीक्षा करवाकर किसानों को अनुदान देकर राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(समय: 16.00 बजे)

सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत प्रदान करने एवं पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 877 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जा चुके हैं। 166 पशु चिकित्सा उप-केन्द्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये गये हैं। समस्त 198 पशु औषधालय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये गये। वहीं सरकार ने पशुधन चिकित्सा के लिए सार्वजनिक उपयोग में आने वाली 120

(श्री हाकम अली खां)

तरह की दवाइयां व टीके पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना में अनुमोदित की है जिससे पशुपालकों को राहत मिलेगी व बेजुबान जानवरों को भी समय पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

सभापति महोदय, गोवंश के हित में भी हमारी सरकार ने गोशालाओं में संधारित गोवंश के लिए सहायता राशि की दर बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये व छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की गयी। पंजीकृत गोशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में वहन किए जाने का निर्णय किया गया। आधारभूत संरचना हेतु 75 गोशालाओं को 5 करोड़ 35 लाख रुपये आवंटित किये गये। हमारी सरकार ने राज्य के दलितों को, अल्पसंख्यकों को, हर वर्ग को कोरोना की मार झेल रहे आर्थिक कमजोर लोगों को भी जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया तथा इनके अधिकारों की रक्षा की। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। हमारी सरकार ने बाबा साहब के सामाजिक न्याय की अवधारणा को सच करने के लिए समाज के हर उस तबके के प्रोत्साहन और विकास पर विशेष ध्यान दिया है जो किन्हीं कारणों से मुख्य धारा से पीछे छूट चुके थे।

महोदय, कोरोना जैसी महामारी में अपनों को खोने का दर्द झेल रहे लोगों के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री वरदान साबित हुए। हमारी संवेदनशील सरकार ने मुख्य मंत्री कोरोना सहायता कोष योजना के तहत 97 करोड़ रुपये व्यय कर कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए 178 अनाथ बच्चों, 8609 विधवा महिलाओं तथा 5640 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इससे बालकों का वर्तमान व भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। हमारी सरकार कोरोना के पीड़ित परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने एवं उनके हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है।

भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की समानता और समता के सिद्धान्तों को अपनाते हुए प्रदेश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की गयीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की पेंशन दी गयी। मेरा सुझाव है कि माननीय विपक्ष के साथी चले गये, खाद्य सुरक्षा से बहुत सारे परिवार वंचित हैं। उन परिवारों को जोड़ने के लिए विपक्ष के

(श्री हाकम अली खां)

साथी 25 सांसदों से मांग करें कि भारत सरकार जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बन्द है, उसको चालू करे और जो वंचित परिवार हैं, उनको जोड़ा जाय। गांव व शहरों के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ें, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 चलाया जिसके अन्तर्गत 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा गया एवं कोरोना काल में प्रभावित हुए राजकीय कार्य को भी इन अभियानों में लगे शिविरों के माध्यम से गति दी गयी।

पालनहार योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 395 करोड़ रुपये से 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों के सभी प्रकार के आनलाइन आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय विवरण जनाधार से वेब सर्विस के माध्यम से स्वत: सत्यापन होगा जिससे विद्यार्थियों को जगह-जगह नहीं जाना होगा तथा आनलाइन सत्यापन होने से पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही आवेदन पर कार्यवाही त्वरित होगी।

हमारी राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये से विकाष कोष का गठन किया। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 95 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान कर एक लाख से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है जो सरकार का सराहनीय कदम है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है। मदरसा बोर्ड का एक्ट बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना, 2021 तीन चरणों में लागू कर प्रथम चरण में 5 हजार 49 ऋणियों को 40 करोड़ 33 लाख रुपये का ऋण माफ कर लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये से जनजाति विकास कोष का गठन किया गया है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कोरोना काल से प्रभावित हुए आमजन के अटके राज्य कार्यों को गति देने के लिए प्रदेशवासियों के हित में वृहत् स्तर पर प्रशासन गांव के संग व शहरों के संग अभियान चलाए जिससे

(श्री हाकम अली खां)

प्रदेशवासियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। गांव के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें इसलिए हमारी सरकार ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कैम्प लगाकर सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को एक छत के नीचे लाकर उनके पास भेजा व उनके सभी प्रकार के कार्य उसी कैम्प में मौके पर ही सम्पादित कर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को राहत प्रदान की।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, ग्रामीण इलाकों में आवासीय पट्टों के मामलों में ग्रामीणों को वर्षों इन्तजार करना पड़ता था। हमारी लोकप्रिय सरकार श्री अशोक जी गहलोत की सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान सफलतापूर्वक संचालित कर प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक पट्टे जारी किये गये। इससे ग्रामीणों को राहत मिली। पंचायती राज को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है।

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में 390 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय कर 7,515 कार्य किये गये। शहरों के दूर-दराज से आकर काम करने वाले और इसी तरह के जरूरतमंद लोगों को सस्ता भोजन और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए, कोई भूखा न सोये की सोच के साथ हमारी सरकार ने इन्दिरा रसोई योजना शुरू की जिसके तहत प्रदेश में 358 रसोइयों के माध्यम से प्रति थाली 8 रुपये की दर से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें राजकीय अनुदान 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली किया गया है। इन्दिरा रसाई में अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क भोजन पैकेट वितरित किये गये।

श्री सभापति: प्लीज, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): दो मिनट का ही है साहब। कोई भूखा न सोये की सोच को साकार करने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा मार्च, 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। बी.पी.एल. स्टेट, बी.पी.एल. अंत्योदय के लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण किया जा चुका है।

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय, जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैली, जब इसकी सैकंड वेव आई तो पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी तब हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने राजस्थान के लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके साथ हमारी सरकार खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आई तब भी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हर जिला कलेक्टर, हर एस.डी.एम. को पाबन्द किया कि आप हर हास्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। जहां-जहां ऑक्सीजन के प्लांट हैं, चाहे अन्य स्टेट से लाना पड़े या अन्य जिलों में प्लांट हैं, वहां से दूसरे जिले में पहुंचाना पड़े, पूरे राजस्थान में ये साबित कर दिया कि अगर अशोक गहलोत नहीं होता तो शायद ऑक्सीजन की बहुत कमी होती। इसमें भारत सरकार ने एक भी सिलेंडर ऑक्सीजन का देने में, जबकि यहां पर जो ऑक्सीजन होता था उसमें से ही, जो अलवर में प्लांट है, उसमें ले जाकर अन्य स्टेट में वह भेजते थे। इसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, यातायात व्यवस्था सुगम बनाने तथा विकास कार्यों को सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया। सड़कें किसी प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छी सड़कों की वजह से निवेश आकर्षित होता है और आम आदमी का जीवन सुगम बनता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 16 हजार 935 करोड़ रुपये व्यय कर 5 हजार 794 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का निर्माण कर 860 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 4 हजार 689 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास व 28 हजार 548 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए हैं। वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये लागत से कार्य करवाने की दिशा में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 336 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक व 522 किलोमीटर लम्बाई में नॉन पेचेबल सड़कों के 1 हजार 487 कार्य राज्य सड़क निधि व नाबार्ड योजना में स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी अच्छा सड़कों का कार्य हुआ है।

महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत नये आयाम स्थापित किये हैं। शिक्षित समाज के रास्ते ही आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा का उजियारा

(श्री हाकम अली खां)

पहुंचाकर ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की गयी। अब तक खोले जा चुके अंग्रेजी माध्यम के 562 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में 86 हजार से अधिक नामांकन हो चुका है। वर्तमान सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पद भरने को विशेष प्राथमिकता दी है। अब तक 61 हजार 625 शिक्षकों को नवीन नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। साथ ही 60 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के परिणामस्वरूप राजकीय विद्यालयों के नामांकन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है।

मूक बधिर विद्यार्थियों हेतु राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय जयपुर में खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। जोधपुर में मूक बधिर महाविद्यालय खोला जा चुका है। महोदय, हमारी सरकार ने राज्य के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें आर्थिक सम्बल देने का प्रयास किया।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामलाल जी मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले तीन साल कोरोना महामारी के भयंकर संकट में गुजरे लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जिस प्रकार से काम किये हैं उसकी प्रशंसा राजस्थान की जनता ही नहीं, देश के प्रधान मंत्री जी ने भी की है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है क्योंकि जब एक तरफ पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा था तब दूसरी तरफ माननीय अशोक जी गहलोत साहब सभी जातियों, धर्म के मुखियाओं से, सभी पार्टियों से घंटों-घंटों बैठकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किस प्रकार से हम राजस्थान की जनता की सेवा कर सकें, इसको लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किए हैं, हम सबको पता है कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में माना गया है। राजस्थान की सब जगह नकल हुई है। आज आपने देखा होगा एक तरफ राजस्थान के मुख्य मंत्री जी संकल्प लेते हैं कि कोरोना

(श्री रामलाल मीणा)

महामारी के अन्दर कोई भूखा नहीं सोये। दूसरी तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी घंटिया बजवाते हैं, तालियां बजवाते हैं। ऐसे काम करते हैं लेकिन आज घंटी और ताली के ऊपर ही रहते तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात हुए, नदी की बाढ़ आने के बाद पता चला कि कितनी लाशों के ढेर हुए हैं। यही हाल हमारा होता लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी की सूझबूझ और उनकी कठोर मेहनत से आज जगह-जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगे। रेमडेसीविर इंजेक्शन की व्यवस्था टाइम पर हुई और हर प्रकार की सुविधा मिलती रही। आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मेरे प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भी राजस्थान के ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों ने भी, क्योंकि बॉर्डर पर पड़ते हैं, आकर इलाज कराया क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को यह विश्वास हो गया कि राजस्थान के अन्दर अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी। हर जगह, हमारे जिला चिकित्सालय में भी चार से पांच ऑक्सीजन के प्लांट लगे। हरनोद के अन्दर ऑक्सीजन प्लांट लगा, छोटी सादड़ी और धरियावद के अन्दर तथा दलोट तक में आक्सीजन प्लांट की हमने व्यवस्था की और राजस्थान में कहीं भी कमी नहीं आने दी। कोई भूखा नहीं सोये उसके लिए घर-घर राशन पहुंचाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने करवाया है।

कोरोनाकाल में इन्दिरा रसोई नाम से चालू करके हर व्यक्ति को आठ रुपये में भोजन देने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। आज एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी खाद्य सुरक्षा स्कीम को बन्द करके बैठे हैं जबकि मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय राइट टू फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट लाये थे, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसको रोक दिया कि गरीबों को खाने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आप देख लीजिए। हर गरीब को बड़ी-बड़ी बीमारियां हो रही हैं। गरीब का इलाज कैसे हो। यह चिन्ता माननीय मुख्य मंत्री जी को है। उन्होंने पांच लाख रुपये तक इलाज की व्यवस्था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से की और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अन्दर शिविर लगाये जा रहे हैं और उनके अन्दर चिरंजीवी योजना को लेकर सारे डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है। कोई बीमारी हो तो बताइये। हम उसका इलाज करेंगे। जिला लेवल पर ऐसी सुविधा भी की गई है, जिस बीमारी का इलाज उन डाक्टर्स के पास नहीं है तो टेलीफोन से या अन्य

(श्री रामलाल मीणा)

डाक्टर्स से, जो प्रदेश स्तर पर बैठे हैं, उनसे राय लेकर भी दवाई लिखी जा रही है। आज नि:शुल्क दवा योजना को देख लीजिए। हमारे पूर्व शासन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया उस समय दवाइयों को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलायी गयीं कि इन दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे पड़ौसी डूंगरपुर के सांसद साहब ने ही कहा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की नि:शुल्क दवा योजना और चिरंजीवी योजना नहीं होती तो मेरा परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता। यह भारतीय जनता पार्टी के मुख से सुनने में आया है।

माननीय सभापति महोदय, आज हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो रखी, हर जगह खुल गये। तीन जगह ऐसे रह गये जहां मेडिकल कालेज नहीं खुल पाये। आज मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रतापगढ़ सहित तीन जगह मेडिकल कालेज खुलने से वंचित रह गये, बहुत जल्दी आप ध्यान दें, क्योंकि राजस्थान से 25 सांसद जीत कर गये लेकिन एक सांसद की केन्द्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे विधायकों की एक-एक बात को माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी तल्लीनता से सुनते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही भी करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की एक और खासियत है कि सत्तापक्ष की तो सुनते ही हैं, विपक्ष के भी कई विधायकों के काम उन्होंने बिना कहे कर दिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा दिल रखते हुए विपक्ष के विधायक के नाम से भी कन्या महाविद्यालय और कई प्रतिष्ठान खड़े किए हैं। यह हर कोई नहीं कर सकता है। आज मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिला कुछ समय पूर्व ही बना है इसलिए मेडिकल कालेज के साथ-साथ नर्सिंग कालेज की स्थापना भी वहां पर की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की आज से तीन साल पहले क्या स्थिति है और आज क्या स्थिति है। किसानों को दिन में लाइट देने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। पहली बार राजस्थान के अन्दर प्रतापगढ़ से ही प्रारम्भ हुई दिन में लाइट देना। किसानों को कड़ाके की ठण्ड में राहत प्रदान की। रात को 12 बजे फीडर आता था, रात को 04 बजे लाइट आती थी और किसानों को कड़ाके की ठण्ड में पाणत करनी पड़ती थी। कई किसान कड़ाके की ठण्ड में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कई

(श्री रामलाल मीणा)

जानवरों की मृत्यु हो जाती थी लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिन में लाइट करके हम सबके लिए बढ़िया काम किया। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि राजस्थान के किसानों को दिन में लाइट मिले। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, ऊर्जा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में दिन में लाइट की व्यवस्था की। कम से कम दस जीएसएस मेरे यहां बनकर तैयार हो चुके हैं। देश आजाद हुआ तब से अब तक जितने जीएसएस बने, उन सबको डबल कैपेसिटी का किया और 132 केवी दलोट और मौखमपुरा को तथा प्रतापगढ़ को भी डबल तिबल कैपेसिटी का किया जिसकी वजह से आज दिन में लाइट मिल रही है।

सभापति महोदय, जब मैं क्षेत्र में दौरे पर था, एक बुजुर्ग महिला हाथ में बिजली का बिल लेकर जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकिए। मुझे एक बार तो डर लगा कि माताजी क्या कह देंगी लेकिन मैंने पूछा माताजी, कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं बिजली का बिल भरने के लिए जा रही हूं। मैंने पूछा कितने रुपये का बिल आया। मुझे वह जानती नहीं थी कि मैं एमएलए हूं। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे तो 19 रुपये का बिल आया है। मैंने कहा फिर तो अगले महीने भर दीजिए। उन्होंने कहां, नहीं-नहीं बेटा, अशोक जी गहलोत साहब ने कहा है कि भले ही एक रुपया भी आये तो उसको उसी महीने भर देना वरना अगली बार माइनस जीरो नहीं आयेगा, माफ नहीं होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने प्रदेश के किसानों की हालत को समझते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए कभी बाढ़, कभी अतिवृष्टि को समझते हुए किसानों के बिजली के बिल को माफ करने के लिए किसान मित्र योजना लागू करके एक हजार रुपये माफ किये जिससे हजारों नहीं लाखों किसानों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, किसी के पांच रुपये आ रहे हैं। मेरे खुद के 60 रुपये बिजली का बिल आया एक कनेक्शन पर। दूसरे कनेक्शन पर तीन रुपये, चार रुपये बिजली का बिल आया। मैं जहां पर भी जाता हूं किसान माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हैं कि कितनी बढ़िया शानदार योजना लागू की लेकिन पहले एक समय ऐसा था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, बिजली के तारों में करंट नहीं आता था, बिजली के बिल के अन्दर करंट आता था। तीन हजार, चार हजार, पांच हजार रुपये किसान का बिजली का बिल आता था और एक बार नहीं, दूसरी बार अगर बिजली का बिल नहीं भरा, उस किसान का ट्रांसफार्मर

(श्री रामलाल मीणा)

उतारकर ले जाते और किसान की फसल जल जाती तथा उसको महीने दो महीने चक्कर काटने पड़ते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इन तीन साल के कार्यकाल के अन्दर एक भी किसान का ट्रांसफार्मर उतारकर बिजली विभाग के अधिकारी नहीं ले गये। और तो और जिन किसानों के ट्रांसफार्मर जले, 24 घंटे नहीं, 72 घंटे के अन्दर-अन्दर ट्रांसफार्मर किसान के घर तक दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक कनेक्शन की बात है, कनेक्शन भी बराबर तरीके से दिये जा रहे हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर सभी जगह कनेक्शन हुए और कुछ कनेक्शन कुछ ठेकेदार छोड़ कर चले गये थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने फिर आर्डर किए कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक भी मकान हो, उसके घर पर भी कनेक्शन होना चाहिए। कोई अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। आज ठेकेदार, बिजली के पोल, बिजली के तार लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं कि कहां-कहां बिजली के कनेक्शन बाकी रह गये हैं। बहुत जल्दी ही सभी जगह ये कनेक्शन भी हो जायेंगे।

जब केन्द्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमारे टीएसपी क्षेत्र में कई लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता था और भी कई गरीब क्षेत्र के लोग थे। मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको समय पर खाना उपलब्ध नहीं हो पाता था। उसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने एक रुपये प्रति किलो गेहूं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और पुनः गेहूं को कम किया गया। गेहूं को कम करने के बाद गेहूं के भाव बढ़ाये गये और गरीबों के साथ शोषण किया गया। जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने पदभार वापस ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही पुनः एक रुपये किलो गेहूं वापस स्टार्ट किये, आज इसकी प्रशंसा भी पूरे क्षेत्र में हो रही है। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को और राजस्थान के 25 के 25 सांसदों से निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो केन्द्र ने बन्द कर रखा है, उसको जल्दी से जल्दी से खोल दें ताकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त क्षेत्रों में जो खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्ति हैं, उनको जोड़ा जा सके।

टूटी सड़कें-जब कांग्रेस सरकार नहीं थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घटिया क्वालिटी की सड़कें बनी थीं और कई जगह पर सड़कें ही नहीं थीं। जगह-जगह पर गड्ढों के अम्बार थे और लोग परेशान थे।

(श्री रामलाल मीणा)

रास्ते इतने दूभर थे कि जाना ही कठिन था, लेकिन इन तीन सालों के कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में भी प्रतापगढ़ से पिपलौदा सड़क का काम चल रहा है, जो कि थोड़े दिनों के बाद पूरा हो जायेगा। प्रतापगढ़ से मंदसौर कमप्लीट हो गया है। प्रतापगढ़ से जाजरी रोड का काम चल रहा है। प्रतापगढ़ से धरिया रोड का काम कमप्लीट होने वाला है। गोतमेश्वर महादेव जैसे स्थान के चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है। उन्होंने कई एमडीआर बनायीं। इस बार भी हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दुबारा रिपीट हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे जल रहे हैं, लेकिन इस बार के बजट के अन्दर इतनी सड़कों का जाल बिछा दिया जाये कि एक भी गांव, एक भी ढाणी सड़कों से वंचित नहीं हो और किसी सड़क पर गड्ढा नहीं हो। इसलिए 23 तारीख को जो बजट आयेगा, उस बजट में भी हमें कई सारी सड़कें मिलेंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी-अभी कई सड़कें टूटी हुई हैं। दलोट से बड़ी सादड़ी होते हुए, आम्बीरामा से अमरगढ़ तक की जो सड़क है, उसके लिए काफी समय से लोगों की मांग थी, जोकि आज तक पूरी नहीं हो पायी है, लेकिन मुझे आशा है कि इस बार यह सड़क पूरी हो जायेगी। आज कुमारियों का पठार होते हुए लाम्बा काठा, भूरा काठा तक रोड रायपुर जंगल, मालियों का खेड़ा तक की, सागड़ों का खेड़ा तक रोड, गठिया कला तक की रोड। ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, उन सभी सड़कों को, पाल माण्डकला जैसी ग्राम पंचायतों को भी सड़कों से जोड़ने की कृपा करें। जोलर पंचायत के कालाखेत से लगाकर कोतवाल तक की रोड, दिवाक माता की रोड, इन सभी रोडों को माननीय मुख्य मंत्री जी जोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां रोकड़िया हनुमान जी हैं, वहां मानपुरा से जांचड़ी होते हुए खैपुर कुलताना होते हुए नंदातावा तक की सड़क, मौखमपुरा से डाबला होते हुए, मगरोड़ा होते हुए पिप्लू गादला से बुहासया तक की सड़क, लुहारिया-नकोर होते हुए, मदो-तलाब होते हुए वाया छोटी सादड़ी तक की सड़क।

श्री सभापति: प्लीज, कनक्लूड करिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): और भी सड़कें हैं, जिनके लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी लिखकर दे रखा है, वे सभी सड़कें उपलब्ध करायें।

(श्री रामलाल मीणा)

मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने जितने प्रस्ताव दिये, उन सभी पंचायतों में आपने पशु उप केन्द्र खोले हैं और कई उप केन्द्रों को पशु चिकित्सा केन्द्रों में स्वीकृत किया है। मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचायतें अभीभी बाकी रह गयी हैं, उनमें भी इस बार एक साथ पशु उप केन्द्र खोल दिये जायें, ताकि बढ़िया तरीके से क्षेत्रों का विकास होगा और पशुओं का भी ध्यान रखा जा सकेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न थानों के अन्दर स्वागत कक्ष स्थापित कराये और सभी थानों में स्वागत कक्ष बन भी गये हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो तो वह वहां सीधा जाकर मिल सकता है। पहले के शासन काल में बेवजह मुकदमे दर्ज किये जाते थे, आदिवासियों के ऊपर दारू के नाम पर मुकदमे दर्ज किये जाते थे और हमारा क्षेत्र अफीम काश्तकारों का क्षेत्र है। वहां असत्य मुकदमे दर्ज करके धारा-29 के अन्दर लोगों से पैसे लूटे जाते थे, लेकिन जिस दिन से राजस्थान की सरकार आयी है, तब से किसानों को दस-पन्द्रह लाख रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं तो एक केस में सौ-पचास लोगों की लाइन लगती थी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासन में उन किसानों से दस-पन्द्रह लाख रुपये लेकर उन किसानों को जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता था। आज न तो उन किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और न ही एनडीपीएस के गलत तरीके से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और न ही वसूली हो रही है और न ही आदिवासियों के ऊपर दारू के केस दर्ज हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इसके लिए बहुतबहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन से आपने कुर्सी संभाली है, उस दिन से आपने युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां की हैं। आप शिक्षक भर्ती को देख लें। आज माननीय सदस्य रीट को लेकर जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको जैसे ही पता चला कि रीट के अन्दर गड़बड़ी हुई है उसी समय डी.पी. जारोली को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का काम किया है। इनकी सरकार होती तो यह नहीं होता। इनके शासन काल में कई बार भर्तियां हुईं, कई बार घोटाले हुए, लेकिन ये बोल तक नहीं पाये थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने त्वरित प्रकार से कह

(श्री रामलाल मीणा)

दिया कि जिस-जिस ने गलत काम किया है, उसको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। कई लोग इनके भी आरोपी होंगे, इसलिए ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं, ताकि सीबीआई की मांग पूरी हो और भर्ती के जो घोटाले हैं, वे ठण्डे बस्ते में चले जायें और युवाओं के साथ शोषण होता रहे। आज किसलिये कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने रीट की भर्ती हो, आरएएस की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, सचिव की भर्ती हो, चाहे किसी की भी भर्ती हो, अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र तक जाने के लिए और वहां से वापस घर तक छोड़ने के लिए व्यवस्था की, वहां उनके खाने के लिए व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह सपना तक नहीं देखा होगा कि युवाओं के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था हो सकती है।

बेरोजगारी भत्ता - इन्होंने सपना तक नहीं देखा होगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा हैं। इंटर्नशिप योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने लागू कर दी। आज इतने बढ़िया तरीके से काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जनता को विधायक नहीं मिलते थे, विधायकों से मंत्री नहीं मिलते थे और मंत्रियों से मुख्य मंत्री जी का मिलना ही दूभर था। कई बार अखबारों में भी आता था, लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या किया? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार की एक-एक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम छोर तक बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए 'प्रशासन गांवों के संग' शिविर और 'प्रशासन शहरों के संग' शिविर लगाकर एक आम व्यक्ति की, एक आम नागरिक की एक-एक मांग और सदियों पुरानी जो समस्याएं थीं, उनको हल करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री श्री शान्ती धारीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शहर के अन्दर कन्वर्जन के मामले हों, पट्टे के मामले हों, परमिशन के मामले हों, कच्ची बस्ती के नियमितीकरण के मामले हों, उनको पट्टे देने की बात हो। ऐसी जो सारी उलझनें थीं, उन सबको 'प्रशासन शहरों के संग' शिविर में सुलझाकर आम लोगों को जो राहत प्रदान की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपने देखा होगा 'प्रशासन गांवों के संग' शिविर के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने घर का पट्टा बनाने के लिए पटवारी और सचिव के कई चक्कर काटते थे। पेंशन के लिए चक्कर काटते थे। कनेक्शन के लिए चक्कर

(श्री रामलाल मीणा)

काटते थे। मकान के लिए चक्कर काटते थे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'प्रशासन गांवों के संग' शिविर लगाकर और सारे विभागों के अधिकारी उस पंचायत में भेजकर लम्बे समय से जो लोगों की समस्याएं थीं, उन सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। मैं हर शिविर में गया और शिविर में देखा कि किसी पंचायत में सात सौ पट्टे बंट रहे हैं, किसी पंचायत में इतनी पेंशन हो रही है, किसी पंचायत में पालनहार योजना के फार्म भरे जा रहे हैं और स्वीकृत हो रहे हैं। मैं एक शिविर में गया था, एक व्यक्ति पेंशन के लिए सात साल से चक्कर काट रहा था, उसकी अंगुलियां नहीं आ रही थीं। उस दिन मैं जिद्द करके बैठ गया कि कलेक्टर साहब आज इसकी पेंशन होगी तब मैं जाऊंगा, उसी समय कलेक्टर साहब ने ऊपर बात की और रास्ता निकाला। दस मिनट में उस विकलांग की पेंशन हो गयी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कोरोना पाजीटिव होते हुए भी उन दीन-दुखियों की सुनी, उन गरीबों की सुनी, उन विकलांग लोगों की सुनी और गरीब जनता की सुनी तो आज कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर पा रहा है।

यह कोरोना आता ही नहीं, मोदी नमस्ते ट्रम्प नहीं करते, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में तल्लीन नहीं होते तो भारत के अन्दर कोरोना प्रवेश नहीं करता और यह भयंकर स्थिति भारत की जनता को झेलनी नहीं पड़ती।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिये। बोलने वालों की काफी लम्बी लिस्ट है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों का ऋण माफ करने का काम किया है। राहुल गांधी जी जब राजस्थान के अन्दर आये थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों का ऋण माफ किया जायेगा। किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया। केन्द्र में जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी, किसानों का ऋण माफ करने का कार्य किया है, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी जब से आये, किसानों की फूटी-कौड़ी तक माफ नहीं की है। एक तरफ नरेन्द्र मोदी जी बिना कहे तीन काले कानून लाकर जनता के ऊपर थोपना चाह रहे थे और उनके कई मंत्रियों ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि ये कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन क्या हुआ? आज उन मोदी जी और उन सारे मंत्रियों को थूक कर चाटना पड़ा और जनता के लोहे को मानना पड़ा और

(श्री रामलाल मीणा)

तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जब एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों का ऋण माफ कर रहे थे, किसानों की समस्या का समाधान कर रहे थे। जो फसलें नष्ट हो गयी थीं, उनका भुगतान कर रहे थे और उधर केन्द्रीय मंत्री के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे थे। कई किसानों की जानें गयीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यूपी के चुनाव आ गये, पांच राज्यों के चुनाव आ गये तो केन्द्र काले कानून वापस लेने की बात कर रही है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्र के कानून बनते ही, राजस्थान की विधान सभा में किसान हितैषी कानून आप लाए। किसानों की जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए, आपने यह काम किया, लेकिन राज्यपाल महोदय जी ने उस कानून को पास नहीं होने दिया। मैं राज्यपाल महोदय जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, जल्दी से वह तीनों कानून पारित हों।

आप आज पंचायती राज पुनर्गठन का मामला देख लीजिये। कितनी पंचायतों का गठन हुआ, राजस्थान में कितनी नई पंचायत समितियां बनीं, मेरे खुद के ज़िले में 70 नई पंचायतों का गठन हुआ। तीन-तीन नई पंचायत समितियां बनीं। राजस्थान में जैसे ही मुख्य मंत्री जी बने, कई जगह कालेज खोले। यहां तक घोषणा की कि हर उप खण्ड मुख्यालय पर कालेज होना चाहिये। सिर्फ मेरे अरनोद उप खण्ड मुख्यालय पर कालेज नहीं है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अरनोद उप खण्ड मुख्यालय पर भी एक कालेज हो।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा और की, जिसका आज तक किसी ने सपना तक नहीं देखा होगा। जिस स्कूल के अंदर 11वीं व 12वीं की 500 बच्चियां होंगी, उस स्कूल को डायरेक्ट कालेज कर दिया जाएगा। यह काम माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता।

आपने आज देखा होगा वनाधिकार पट्टे, पांच साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके एमएलए कहते रहे कि वनाधिकार पट्टे तो जब मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार का काम था, इसलिए अपने को एक पट्टा नहीं देना, नहीं तो कांग्रेस का नाम हो जाएगा। कोई पट्टा नहीं दिया गया। जैसे ही राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब, वापस सत्ता में आए, एक आर्डर से उन्होंने कह दिया कि आदिवासी

(श्री रामलाल मीणा)

क्षेत्र में जो भी किसान जंगलों में विराज रहा है, खेती कर रहा है, उनको वनाधिकार पट्टे मिलने चाहिये। काग़ज़ों के लिए वह ज्यादा चक्कर नहीं काटे, इसलिए ई-मित्र पर ऑनलाइन पट्टों की कार्यवाही कर दी जाये। अभी हज़ारों लोगों के पट्टे बन रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आपको आदिवासियों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा।

अँग्रेज़ी माध्यम के स्कूल। मैं शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब को आज बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के बच्चे तक का विचार किया। उनके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले, 70 हजार, 80 हजार या एक लाख रुपये की फीस देकर बच्चे को अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने व शिक्षा मंत्रीजी ने गांव-गांव में 5 हजार तक की आबादी के गांवों में अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की है। मैंने भी कई स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम के खुलवाये। एक अंग्रेज़ी माध्यम का स्कूल मैंने ग्रामीण क्षेत्र में खुलवा दिया। पहली बार देखा कि शहर के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पूछा कि आपके शहर में इतने अंग्रेज़ी माध्यम के प्राइवेट स्कूल हैं, आप अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में क्यों भेज रहे हो। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का ही दूरगामी सोच का परिणाम है, यहां स्कूल के अंदर जो टीचर लगे हुए हैं वह डिग्रीधारी, अनुभवी लगे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल में 5 हजार या 10 हजार का टीचर क्या पढ़ाएगा।

श्री सभापति: प्लीज, दो मिनट में कन्क्लूड कर दीजिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसलिए हम वहां पढ़ने भेज रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आई एम. शक्ति उड़ान, इसके लिए किसी ने विचार तक नहीं किया, सपना तक नहीं देखा कि एक महिला की क्या-क्या समस्याएं हैं। उनको कैसे दूर किया जा सकता है, महिला को गम्भीर बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। उड़ान योजना लागू करके नि:शुल्क सेनेटरी बांटने का काम किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

एकलव्य मॉडल स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र में, तहसील मुख्यालय पर, एकलव्य मॉडल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे, 700 बालक-बालिकाएं, एक साल वहां भर्ती होंगे, 12वीं तक

(श्री रामलाल मीणा)

अंग्रेजी माध्यम की स्कूल करके, खाना-पीना उनका वहीं होगा, उसके बाद वहां से जाएंगे। मेरे यहां भी नाथदवाड़ा के अंदर, पीपलखूंट के सुआपुरा के अंदर, धरियावद के पांचाकुड़ा के अंदर एकलव्य मॉडल के, अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खुले। छोटी सादड़ी, सुआपुरा व धमोत्तर पंचायत समिति व धोला पंचायत समिति के अंदर भी मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि एकलव्य मॉडल स्कूल खुले।

आज मेरे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की भी काफी आबादी है। अल्पसंख्यक आबादी के बच्चों के लिए एक भी कालेज, आवासीय विद्यालय, छात्रावास नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि बालक बालिकाओं के आवासीय विद्यालय या छात्रावास की व्यवस्था इस बजट के अंदर करें।

मेरे ज़िले में एससी की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। एससी का एक भी छात्रावास नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एससी के छात्रावास की घोषणा भी इस बजट में करें। गुर्जर, गायरी, रैबारी, एमबीसी से, देवनारायण बोर्ड से मेरे यहां आवासीय विद्यालय खुले, वहां काफी संख्या में गुर्जर, लवाणा, गायरी समाज के लोग हैं, उनके लिए भी यह सुविधा हो सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, हम खड्ढ़ा खोदकर पानी पीते थे, आज कई जगह घर-घर नल कनेक्शन हुए हैं। केन्द्र ने तो यह देखा होगा कि हम ज्यादा पैसा राज्य सरकार पर छोड़ दें, ताकि यह काम नहीं कर सके। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि इस योजना में जितना पैसा मुझे लगाना पड़े, राज्य सरकार से लगाऊंगा, लेकिन एक-एक व्यक्ति के घर तक नल कनेक्शन होना चाहिये। आज मेरे 58 गांवों के अंदर नल कनेक्शन के लिए बड़ी-बड़ी टंकियां बन रही हैं। कई जगह तो कनेक्शन भी चालू हो गये। कई जगह बड़ी-बड़ी टंकियां बन रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों में और धमोत्तर पंचायत समिति के सभी गांवों में घर-घर नल कनेक्शन हो। जाखम की योजना से पानी आये। सारा पानी एक-एक घर तक पहुंचे, ताकि किसी भी माता-बहन को सिर पर मटका लेकर नहीं जाना पड़े।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे भंवर सेमला बांध की नहरों का काम भी किया। मेरे छोटे-मोटे बहुत सारे बांध बाकी रह गये हैं, मोकाटेक डैम, देवतगाडिया बांध, अमृत्यावाजी बांध, सवण्या, बांध, ऐसे कई सारे बांध हैं, जिनको मैंने लिखित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को दे रखा है, इस बजट में करने की कृपा करें।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी, जैसे ही पद पर बैठे, कहा कि नरेगा योजना तो खड्ढ़ा खोदने की स्कीम है, इसको बन्द कर दिया जाये। उनको यह पता नहीं था कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन गरीब लोगों की तरफ देखा, जिनके लिए कोई रोजगार नहीं है, इसलिए राइट टू...

श्री सभापति: एम्प्लायमेंट।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): राइट टू एम्प्लायमेंट जो कानून लाए हैं, उस कानून के अंदर देखा कि यह तो कानून बना हुआ है, वह बन्द नहीं कर पाए। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मजदूरों को 70-80 रुपये मिलते थे, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक योजना लागू की "पूरा काम पूरा दाम"। उसके मार्फत आज मज़दूरों को 200-220 रुपये तक पूरी मजदूरी मिल रही है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा योजना के अन्तर्गत कई स्थाई काम हो रहे हैं। आज टीकाकरण का मामला भी देख लीजिये, टीकाकरण प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे टाप पर रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य महोदय, थैंक यू।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रतापगढ़ में सुपर "ए" क्लास मण्डी थी, कई जगह जाम लग जाते थे, लेकिन मण्डी के नाम पर और दस बीघा जमीन, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और मंत्रीजी ने करके प्रतापगढ़वासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी कल-परसों के अख़बार में एक बात छपी थी, जिसमें हमारे सांसद साहब कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ का रेल मंत्री हो जाए, तो भी प्रतापगढ़ में रेल नहीं आएगी। मैं प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता को कहना चाहूंगा और राजस्थान की सभी जनता को कहना चाहूंगा कि 25 सांसद आपने जिता कर तो भेज दिये, लेकिन किस सांसद ने आपके क्षेत्र की क्या मांग रखी, यह हिसाब भी उनसे पूछिये। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि एक-एक

(श्री रामलाल मीणा)

सांसद गांव में जाकर ग्राम पंचायत गोद लेगा। आज जिन-जिन सांसदों ने पंचायतें गोद लीं, वह पंचायतें गोद की गोद में रह गई, अभी तक चलना नहीं सीखी, एक रुपये का काम उन क्षेत्रों में नहीं हुआ है। कहां गई स्मार्ट सिटी, कहां गये नरेन्द्र मोदी जी के वादे, दो करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपये?

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुरेश टाक।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): धन्यवाद, साहब।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सर्वप्रथम राजस्थान के मुखिया, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह अभिभाषण राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया है, पर निश्चित रूप से यह सरकार का एक आईना है। इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह आईना सच बोल रहा है। यह आईना बिलकुल सच बोल रहा है। सरकार ने राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल में जो काम किये हैं, उन सब कामों का लेखा-जोखा। हम लोग उसके प्रत्यक्ष गवाह। राजस्थान की पूरी जनता इस बात को मन से स्वीकार करती है कि राजस्थान में कोरोना महामारी, पूरे भारत में कोरोना महामारी आई, उसके बाद राजस्थान स्टेट की रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ, उसके बाद भी किसी भी सूरत में राजस्थान के विकास की रफ्तार को कमजोर नहीं पड़ने दिया, यही एक सफल मैनेजमेंट था। जीवन बचाना और जीवनयापन कराना, इन दोनों कामों पर सरकार का फोकस था, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, राजस्थान की जनता यह बहुत अच्छी तरह से जानती है।

हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है जब पहली कोविड की लहर आयी थी, तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक विधायक के साथ, वन टू वन चर्चा करके राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, कैसे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और इस महामारी से बचने के लिए हमें क्या-क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी जनता सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इससे पूरे भारत में राजस्थान को एक रोल मॉडल के रूप में देखा गया और यह सारा श्रेय माननीय मुख्य मंत्रीजी के मैनेजमेंट को जाता है। उनका सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है, उस भाव को जाता है और यही कारण है कि

(श्री सुरेश टाक)

राजस्थान में आज भी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह और एक बहुत बड़ा विश्वास है कि हमारा मुखिया हमारे लिए सजग है, हमारे लिए प्रयत्नशील है और हमारे लिए सोचता है।

हमारे चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे रोटी का मामला हो या चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, कोई भी काम हो उसमें हर तरह से राजस्थान के मुख्य मंत्री का फोकस लगातार जमीनी स्तर पर है। मैं आज इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि हमें जो मार्गदर्शन मिला है, हम पहली बार के विधायक हैं और पहली बार जीतने के बाद एक ऐसे मुख्य मंत्री के पास काम करने का मौका मिला, जहां से हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। बहुत सारी स्थितियां बदलीं, बहुत सारे अलग-अलग काल-खण्ड आये लेकिन उन काल-खण्डों का बहुत ही मजबूती के साथ मुकाबला करते हुए केवल एक ध्येय रखा कि मेरा राजस्थान, मेरा परिवार और मैं उसका मुखिया और मुखिया होने के नाते जितना अच्छा कर सकते थे, उससे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। चाहे वह कोई भी सैक्टर था, चाहे वह शिक्षा थी, चाहे स्वास्थ्य था, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, हर सैक्टर में बहुआयामी परिणाम आये हैं। यह नहीं है कि केवल घोषणा ही हुई है, जमीन पर काम हुए हैं।

हम इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं क्योंकि मैं लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं वहां पर पार्षद भी रहा हूं, मैं सभापति भी रहा हूं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल संस्था है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, मैं उसका चेयरमैन दस साल रहा हूं तो मैंने बहुत नजदीक से राजनीति को देखा है और मैंने यह महसूस किया है कि जो काम इन तीन सालों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं, वह इतिहास बन गये। इतने बड़े काम, इतनी बड़ी सोच, ऐसे काम कभी भी नहीं हुए जो मैं खुलकर इस बात को बोल सकता हूं। मुझे पता है कि मेरे शहर की एक मात्र सड़क थी जो पिछले तीस सालों से कभी नहीं बनी और वह शहर की लाइफ लाइन है। उसके लिए मैं लगातार तीन सालों से बजट में मांग करता रहा और आखिर तीसरी साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरी बात को बहुत ही मन से सुना और मुझे 22 करोड़ रुपये मेरे शहर की उस सड़क के लिए दिये, जिसके लिए मेरा पूरा

(श्री सुरेश टाक)

शहर गदगद है, वह काम अभी चालू है और एक ऐसी सौगात मुझे मिली है, जिसकी मेरा शहर कल्पना भी नहीं कर सकता था।

यह एक बड़ी सोच की बात है कि वे सबको एक परिवार मानते हैं। हम सबको अपना एक अंग मानते हुए हमारी जो वाजिब जायज डिमांड थी, उस डिमांड को उन्होंने मूर्त रूप दिया और जमीन पर उतारा। वह ही नहीं, और भी कोई भी काम जो हमने जनता के विकास के लिए मांगा, आम जनता की राय पर, आम जनता की समस्या को लेकर हमने रखा तो उस समस्या का समाधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही त्वरित गति से किया है इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे छोटे-छोटे निवेदन को स्वीकार करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान की।

इस महामारी के दौर में जब पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा भारत जूझ रहा था, लॉकडाउन में प्रदेश में राजस्व की आय भी घट गयी थी, तब आपके कुशल नेतृत्व में इस सरकार ने चाहे वह मजदूर था, चाहे हमारा प्रवासी मजदूर था, चाहे वह कोई भी था, हर सैक्टर पर ध्यान दिया, हर व्यक्ति पर ध्यान दिया, उसको पैदल नहीं चलने दिया, उसको भूखा नहीं सोने दिया। सबसे पहले 'राजस्थान सतर्क है', इस बात पर फोकस करते हुए वास्तव में राजस्थान को सतर्क किया और राजस्थान सतर्क का नतीजा यह था कि तीसरी लहर में हमारे राजस्थान का कुछ नहीं बिगड़ने दिया और आज हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और तीसरी लहर करीब-करीब समाप्त होने जा रही है, यह एक कोरोना के बेहतर मैनेजमेंट की वजह से ही सम्भव हो पाया कि हमने हर स्टेप पर फोकस किया और हर स्टेप पर फोकस करने के बाद ही यह नतीजे आये हैं कि हम आज सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं।

रेवेन्यू भले ही घटी है लेकिन राजस्थान के विकास की रफ्तार कभी कम नहीं हुई है। चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे पीने के पानी का काम हो, हर काम में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। हर बार हर बजट में, बहुत एक्स्ट्रा आर्डिनरी बजट आया है और इस बार भी जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन बजट पेश किये, उन तीनों बजट में बढ़-चढ़कर जैसा बजट आता गया है, पूरी राजस्थान की जनता आशान्वित है इस बात को लेकर कि यह चौथा बजट जो आयेगा, वह राजस्थान को एक नयी दिशा देगा, एक नया रूप देगा

(श्री सुरेश टाक)

और वास्तव में हम एक नया राजस्थान बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसा हमारा ही नहीं, पूरी राजस्थान की जनता का विश्वास है और यह होगा भी, यह हमें पता भी है कि यह होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर जो व्यक्ति काम करता है उसको पूरा पता रहता है और राजस्थान की जनता किस चीज से परेशान है, उस चीज का भी पूरा ज्ञान रहता है, हर चीज की मॉनिटरिंग करना, हर चीज की पूरी जानकारी लेना, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की आदत में रहा है और यही कारण रहा है कि ब्यूरोक्रेसी लगातार काम करती रही और इसी का नतीजा जमीन पर उतरा है और आज जनता के सामने बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, मैं इसको बहुत ही मजबूत शब्दों के साथ कह सकता हूं।

कोरोना काल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लोगों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ निराश्रित परिवारों को राहत पहुंचाने का भी बहुत बड़ा काम किया है। करीबन 5500 रुपये प्रत्येक परिवार को, 33 लाख परिवारों को यह पैसा मिला है और यह परिवार किस तरह से गदगद हैं, एक ऐसे समय में जब बहुत कठिन समय था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे परिजनों की अगर घर में किसी की डैथ भी हो गयी थी तो उसकी लाश को दाह संस्कार करने के लिए भी, हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थे, ऐसे समय में किसी परिवार का रोजी रोटी का सहारा बनना, उसको आर्थिक सहायता देना, यह एक बहुत बड़ा काम था और यह जो मुखिया होने का दायित्व निभाया है, इसके लिए भी राजस्थान की जनता बहुत-बहुत साधुवाद दे रही है।

इसके साथ-साथ, ऐसे संकट में प्रदेश में विकास की रफ्तार को कभी कम नहीं होने दिया और लगातार नयी-नयी सौगातें देते हुए राजस्थान को एक नयी दिशा प्रदान की। वह चाहे कोई भी काम हो, किसी भी तरह का नवाचार हो। जो नवाचार मैंने इस कार्यकाल में देखे, शायद मैंने कभी नहीं देखे। सबसे बड़ा नवाचार दूसरी लहर के बाद, जब स्थितियां बहुत बिगड़ गई थीं, हमने अपनो को, अपने परिजनों को, बहुतों को खोया और उसके बाद में जो बीमारियां आयीं तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, इलाज कहां से करायें?

एक सबसे बड़ी स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज प्रोग्राम के तहत जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आयी है, मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूं, सारा सदन भी प्रत्यक्षदर्शी है कि हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान में, मैंने तो कोई भी गांव, किसी भी पंचायत का कोई

(श्री सुरेश टाक)

कैम्प नहीं छोड़ा और हर कैम्प में मुझे यह बात लोगों ने बढ़-चढ़कर बतायी कि जो पांच लाख रुपये का बीमा सरकार ने किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच ने किया, वह जो पोस्ट कोविड के बाद में बीमारियां आयी थीं उसमें बहुत बड़ा जीवनदान लोगों को मिला। अगर यह पांच लाख रुपये का बीमा नहीं होता तो कई जानें और चली जातीं, लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते और आज अगर इलाज हो रहा है तो यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच का परिणाम है।

(समय: 16.47 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उनकी दूरगामी सोच थी, उनको यह अहसास था कि पोस्ट कोविड के बाद में बहुत बड़ी बीमारियां आयेंगी, लोगों के पास रोटी के पैसे नहीं हैं तो इलाज कहां से करवायेंगे? वे अपने परिजनों को मरते हुए, तड़पते हुए देखना नहीं चाहते थे और राजस्थान के हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मुखिया होने के नाते इस दर्द को समझा, इस पीड़ा को महसूस किया और समय आने से पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करके प्रदेश में एक ऐसा नवाचार स्थापित किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

अब बारी हम सबकी थी, हमारे नीचे वाले जन-प्रतिनिधि हैं, उनकी भी थी कि हम जनता को जाग्रत करें और इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाये। उन लोगों तक पहुंचाये ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद मिले और उनको यह महसूस हो कि उस व्यक्ति की वजह से हमारा बीमा हो गया और बीमे की वजह से हमारा घर का परिजन जिसका इलाज होना था, वह इलाज सरकार ने फ्री में पांच लाख रुपये तक का एक मुखिया का बीमा होने पर पूरे परिवार का इलाज पांच लाख रुपये तक का फ्री था। चाहे वह सरकारी अस्पताल हो, चाहे वह प्राइवेट अस्पताल हो, किसी भी तरह की बीमारियां, पहले 45 तरह की बीमारियां थीं, उसके बाद और बीमारियां भी इसमें जोड़ दी गयीं। अभी तो इस समय तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जिनको इसमें इन्वाल्व कर दिया गया है और बहुत आराम के साथ लोग दुआएं देते हुए इलाज करवा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा परिणाम भी देखने को मिला।

इसके साथ ही, प्रशासन गांवों के संग अभियान में दस लाख पट्टे बांटे गये, यह अपने आप में एक माइलस्टोन वर्क है। जिसकी बात करना, सपना

(श्री सुरेश टाक)

लेना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसको योजनाबद्ध तरीके से, एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया और इसमें जन प्रतिनिधियों की भूमिका रही, लोगों को इतनी खुशी मिली, पट्टे मिलने के बाद जो उनके चेहरे की रौनक देखने लायक थी क्योंकि हम लोग लगातार कैम्प्स में थे और हमने देखा है कि जब हम पट्टे बांट रहे होते हैं तो लोग कितने खुश होकर जा रहे थे। जिस आदमी को अपने घर के लिए परेशानियां हो रही थीं, उसको जब सरकार फ्री में पट्टा दे रही है, इससे बड़ा कोई काम नहीं था।

पट्टे के साथ-साथ जो पेंशन योजना का काम हुआ है, इन कैम्प्स में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा काम हुआ है। यह आम जन को पता भी नहीं था कि सरकार ने हमारे हितों के लिए कितनी योजनाएं बना रखी हैं, उन सब योजनाओं का, हम लोग जब जाते कैम्प्स में तो मैं तो विशेष तौर से मैंने तो पूरी, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, जितनी भी योजनाएं थीं, हमने सबका नोट बनाया और नोट बनाकर हमने कोशिश की हर कैम्प में लोगों को जागरूक करें और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे और मैं हर कैम्प में कम से कम दो-दो, तीन-तीन, चार-चार महिलाएं ऐसी होती थीं जिनको यह पता नहीं होता था कि वह विधवा है और उसको पालनहार योजना का फायदा मिलने वाला है। उन कैम्पों की वजह से उन विधवाओं के बच्चे आज पढ़ रहे हैं। उनको एक हजार रुपये प्रति बच्चा मिल रहा है। यह बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर यह कैम्प नहीं होते तो शायद यह योजनाएं घर-घर तक नहीं पहुंच पातीं।

एक सबसे बड़ा नवाचार 'प्रशासन शहरों के संग' में बहुत सारे पट्टे, बहुत सारे विद्युत के तार, जो घरों के ऊपर से निकल रहे थे। ऐसे छोटे-छोटे, जिनके लिये लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। 21 विभाग एक छत के नीचे बैठकर काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा विभाग बचा हो, जिसके लिये किसी व्यक्ति को कहीं चक्कर काटना पड़े। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है और इस नवाचार के बहुत बड़े सुपरिणाम सामने आये हैं। इससे लोगों को राहत मिली है।

तीसरी लहर में जब हम दूसरा कैम्प लगाने चले तो तीसरी लहर की वजह से वह कैम्प बन्द हो गये। पर मैं यह चाहूंगा कि इन कैम्पों को सरकार अनवरत जारी रखे। इन कैम्पों से ग्रामीण लोग इतने ज्यादा प्रसन्न हैं, इतने

(श्री सुरेश टाक)

ज्यादा खुश हैं और वह सरकार को बार-बार दुआएं दे रहे हैं कि हमें ऐसे कैम्प बार-बार मिलें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पहले कैम्प में लोगों तक इस तरह का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया, लोग आ नहीं पाये। लोगों ने कैम्पों को हल्के में लिया होगा, शायद नहीं आ पाये, पर अब उनको इस बात की आवश्यकता है। चाहे कैम्प लगे, चाहे आप जिला कलेक्टर को निर्देशित करायें कि चौपाल कार्यक्रम के तहत विधायक के साथ बैठकर तारीख तय करें और हर पंचायत हैड क्वार्टर पर एक चौपाल पूरे दिन की लगे, जिसमें सारे विभाग शामिल हों ताकि हम फिर एक बार गांवों के बीच में जायें और गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान में आये हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से या काम की धीमी गति होने की वजह से वह काम अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाये। शायद अगर यह चौपाल या 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान का अगर सैकण्ड फेज वापस चालू हो तो वह सारे काम, जो रजिस्टर्ड हुए हैं, वह सब जमीन पर उतर जाएंगे और सारे लोगों को वह सुविधाएं मिलेंगी, जो सरकार वास्तव में देना चाहती है। यह तभी सम्भव होगा, जब हम एक बार फिर वापस गांवों की तरफ रूख करेंगे और लोगों के जो बचे हुए काम हैं, पैंडिंग काम हैं, उन कामों को लोगों तक हम पहुचाएंगे।

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत नये आयाम स्थापित किये हैं। मैं पशु चिकित्सा मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने उनसे जो मांगा, वह उन्होंने हमें दिया। चाहे हमने पशु चिकित्सालय मांगा, चाहे पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किया, चाहे हमने स्टाफ मांगा, चाहे हमने भवन मांगा, चाहे किसान भवन मांगा, जो कुछ भी मांगा, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही मन के साथ उन्होंने काम दिया और निश्चित रूप से यह भी सरकार के लिये एक माइलस्टोन साबित हुआ। एक मंत्री, जिसने हमारी बात को सुना, हमारी पीड़ा को समझा और हमारे गांव के लोगों की समस्या को समझा और इतने पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत हुए इतने नये पशु चिकित्सा केन्द्र खुले, जिसकी वजह से हर गांव में पशुओं की चिकित्सा के लिये सुविधा उपलब्ध हो गयी। यह एक बहुत बड़ा काम था।

इसी के साथ, बिजली के क्षेत्र में सरकार ने एक अनूठा काम किया

(श्री सुरेश टाक)

है। ऊर्जा मंत्रीजी, अभी चले गये। मैं उनको कहना चाह रहा हूं। मैं मेरे अजमेर निगम की बात करता हूं कि अजमेर निगम 2,800 करोड़ रुपये के घाटे में था। लेकिन बेहतर मैनेजमेंट की वजह से आज 175 करोड़ का मुनाफा है। 2,800 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करने के बाद 175 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लेना, यह भी एक मैनेजमेंट की बात है और यह अधिकारियों पर सरकार का फोकस, अंकुश, डर या नतीजा देने का काम सबसे बड़ा अगर हुआ है तो रिजल्ट ओरियन्टेड काम होने की वजह से यह सब हुआ। आज चोरी रूकी है, छीजत रूकी है, पैंडेंसी कम हुई है, लोगों से रिकवरी बढ़ी है। यही कारण रहा है कि निगम का घाटा बिलकुल खतम होकर निगम मुनाफे में आ गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जब निगम मुनाफे में आयेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे किसान हैं, उनको बिजली की सुविधा ज्यादा उपलब्ध होगी।

एक सबसे बड़ा नवाचार अगर किया है तो वह यह था कि दिसम्बर, 2012 के बाद सामान्य श्रेणी के कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। पिछले 10-12 सालों से सामान्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने सदन में डिमाण्ड के समय यह बात रखी थी और बहुत मन से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस बात को सुना और तुरन्त उस पर संज्ञान लिया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल का कार्यकाल बढ़ा है और 2012 से 2013 की जो पैंडेंसी थी, उसको जीरो कर दिया गया। यह सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये एक बहुत बड़ी सौगात थी और उनको यह महसूस हुआ कि सरकार सभी को समान रूप से एक नजर से देखकर सभी श्रेणी के लोगों को, चाहे वह एस.सी. हो, एस.टी. हो, जनरल हो, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। यह एक बड़ा काम था। मैं इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी बात को मन से सुना और उस पर फोकस करते हुए राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान की।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के काम चालू कर दिये हैं। घरों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। यह भी एक प्राथमिक काम था और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जेजे.एम. अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। आपके निर्देशन में बहुत शानदार काम हो रहे हैं पर मेरा आपसे

(श्री सुरेश टाक)

एक निवेदन है कि आप सारे अधिकारियों के साथ दो या तीन महीने में एक बार, चाहे ऑनलाइन ले लें, चाहे सम्भाग स्तर की मीटिंग लें, पर छोटी मीटिंग लें ताकि विधायक उसमें उपलब्ध हो तो जो भी कोई छोटी-मोटी समस्या हो, तो उसका समाधान हो सके। वैसे आपका पत्र आया है हमारे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मंत्री जो बना और मंत्री बनते ही सबसे पहले चिन्ता इस बात की कर रहा है कि मुझे सुझाव मिले और वह सुझाव यह मिले कि मुझे और बेहतर तरीके से काम करना है, आप अपने सुझाव भेजिए। मैं इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करूंगा और यह चाहूंगा कि हम सब मिलकर इसी तरीके से अच्छे से काम करें जिससे राजस्थान सरकार के प्रति आमजन का विश्वास बढ़े और जो मेरा आग्रह था, वह यह था कि आप अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, पर अगर उसमें विधायक को भी शामिल कर लिया जाये तो जो छोटी-मोटी अड़चनें अगर कहीं आती हैं तो वह अड़चनें उसी समय समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अधिकारियों के साथ अगर विधायक बैठेंगे तो विधायक अपनी बात को कह पायेगा और विधायक आपके सामने अपनी बात को रखेगा तो अधिकारियों पर इस बात का बड़ा प्रभाव जायेगा और उनको लगेगा कि हम सब लोग काम की चिन्ता करते हैं और माननीय मंत्री महोदय विधायक के साथ बैठकर यह चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में जल प्रबन्धन का जो काम है, वह बहुत बेहतरीन तरीके से जमीन पर उतरे और जो सरकार की सोच है कि हम पीने का स्वच्छ पानी लोगों तक उपलब्ध करवायें, वह वास्तव में लोगों को स्वच्छ पानी मिले।

मेरा एक निवेदन और भी है कि मेरे किशनगढ़ में 11.6 एम.एल.डी. पानी की डिमाण्ड है, पर अभी हमें केवल 9 एम.एल.डी. पानी ही मिल रहा है। अब जब जे.जे.एम. आ जाएगी तो हमें 16 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता होगी तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें कि जब आप जे.जे.एम. दे रहे हैं तो पानी की उपलब्धता भी पूरी हो, नहीं तो यह स्कीम जमीन पर उतरने से पहले ही कहीं बेकार नहीं हो जाये। बिना पानी की उपलब्धता के जे.जे.एम. को सफल करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी है, अजमेर जिला सबसे पहला हक रखता है कि पहले अजमेर जिले को पूरा पानी मिले, उसके बाद दूसरे जिलों को मिले। अब जब जे.जे.एम. आ गयी है तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको बीसलपुर का पानी पहुंचाना है, तो हमारी जो पानी की कमी है, फिलहाल उस कमी को तो एक बार जितनी आवश्यकता है, उतना पूरा करायें अधिकारियों को बोलकर, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(श्री सुरेश टाक)

सड़कों के मामले में जो काम हुए हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्य मंत्री ने शहरी क्षेत्र में विधायकों को समान रूप से, कोई पार्टी नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सबको समान रूप से नगरपालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद् में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर की सड़कें दी हैं। यह पहली बार हुआ है। लोगों ने बहुत आश्चर्य किया कि एम.एल.ए. सड़क कैसे बना रहा है। एम.एल.ए. सड़क इसलिए बना रहा है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एम.एल.ए. को यह गिफ्ट दिया है कि आप शहर की जनता का भी ख्याल रखें। हमें शहर की भी चिन्ता करनी है और इसीलिए 20-20 किलोमीटर की, मेरे यहां नगर परिषद् है, मुझे 20 किलोमीटर सड़क मिली है। हम रोज उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को यह संदेश जा रहा है कि सरकार ने केवल नगर परिषद् या नगर निकाय के भरोसे शहरों को नहीं छोड़ रखा है। सरकार भी पूरा ध्यान रख रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि शहरों में सड़कों की स्थिति खराब नहीं हो। सड़कों की स्थिति अच्छी हो, इसलिए वह सहयोगी बनकर, सरकार ने अपनी तरफ से 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ का जो यह पैसा दिया है, यह एक मायना रखता है और यह एक बहुत बड़ी सोच के साथ दिया है और इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। पूरे राजस्थान को समभाव से देखते हुए, एक परिवार मानते हुए, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, सबको समान रूप से दिया और इसी तरह से पांच करोड़ की मिसिंग लिंक है, वह भी सभी को समान रूप से दिया है। यह एक बड़ा उदाहरण है कि हम यहां राजनीति करने नहीं आये हैं। वास्तव में यह संदेश जा रहा है कि हम राजनीति नहीं करने आये हैं और विकास की बात करने आये हैं।

श्री सभापति: एक मिनट विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय विधायक राजकुमार जी गौड़ के बोलने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय माननीय राजकुमार जी गौड़ का वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय माननीय राजकुमार जी गौड़ का वक्तव्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सड़कों में चाहे स्टेट हाईवे का मामला हो, चाहे आर.आई.डी.एफ. का मामला हो, इतना काम दे दिया है एक ही बार में, कि अभी तक शिलान्यास पूरे नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान की जनता इस बात को देख भी रही है और सब समझ भी रही है कि क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से काम हो रहे हैं। चाहे आर.यू.बी. का काम हो, चाहे आर.ओ.बी. का काम हो, इतने अनगिनत आर.यू.बी. दिये हैं, इतने अनगिनत आर.ओ.बी. दिये हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं, काम चल रहा है। उनके बहुत जल्दी ही लोकार्पण होंगे और बहुत जल्दी जनता के सामने आयेंगे।

(समय: 17.00 बजे)

बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी सरकार ने एक नया नवाचार किया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले हैं। यह एक नई सोच का परिणाम है। राजस्थान में 502 स्कूलें खुलना एक मायने रखता है। हमारे बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल पहली बार सरकार द्वारा खोले गये हैं। यह पहला नवाचार है। अंग्रेजी माध्यम से सरकार के स्कूलों में पढ़ाया जायेगा। धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। इस बजट में शायद और ज्यादा स्कूलें मिलने वाली हैं।

अब तो स्थिति यह हो गयी है कि एडमिशन के लिये लाइन लगानी पड़ रही है। लोग एप्रोच करवा रहे हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूल में हो, लेकिन जगह नहीं है। यह एक बहुत बड़ा काम है। ऐसी स्थिति पैदा होना भी अपने आपमें अभूतपूर्व है। ऐसी स्थिति है कि एडमिशन के लिये लोगों को इन्तजार करना पड़ रहा है। जैसा प्राइवेट स्कूलों में लोग करते थे वैसा सरकारी स्कूलों में करने लगे। ऐसा पहली बार हुआ। नये संकाय खोलने हों, नये सब्जेक्ट खोलने हों, स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, कहीं भी कोई कमी नहीं है। सभी तरफ से हर सेक्टर में सरकार ने पूरा ध्यान रखा है।

(श्री सुरेश टाक)

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक नया नवाचार किया है। अगर उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में, बारहवीं क्लास में 500 बच्चियां पढ़ रही हैं तो वहां बालिका कालेज खोल दिया जायेगा। यह भी कम बात नहीं है। यह घोषणा करना अपने आपमें महत्वपूर्ण है। इस घोषणा के बाद से सरकारी स्कूलों में बालिकाओं की संख्या बढ़ गयी है। हर कोई चाहता है कि हमारे यहां राजकीय बालिका महाविद्यालय खुले ताकि हमारी बेटियां ज्यादा पढ़ें। हमारी बेटियों की शिक्षा का स्तर बढ़े। उनको अपने घर के पास, अपने गांव में, अपने शहर में कालेज मिल जाये। अगर यह हो गया तो हमारी बच्चियां जो गांवों में स्कूल नहीं होने से दसवीं पढ़कर रह जाती थीं, आठवीं पढ़कर बंद कर देती हैं। शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि बालिका कालेज नहीं होने से पेरेन्ट्स को-एजुकेशन में नहीं पढ़ाते हैं। अगर बालिका कालेज अलग से हो गया तो हमारी बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने विवाह की उम्र को 18 से 21 किया है, वह यहां सार्थक होता दिख रहा है। 18 से 21 का जो समय है, यह भविष्य चुनने का समय होता है। बालिका को यह तय करना होता है कि उसे करना क्या है। लेकिन अगर शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण आयाम उसको मिलेगा, कालेज उसको अपने यहां मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी जो बालिकाएं हैं, वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाली हैं। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच का परिणाम है। यह जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, यह अपने आपमें बालिका शिक्षा को बेहतरीन करने का काम है।

इसी के साथ उद्योग विकास में भी कोई कमी नहीं रही है। मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं व्यापारी रहा हूं और10 साल तक मैंने ऐसी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी एसोसिएशन है। लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग या किसी भी तरह के उद्योग हैं, उनके लिये आपने इतने नये रीको इण्डस्ट्रियल एरिया खोलने का जो प्लान किया है, यह बेमिसाल है। आपने जितने भी अभी तक खोले हैं, मेरे हिसाब से 147 की आपने घोषणा की थी। 64 उपखण्डों पर नये रीको इण्डस्ट्रियल एरिये खुल गये हैं।

अभी हमारे यहां अजमेर माननीय मंत्री महोदया आई थीं। हमें अच्छा लगा। आपने सभी दलों के विधायकों को खुद, पर्सनली फोन करके बुलाया।

(श्री सुरेश टाक)

वहां के इण्डस्ट्रियलिस्ट को संदेश दिया कि हम सब मिलकर के काम करना चाहते हैं। हम सब मिलकर राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि जहां 64 उपखण्डों में रीको इण्डस्ट्रियल एरिये खुले हैं, आज आप मालूम कर लें, शायद वहां प्लाट नहीं हैं। वहां प्लाट कम पड़ रहे हैं। लोग इण्डस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे-छोटे सेक्टर में चाहे 200 गज का प्लाट, 500 गज का प्लाट, 1000 गज का प्लाट, 2000 गज का प्लाट, जिसको जितनी आवश्यकता है, उसको उतना प्लाट मिल रहा है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर डवलप्ड प्लाट मिल रहा है, जहां पूरी सड़कें, लाइट्स, बिजली, पानी सब कुछ मिल रहा है। जहां आपको अगर सब स्टेशन खोलना है, जीएसएस खोलना है, वह भी जगह है। यह सब सुविधायुक्त हैं। हर कोई रीको की तरफ बढ़ रहा है। यह नवाचार माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच का था कि एक साथ 167 उपखण्डों पर नये रीको इण्डस्ट्रियल एरियों को खोलना और वहां जमीन उपलब्ध कराकर लोगों को उद्योग लगाने के लिये आकर्षित करना, यह बहुत बड़ा काम है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करूंगा।

मैं मेरी बात को एक आखिरी बात कहकर के विराम दूंगा। मैं जितना बोलूंगा उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं किस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूं। जिस तरह से काम हो रहे हैं, वह मैं बोल भी नहीं सकता। यह सारा विधान सभा क्षेत्र के लोग बोलते हैं। लोगों का नजरिया बदल चुका है। लोग यह चाहते हैं कि काम इसी गति से होते रहें।

मैं एक निवेदन के साथ, एक आग्रह के साथ मेरी बात को समाप्त करुंगा। जेजेएम और पीडब्ल्यूडी 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भी पूरा ध्यान है। मैं जो बात पहले जेजेएम के लिये बोल रहा था, वही बात पीडब्ल्यूडी और जेजेएम दोनों को मिक्स करके बोल रहा हूं। यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंचे। माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं। आप भी सुन लें। संभाग स्तर पर हर बार अधिकारियों की बैठक में आप एमएलएज को भी शामिल करें। बिना मानिटरिंग के अभाव में दोनों विभागों के काम जितना आप चाह रहे हैं, जितना सरकार चाह रही है, जितना मुख्य मंत्री चाह रहे हैं, उसके अनुरूप नहीं हो पायेगा। मैं इस बात को खुद देख रहा हूं। मैं 20 सालों से लगातार इसी काम में हूं। मैंने इण्डस्ट्रियल एरिये को बिलकुल अलग्सा कर दिया। मैं

(श्री सुरेश टाक)

इसीलिए चाहता हूं कि विधायक को बीच में रखकर अगर पीडब्ल्यूडी के कामों की मानिटरिंग होगी तो जो अधिकारी मनमर्जी करते हैं, वह रुक जायेगी।

मैं इस बात का एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे यहां पर एक अधिकारी लगा है। उस अधिकारी के आने के बाद जितने काम चल रहे थे, उन कामों को बंद करने का प्रयास कर रहा है। यह बात हम कहां कहें? किस स्तर पर बोलें? हमें पता ही नहीं कि कहां बोलना है। अब जहां बोलेंगे वहां पर यह बात समझ में नहीं आयेगी। मैं हाउस में इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि संभाग स्तर पर हर 2 महीने या 3 महीने में विधायकों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जेजेएम के अधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग हो। उस मीटिंग में हर काम की मानिटरिंग हो। चाहे सरकार ने 2 करोड़ का काम दिया है, उसकी भी समीक्षा हो। तभी आपकी सोच जमीन पर उतर पायेगी। क्वालिटी के साथ काम होगा। गुणवत्ता के साथ काम होगा। जनता के बीच में एक बहुत बड़ा सन्देश जायेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजकुमार जी गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिये आपका धन्यवाद।

मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सभी विषयों पर बोला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोविड 19 के बावजूद भी गत 3 वर्षों में राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में काम किये हैं, उनकी सराहना केवल यहां सदन में बैठे हुए सदस्य नहीं कर रहे बल्कि आम पब्लिक इसकी सराहना कर रही है। गजब के काम इन 3 वर्षों में हुए हैं। 3 साल बेमिसाल, यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने करके दिखा दिया है।

अभिभाषण में सरकार द्वारा किये गये काम का उल्लेख है। सभी क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, उसको सभी लोग समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। कोविड में किस तरह से 2 साल निकले। किस तरह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राहि-त्राहि पूरे विश्व में मच गयी थी, परन्तु आज जिस तरह से कोविड होने के बावजूद भी राजस्थान में जो विकास के काम हुए हैं, उनकी आम आदमी कल्पना भी नहीं करता था।

(श्री राजकुमार गौड़)

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 473 ऑक्सीजन प्लांट लगाये गये। दवाइयां फ्री मिल रही हैं। लोग तीसरी लहर जब आयी थी, चिन्तित हो गये थे। लेकिन लोगों को माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत पर पूरा विश्वास था कि हमें बचाने वाले बैठे हैं। जिस तरह से तीसरी लहर पर इंतजाम किये गये, जिस तरह से गाइडलाइन दी गयी, उससे आज सब लोग सुरक्षित हैं। राजस्थान एक बार फिर विकास की पटरी पर तेजी से बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।

शिक्षा के क्षेत्र में बात करें। अंग्रेजी स्कूल जिस तरीके से खोले गये। आज हर गरीब आदमी सोचता है कि मैं अंग्रेजी स्कूल में मेरे बच्चे को पढ़ाऊं। पूर्व वक्ता ने निश्चित रूप से सही कहा कि आज ज्यादा अंग्रेजी स्कूलों को खोलने की आवश्यकता है। हर गांव में आदमी चाहता है। हर शहर में, मोहल्ले में आदमी चाहता है कि अंग्रेजी स्कूल खुलें। सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले और हम हमारे बच्चों को वहां शिक्षा दिलवा पायें। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले बजट में इस तरफ निश्चित रूप से काम होगा।

गत 4 दिनों से विपक्ष जिस तरह से अपना रूप दिखा रहा है, आम आदमी इन लोगों को समझ चुका है। हर आदमी इस बात को जान गया है कि 3 साल में आप विपक्ष में रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाये। 3 साल में आपने कोई काम नहीं किया। केन्द्र में आपके 25 एम.पी. बैठे थे। उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। केन्द्र का जो बजट आया, यह जानते थे कि इस बजट पर चर्चा करेंगे। इस बजट पर हर एमएलए बोलेगा कि केन्द्र सरकार ने क्या दिया? 25 एम.पी. ने क्या दिया?

किस तरह से काला कृषि कानून लाया गया। किस तरह से 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। उस पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने के लिये तैयार नहीं हैं। उन कानूनों को, जिनको कहते थे कि बहुत अच्छे कानून हैं, प्रधान मंत्री जी अब कहते हैं कि हम लोगों को समझा नहीं पाये। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपको भी अब लोग बता देंगे। जो 5 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद फिर आपको यह कहना पड़ेगा कि हम जनता को समझा नहीं पाये। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है।

आपकी नीयत में जो खोट था, आप किसान के बारे में नहीं सोचना चाहते, आप गरीब के बारे में नहीं सोचना चाहते, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, आप क्या आज सारा उत्पाद खरीदने को तैयार हैं उस पर? आपने कहीं कहा कि हम कौन-कौनसा अनाज खरीदेंगे। आज सही स्थिति यह

(श्री राजकुमार गौड़)

है कि जब भी एमएसपी की बात करते हैं तो आप पीछे हटते हैं। आपने बजट में रखा कि हम एमएसपी पर ज्यादा उत्पाद खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे आप? आप पूरा उत्पादन तो खरीद ही नहीं पाये, आप पूरी जिंस तो खरीद ही नहीं पाये, आप किसानों को कोंफिडेंस में ले ही नहीं पा रहे, आज किसान भटक रहा है, जब उसका मूंग आता है तो उसको खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जब सरसों आती है तो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जब मूंगफली आती है तो उसको खरीदने को तैयार नहीं हैं, केवल आप झांसा देना चाहते हैं। आपने जो झांसा दिया है वह माननीय प्रधान मंत्री जी, इस बात को किसान समझ चुका है, आप किसान को पानी पूरा दे नहीं सकते, आप खाद और बीज पूरा दे नहीं सकते, आपके यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के किसान को लाइन में लगना पड़ता है, आप कर क्या रहे हो? ये बात विपक्ष के लोग जानते थे और वो सहन नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, आज जब हमारे स्पीकर महोदय ने खुद बुलाकर अपने चैम्बर में बात कर ली, बात हो गयी कि आप अपनी बात रखिये रीट के बारे में, पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद आप क्यों भाग गये? आप सुनने को तैयार नहीं हैं, आप इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं हैं कि आपकी जब सरकार थी तब क्या हुआ था, तब पेपर आउट हुए थे तब आपने क्या किया? तब आपने एसओजी को नहीं दिया, तब आपने सीबीआई की बात नहीं की, तब तो आप लोकल पुलिस से ही काम चलाना चाहते थे। ये बात आप जानते हैं, और लोग भी जानते हैं, पर मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, इनकी नीयत है कि राजस्थान में माहौल खराब हो क्योंकि तीन साल में एक भी मुद्दा इनको ऐसा नहीं मिला। उप चुनावों में इनको मालूम चल गया कि लोग इनको नहीं चाहते। गत दिनों में पंचायत समितियों के चुनाव हुए जिला परिषद् के चुनाव हुए नगर परिषद् के चुनाव हुए तो लोगों ने इनको ठुकरा दिया। ये जानते हैं कि जनता के बीच में ये जाने वाले नहीं हैं और किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और ये बिलकुल कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ षड्यन्त्र रचना चाहते हैं, इस षड्यन्त्र से हम लोगों को बचना पड़ेगा, उन लोगों को हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा।

आज वो कहने को तैयार नहीं है पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 16 जिलों में मेडिकल कालेज स्वीकृत हो गये, 6 जिलों में मेडिकल कालेज बन रहे हैं, हमारे गंगानगर में मेडिकल कालेज बन रहा है, कृषि महाविद्यालय

(श्री राजकुमार गौड़)

2020 में स्वीकृत हुआ गंगानगर में आज तीसरा सेमेस्टर चल रहा है वहां। आज वहां पर नर्सिंग कालेज हो गया, आज वहां सड़कों का जाल बिछ गया।

माननीय सभापति महोदय, आज लोगों ने पहली बार देखा है कि तीन साल में जो बजट आये और जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा वो काम धरातल पर आ गये हैं, ये छोटी बात नहीं है। मेडिकल कालेज 6 जगहों पर शुरू होना छोटी बात नहीं है। कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाना छोटी बात नहीं है। महाविद्यालय शुरू हो जाना छोटी बात नहीं है, पांच सौ से ज्यादा इंग्लिश स्कूल शुरू हो जाना छोटी बात नहीं है। सड़कों का जाल बिछा दिया। लोग, किसान बात करते हैं, गांवों में जिस तरह से सड़कें दीं एक-एक एमएलए को छह-छह करोड़ रुपये की, आज किसान कहते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था कि ये सड़कें बनेंगी, एमएलए साहब, आपने ये सड़कें बना कैसे दीं? हमने कहा कि हमने नहीं बना दीं, ये राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने बना दीं। उनकी सोच थी कि किसान को सुविधा मिले, उनकी सोच थी कि गरीब आदमी को सुविधा मिले, वो चाहते थे कि आम आदमी को तकलीफ नहीं हो और आने वाले बजट में भी लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोगों को और ज्यादा सड़कों की सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के क्षेत्र में जिस तरह से काम हुए सब लोगों ने सराहा पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मंत्रीजी को कि अभी भी कुछ जिलों में हमें बिजली के बारे में देखने की आवश्यकता है। अभी भी गरीब आदमी सोचता है कि बिजली के रेट कुछ कम हों, गरीब आदमी को लगता है कि ये रेट ज्यादा हैं। किसान को निश्चित रूप से आपने प्रति माह एक हजार रुपया दे दिया, बारह हजार रुपये का उसको फायदा हो रहा है पर इसको कई जगह हमें चैक करने की जरूरत है, आज इस रेट के बारे में हम फिर से एक बार सोचें।

माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा की बात करूं, सौर ऊर्जा में जब गहलोत साहब की सरकार थी, 2008 से 2013 तक तो 86 प्रतिशत अनुदान मिलता था सौर ऊर्जा के लिए किसान को, लेकिन बीजेपी की सरकार ने लाकर 45 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज फिर लोग देख रहे हैं सरकार की तरफ कि सौर ऊर्जा पर जो अनुदान किसान को मिलता है वह अनुदान बढ़े। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्र भी जो लोग लगाना चाहते हैं उन लोगों को भी सरकार अनुदान दे, इससे हम लोगों को

(श्री राजकुमार गौड़)

फायदा होगा। लोगों को ये बात पसन्द नहीं आ रही है कि आप दे तो 9 रुपये प्रति यूनिट पर जब आप सौर ऊर्जा के माध्यम से जिसके घर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, उसको आप 3 रुपये प्रति यूनिट देना चाहते हो, 60 पैसा प्रति यूनिट आप उनसे चार्ज करना चाहते हो इस पर सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, उसको अनुदान दीजिये, उसको बढ़ावा दीजिये, उससे हम लोगों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, किसान को ऋण दिया, 8,181 करोड़ रुपये का ऋण किसानों का सरकार ने माफ किया। आज क्या स्थिति बनी? 5 एकड़ भूमि कुर्क हो रही है, इसी विधान सभा में हम लोगों ने बिल पास किया कि 5 एकड़ भूमि तक किसी को कुर्क नहीं किया जायेगा, अगर वह समय पर बिल चला जाता, गवर्नर साहब उस बिल को भारत सरकार को भेज देते, राष्ट्रपतिजी को भेज देते तो शायद सरकार को ये दुबारा आदेश जारी नहीं करने पड़ते। मुख्य मंत्रीजी को किसानों की तरफ से पूरे राजस्थान के किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत से घरों को बचा लिया, बहुत सारे घर जो उजड़ जाते, जिनकी जमीन कुर्क हो रही थी, उनको आपने एक आदेश निकालकर किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के संग में अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा कोविड काल में काम हुआ। पालनहार योजना का भी लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिला। एक लाख रुपये तुरन्त, 2 हजार रुपये प्रति माह बच्चों को, 18 साल के बाद 5 लाख रुपये देने की जो योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनायी उसकी जितनी भी तारीफ की जाये कम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जैविक कृषि के बारे में केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है, उसमें कह रहे हैं कि हम जैविक कृषि को बढ़ाएंगे। आप जैविक कृषि को कैसे बढ़ाएंगे, यह केन्द्र सरकार ने नहीं बताया। जैविक खेती हर आदमी बढ़ाना चाहता है परन्तु एक किसान जैविक खेती पर आ कैसे जायेगा, आज तो वह कीटनाशक डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, फर्टिलाइजर डाल रहा है, उसकी वजह से मान लिया उसको 100 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है। जैविक खेती पर आयेगा तो एकदम से 60 से 70 क्विंटल उपज हो जायेगी। उस अंतर का भुगतान कौन करेगा? केन्द्र सरकार में

(श्री राजकुमार गौड़)

प्रधान मंत्रीजी कहते थे कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे लेकिन आप दुगुनी आय कहां कर रहे हो, आप तो उसकी आय को कम कर रहे हो। मेरा इसमें सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है और राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि अगर जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उपज में जो अन्तर है, जैविक खेती करने के बाद उपज में जो कमी आयेगी, 100 क्विंटल की जगह 70 क्विंटल होगी तो उस 30 क्विंटल की भरपाई केन्द्र सरकार करे या राज्य सरकार करे तब तो किसान जैविक खेती की तरफ आयेगा नहीं तो जैविक खेती की हम कल्पना तो करेंगे लेकिन उस साइड में आ नहीं पायेंगे। इतना बड़ा लोस आज किसान उठा नहीं पायेगा। किसान पहले से ही कमजोर है, किसान पहले ही ऋण से दबा हुआ है। किसान पहले ही काले कानूनों से परेशान है, अगर उसकी परेशानियों को हम कम करना चाहते हैं तो उसका उत्पादन कैसे बढ़े, कैसे उसकी आय दुगुनी हो, इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज कई समस्याएं हैं, किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। मैं मेरे जिले की ही बात करूं तो कहना चाहूंगा सिंचाई मंत्रीजी से कि फिरोजपुर फीडर का डीपीआर तैयार हो रहा है, गत एक वर्ष से, मुख्य मंत्रीजी पंजाब जाकर आये थे, माननीय पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से बात करके आये थे। फिरोजपुर फीडर का डीपीआर जल्दी तैयार हो, किसान उम्मीद लगाये बैठे हैं, जैसे ही डीपीआर तैयार हो, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है मैंने कि फिरोजपुर फीडर के लिए करीब 420 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा, 200 करोड़ रुपये से ज्यादा हम लोगों के हिस्से में आयेगा। जो किसान बजट आ रहा है इसमें मैं निवेदन करूंगा कि सरकार राजस्थान की तरफ से 200 करोड़ का आबंटन इस हेतु हो।

माननीय सभापति महोदय, जहरीले पानी के लिए भी मैंने कई बार निवेदन किया है इस हाउस में। पंजाब से हमारी नहरों में जहरीला पानी आता है, चाहे वो गंग कैनाल की बात करें, भाखड़ा की बात करें, इन्दिरा गांधी कैनाल की बात करें, वो जहरीला पानी हम पी रहे हैं। 10 जिलों को वो जहरीला पानी प्रभावित कर रहा है। कैंसर का रोग वहां फैला हुआ है बार-बार कह रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी पंजाब जाकर भी बात करके आये और पंजाब सरकार पर उसका प्रभाव नहीं हो रहा, कोई नतीजा नहीं आ रहा, आज भी वो उसी तरह जहरीला पानी आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके

(श्री राजकुमार गौड़)

बारे में कोई उचित कदम उठाये, सख्त कदम उठाये और इस जहरीले पानी को हम बन्द नहीं करेंगे तब तक लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

माननीय सभापति महोदय, किसान के बजट की बात है, गंगानगर पूरे जिले में 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जाते-जाते डिग्गियों की स्वीकृति दी थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की, परन्तु राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने उन तमाम डिग्गियों का पेमेंट किया, चाहे अनुदान हमें भारत सरकार से नहीं मिला। इस बार भी हम किसान को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसान बचे, तो गंगानगर में हम लोगों की डिमांड है, पूरे गंगानगर जिले के हम जितने भी प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, चाहे कुन्नर साहब हो, चाहे जगदीशजी हों, चाहे मैं हूं, चाहे दूसरे हों, कम से कम 8 हजार डिग्गियों का प्रोविजन यह जो किसान बजट आ रहा है, इसमें इनका प्रोविजन करें। अनुदान मिले, जिससे किसान मजबूत होगा और किसान मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। छोटी-छोटी अनेकों बातें हैं।

पूर्व में सब वक्ताओं ने उन बातों का जिक्र किया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्पिनिंग मिल्स थीं। वे स्पिनिंग मिल्स दोनों बन्द हो गयीं। उनके कर्मचारियों को हम अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाये। हनुमानगढ़ के भी कर्मचारी हैं और गंगानगर के भी हैं। सरकार इन्हें जहां भी समकक्ष पोस्ट हो, वहां लगाये। ज्यादातर गरीब मजदूर हैं, फोर्थ क्लास हैं। अगर हम इन्हें रोजगार दे पाये तो उससे हमें फायदा होगा।

रीट के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है, वह बढ़िया है। जल्दी से जल्दी परीक्षा हो और उन लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि बहुत लम्बे समय से वे इन्तजार कर रहे हैं। बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं, ये कोई छात्रों के हित के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि राज्य सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पहले ही बहुत लोगों को रोजगार दे दिया है, अब ये 60 हजार और लोगों को रोजगार दे देंगे तो इनके पेट में दर्द है। ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इन्हें रोजगार न मिले, नौकरी न मिले। केवल नौकरी न देने का षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि और भी काफी डिमांड्स हैं।

आरएएस का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें बच्चों की काफी डिमांड है कि आरएएस का एग्जाम थोड़ा आगे किया जाये। अगर सरकार इस पर विचार करे तो निश्चित रूप से बच्चों को फायदा होगा। अनेक विषयों पर सब लोगों

(श्री राजकुमार गौड़)

ने चर्चा कर ली। सभापति महोदय, मुझे आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभार। शानदार काम हुए हैं। जो कहा, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। यही कारण है कि पूरे राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी को लोग याद करते हैं। लोगों को विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आने वाले बजट में लोगों को और राहत देंगे, सुविधा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.22 बजे मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

रामगढ़ शेखावाटी (सीकर) के किसानों को फसल खराबे का अनुदान

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन दो तहसील बनी हुई हैं तहसील फतेहपुर एवं तहसील रामगढ़ शेखावाटी। इन दोनों तहसीलों की सीमाएं आपस में सटी हुई है तथा रामगढ़ तहसील में आने वाले कई गांव फतेहपुर तहसील मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

अध्यक्ष जी, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। जल स्रोतों की कमी के चलते यहां मुख्य रूप से किसान केवल खरीफ की फसल पर निर्भर रहते हैं तथा इसी से किसानों की रोजी-रोटी चलती है।

खरीफ फसल-2020 के समय 11 जून, 2020 से क्षेत्र में लगातार टिड्डी दल सक्रिय रहे जिससे किसानों को काफी आर्थिक व मानसिक नुकसान झेलना पड़ा था एवं खरीफ फसल-2021 के समय मौसम में आये अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव व भारी अतिदृष्टि के कारण प्रदेशभर में खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ। इस समय विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर भी पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, वहीं लगातार दो वर्षों में हुए आय के एक मात्र स्रोत खरीफ की फसल के खराबे ने किसानों को हताश कर दिया।

अध्यक्ष जी, लोक-कल्याणकारी राज्य सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता के कारण अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के कारण किसानों को अनुदान के रूप में राहत प्रदान करने हेतु सर्वे करवाया। राज्य सरकार द्वारा सर्वे करवाये जाने पर विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की एक तहसील फतेहपुर से फसल खराबे की रिपोर्ट प्रपत्र 7D में दर्ज कर सरकार को भिजवायी गई, जिसके

अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा हुआ है परन्तु इसी क्षेत्र में आने वाली दूसरी तहसील रामगढ़ शेखावाटी में कार्मिकों की लापरवाही के चलते यहां फसल खराबे की रिपोर्ट प्रपत्र 7D में दर्ज नहीं की गई व कर्मचारियों ने कार्यभार से बचने के लिए राज्य सरकार को फसल खराबे की सही जानकारी नहीं दी, जिसके कारण क्षेत्र के किसान राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से वंचित रह जायेंगे।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान हित में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की तहसील रामगढ़ शेखावाटी (सीकर) के किसानों को फसल खराबे की पुनः समीक्षा करवाकर किसानों को अनुदान देकर राहत प्रदान करने की कृपा करें।

अलवर उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय का क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में क्रमोन्नयन

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़)

महोदय,

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अलवर रोजगार कार्यालय 1975 से उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। उक्त क्षेत्र में करीब 5548 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं, 119 आईटीआई, 05 इंजीनियर कालेज, 84 राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय एवं एक मेडिकल कालेज संचालित है तथा दूसरा मेडिकल कालेज प्रक्रियाधीन है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में प्रदेश में शीर्ष स्थान कायम रखते हुए 40,000 युवाओं को 130 करोड़ रुपये का पारदर्शी ईमानदारी पूर्ण यह समय पर भुगतान कर सरकार की छवि को युवा वर्ग में उज्ज्वल किया है तथा रोजगार मेलों' के माध्यम से करीब 5,000 युवाओं को भौतिक रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट सत्र में उपरोक्त कार्यालय को अपग्रेड कर उप निदेशक का पद व क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय घोषित करते हैं तो राज्य सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा तथा अलवर की युवा पीढ़ी में इसका सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव रेखांकित होगा एवं साथ ही अलवर में उभरते हुए औद्योगिक परिदृश्य को अनुकूल मानव शक्ति की उपलब्धता निर्बाध होती रहेगी।

डूंगरपुर के चिकित्सालयों में सफाई कर्मियों के भुगतान तथा सफाई व्यवस्था में अनियमितता से आमजन को परेशानी

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्था में हो रही अनियमितता से आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डूंगरपुर जिले का जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाईकर्मियों का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है और एक सफाईकर्मी को 8 घण्टे की ड्यूटी का प्रतिदिन मात्र 100 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इस समस्त अव्यवस्था की मुख्य जड़ आकांशा कंसल्टेन्सी एजेन्सी है। पूरे जिले की सफाई व्यवस्था का कार्य इस एजेन्सी को टेण्डर के माध्यम से दिया गया है। इसके द्वारा सभी जगह पर्याप्त मात्रा में सफाईकर्मी भी नहीं लगाये गये हैं और टेण्डर शर्तो के अनुरूप सफाई सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पूरे जिले की चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।

इस एजेन्सी एवं कुछ अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक माह लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और गरीब सफाईकर्मियों को माह का मात्र 3,000 रुपया देकर कार्य करवाया जा रहा है। कई जगह सफाईकर्मी कार्य छोड़कर चले गये हैं, जिससे जिले के चिकित्सालयों की दयनीय स्थिति है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले में आकांशा कंसल्टेन्सी एजेन्सी का टेण्डर तत्काल निरस्त कर जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कार्यवाही कर जिले के चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था को सुधार कर मरीजों को राहत प्रदान करें।

बगरू के गांवों को सड़कों से जोड़ने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्रीमती गंगा देवी (बगरू)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें टूटी हुई हैं। उन्हें नवीनीकरण

योजना में देकर फिर से नई बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सड़क से वंचित ग्राम पंचायत के गावों को भी सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है। जहां कई वर्षों से लगातार सड़क निर्माण की मांग उठाई जा रही है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि जल्द से जल्द सड़कें बनवाने की कृपा करावें।

पिलानी में तहसील की स्वीकृति

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अन्तर्गत पिलानी में पंचायत समिति बन चुकी है, वहां चुनाव भी हो चुके हैं एवं पंचायत समिति पिलानी वर्तमान में कार्यशील है, परन्तु पिलानी पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों व पिलानी विधान सभा क्षेत्र की ही 7 उन ग्राम पंचायतों जो कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, उनका राजकीय कार्य तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से सम्पादित हो रहा है जो कि दूसरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पड़ता है। इस कारण समस्त 31 ग्राम पंचायतों व इसके अतिरिक्त नगरपालिका पिलानी व नगरपालिका विद्याविहार पिलानी के नागरिकों व कर्मचारियों को सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के तहसीलदार, सूरजगढ़ व उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के पास राजकीय कार्यों के लिये व राजस्व कार्यों के लिये जाना पड़ता है जो असुविधाजनक होने के साथ-साथ अव्यावहारिक भी है और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह व्यवस्था उचित नहीं है।

इस विषमता को दूर करने के लिये राज्य सरकार से निवेदन है कि कृपया पिलानी में तहसील स्वीकृत कर अनुगृहीत करें ताकि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजकीय व राजस्व कार्य तहसीलदार पिलानी के माध्यम से ही सम्पन्न हो और उसका प्रशासनिक नियन्त्रण भी पिलानी विधान सभा क्षेत्र में ही कार्यरत उप खण्ड अधिकारी, चिड़ावा के माध्यम से हो जाए।

कृपया पिलानी में अवश्य तहसील स्वीकृत कर अनुगृहीत करावें।

सलूम्बर में आबादी क्षेत्र से गुजर रही विद्युत लाइनों का अन्यत्र स्थानान्तरण

श्री अमृत लाल मीणा (सलूम्बर)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर

की निम्न विद्युत सम्बन्धित लाइनों की समस्याओं का निराकरण कराकर आमजन को राहत प्रदान करावें।

1. श्री कलाजी विकास संस्थान जयसमन्द धार्मिक मन्दिर के ऊपर से 33 के.वी. बिजली की लाइन गुजर रही है अन्यत्र शिफ्ट किया जाये।
2. डगार फीडर से निकलने वाली 11 के.वी. विदयुत लाइन केकुडिया, जयमनपुरा, ईटाली खेड़ा, पारोड़ा, खण्डोरा, खैरोली होते हुए ऐमनिया पाडला जाती है करीब 30 से 40 किलोमीटर लम्बी लाइन होने के कारण अत्यधिक विद्युत बाधित रहती गांवों में इससे नजदीक के डगार से लाम्बीडूंगरी जाने वाले फीडर से जोड़कर 6-7 पोल लगाने से उक्त समस्या का निराकरण किया जा सकता है और किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध होगी।
3. ग्राम पंचायत खरका जी.एम.एस. से 11 के.वी. लाइन का सेपरेशन फीडर के तहत खींचा गया था आबादी क्षेत्र और मुख्य बाजार में मकानों को छूते हुए खींचा गया है जिसे जनहानि होने की अत्यधिक सम्भावना है जिस वजह से ग्रामीणों ने उक्त फीडर को चार्ज नहीं होने दिया है। इसे अतिशीघ्र चार्ज करावें ताकि ग्रामवासियों को उक्त फीडर का लाभ मिल सके और बस्ती के मध्य में जो तार है उसे भी हटाने की कृपा करें।
4. जयसमन्द जी.एस.एस. से निकलने वाली 11 केवी लाइन का फीडर डीगरी गांव में होकर गुजर रहा है। साथ ही अदकालिया 132 के.वी. जी.एस.एस. से 33 के.वी. की लाइन भी डींगरी के बस्ती के मध्य में होकर गुजर रही है जिससे हर वक्त दुर्घटना का भय ग्रामीणों में रहता है क्योंकि पूर्व में भी उक्त लाईनों से कई जनहानि हो चुकी है। अतः उक्त दोनों लाइनों को बस्ती के मध्य से अन्यत्र शिफ्ट किया जाये।
5. सराड़ा 132 के.वी. जीएसएस के निर्माण के लिये बजट आबंटन करा कर निर्माण कराया जावे, ताकि क्षेत्र के लोगों को बिजली से निजात मिल सके।

उक्त लाइनों के उपयुक्त क्लीयरेन्स नहीं होने से यहां जानमाल का खतरा बना हुआ है। कृपया इन लाइनों को शिफ्ट करने हेतु सम्बन्धित अभियन्ता को तुरन्त निर्देश प्रदान करवारकर अनुगृहीत करावें।

मारवाड़ में पर्यटन स्थलों के विकास एवं रियासत कालीन हवाई पट्टियों का जीर्णोद्धार

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन)

महोदय,

मारवाड़ (पश्चिमी राजस्थान) में 27 रियासत कालीन हवाई पट्टियां बनी हुई हैं। जिसमें से विशेषकर गोडवाड में धार्मिक, पर्यटन वाइल्ड लाइफ पर्यटन पारम्परिक कल्चरल पर्यटन, योग एवं स्वास्थ्य पर्यटन ने आज भी अपनी विरासत को संजोए रखा है। यहां स्थापत्य व वास्तुकला की विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। पूरे विश्व में आज भी गोडवाड अपने गौरवशाली इतिहास व संस्कृति की अलग पहचान रखता है।

रियासत कालीन हवाई पट्टियों को दुरुस्त कर पर्यटकों हेतु घरेलू हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी जाय जिससे सादड़ी हवाई पट्टी के विकास के साथ ही गोडवाड पर्यटन सर्किट बनाकर जिसमें कामलीघाट से फुलाद हैरिटेज मीटर गेज रेलवे लाइन. भीलबेरी जोजावर वाटरफाल जो कि राज्य का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जल प्रपात। साथ ही सुगेर कालेश्वर महादेव, मुछाला महावीर पाणेराव जहां पर वन्य जीवों की बहुतायत है जहां पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण ग्रासलैण्ड डवलप किया जा रहा है, जिससे बाघ को स्थापित करने की प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही आसपास में कई पर्यटन स्थल व अभयारण्य स्थल भी स्थापित है। कुछ ही दूरी पर राजसमन्द है जहां Lake में रियासत कालीन जल हवाई पट्टी भी थी, साथ ही कुम्भलगढ़ को Hot Air Bloon से जोड़ा जा सकता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के एक किलोमीटर दायरे में वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी उसे हटाकर जीरो बिन्दु की जाय जिससे पर्यटन इकाई जोन की स्थापना के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मारवाड में पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ रियासत कालीन हवाई पट्टियों का जीर्णोद्धार कर घरेलू हवाई सेवा प्रारम्भ की जाय जिससे पर्यटकों को आवागमन की सुविधा मिल सके और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके।

नीम का थाना में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पीने का पानी तथा यमुना से सिंचाई के पानी की उपलब्धता

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सीकर जिला बहुत पहले से डार्क जोन घोषित है। नीम का थाना में जल स्तर 1,000 फीट से नीचे चला गया है एवं पानी फ्लोराइडयुक्त आता है जिससे अनेक रोगों से जनता पीड़ित है।

जल जीवन मिशन में भी बोरिंग फेल हो रहे हैं। ऐसे में एकमात्र उपाय कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पीने का पानी एवं यमुना से सिंचाई का पानी आना है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस पर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करें।

बाड़मेर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री अमीन खां (शिव)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर का क्षेत्र हमेशा से शिक्षा में सबसे निम्नतम आता है जिसका कारण वहां शिक्षा कम होने से लोकल अध्यापक नहीं है एवं बाहर के अध्यापक तबादला कराकर हमेशा चले जाते हैं। आज की तारीख में 776 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान में इतने पद कहीं खाली नहीं हैं।

गरडा रोड ब्लॉक के अन्दर देताणी गांव में राज्य सरकार ने मॉडल स्कूल खोल रखी है। कुल 28 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उन 28 पदों में से 15 पद खाली हैं और उसमें से भी अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान अध्यापकों के पद हमेशा रिक्त रहते हैं। जिसके कारण वहां के बच्चे उस स्कूल से टी.सी. लेकर चले जाते हैं। ऐसी हालत में हमारा निवदेन है कि सीमावर्ती क्षेत्र जो शिक्षा में पिछड़ा हुआहै वहां अध्यापकों के खाली पदों को भरा जाए।

रीट परीक्षा-2021 के पेपर लीक प्रकरण की CBI से जांच

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली)

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राज्य सरकार दवारा 26 दिसम्बर,

2021 को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की गई जिसमें दो चरणों में 26 लाख 51 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को कई किलोमीटर दूर की यात्रा करके परीक्षा देने आना पड़ा। परीक्षा के दिन पूर्ण रूप से नेटबंदी और करोड़ों रुपये के सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद भी परीक्षा से एक दर्जन से अधिक शहरों में प्रश्न पत्र व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिया गया तथा निश्चित रूप से पेपर आउट कर दिया गया। उक्त प्रकरण में मुख्य सरगना भजन लाल सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 9 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, दो पुलिस अधिकारी, एक शिक्षा अधिकारी व तीन पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। पेपर लीक करने वाले मुख्य सरगना बत्ती लाल व भजन लाल को पेपर किसने उपलब्ध कराए, यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। एक सेवानिवृत्त व्याख्याता को जयपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया तथा जयपुर के मानसरोवर, दुर्गापुरा इलाके में रीट का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व 994 में बेचे जाएंगे, की सूचना एसओजी को प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रही थी, लेकिन राजस्थान में सक्रिय पेपर माफिया ने सरकार के वाशिंदों के साथ मिलकर इस प्रकार के पेपर लीक की साजिश को अंजाम दिया उसके कारण देशभर में राजस्थान की छवि धूमिल हुई है। साथ ही लाखों परीक्षार्थियों की भावना को गहरा आघात लगा।

अतः माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाये।

मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड में नवीन एम्बुलेंसों का संचालन

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा निरोगी राजस्थान की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने और सर्वजन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए गत और वर्तमान बजट में कई लोक लुभावनी घोषणा तो कर दी परन्तु उनके सफल क्रियान्वयन में हर बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में एम्बुलेंस (108) के संचालन हेतु GVKEMRI नाम की कम्पनी के साथ अनुबंध किया है। उपरोक्त कम्पनी पिछले लगभग 8-10 महीनों से एम्बुलेंस (108) वाहनों एवं नर्सिंग व अन्य स्टाफ का फर्जी भुगतान उठा रही है। प्रदेश में उक्त कम्पनी के अधीन संचालित लगभग 70 ऐसी एम्बुलेंस (108) संचालित हैं, जिनमें नर्सिंग स्टाफ नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के अभाव में मरीजों को दी जाने वाली आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है।

मेरे क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा में संचालित एम्बुलेंस से (108) करीब 2 साल से एक-दो एम्बुलेंस (108) को छोड़कर चालू हालत में नहीं है तथा उपखण्ड टोडारायसिंह में मात्र एक ही एम्बुलेंस (108) वाहन संचालित है जिसमें भी समय पर मेन्टीनेन्स नहीं किये जाने से बार-बार धक्के लगाने पड़ते हैं। क्या सरकार ने मालपुरा व टोडारायसिंह की आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? क्या आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना उनका अधिकार नहीं है? जबकि मेरे क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में विस्तृत नगरपालिका क्षेत्र एवं काफी बड़े ग्रामीण क्षेत्र साथ-साथ दो स्टेट हाईवे एसएच 37-ए (दूदू छाण वाया मालपुरा) एवं एसएच-12 (जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा) गुजरते हैं। जिन पर आये दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है जिनमें त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और प्राथमिक उपचार नहीं मिलने के कारण घायलों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह, मालपुरा व डिग्गी से रैफर किये जाने वाले मरीजों का पहले जिला चिकित्सालय टोंक रैफर किया जाता है फिर वहां से जयपुर के लिए रैफर किया जाता है। इस प्रक्रिया से मरीज अत्यन्त ही विकट स्थिति में पहुंच जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसलिए रैफरल कैस को सीधे जयपुर के लिए ही रैफर किया जाना चाहिए जिससे समय पर उचित इलाज मिल सके।

अतः माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में संचालित एम्बुलेंसों (108) पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करवाकर मेरे क्षेत्र के मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड में नवीन एम्बुलेंस (108) संचालित करवाने की कृपा करें।

बालोतरा को जिले का दर्जा

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल 28,387 किमी है जो कई एक राज्य में धौलपुर, दौसा, जयपुर एवं जोधपुर से बड़ा है। सीमावर्ती विकट भौगोलिक परिस्थितियों का मरुस्थलीय अभावग्रस्त एवं प्राय: सूखाग्रस्त है। यह जिला शिक्षा एवं आर्थिक दोनों दृष्टि से पिछड़ा है। जिला जयपुर पाली जालौर की सीमावर्ती के लोगों को जिला मुख्यालय बाड़मेर पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यों हेतु आने-जाने के लिए 195-250 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही मरुस्थलीय एवं विकट परिस्थिति एवं विकास के अभाव में संसाधनों का भी भयंकर अभाव है। ऐसी स्थिति में सरकारी एवं अन्य जिला स्तरीय कार्यों के निस्तारण में आमजन विशेषकर वरिष्ठ नागरिक एवं महिला वर्ग को भयंकर परेशानी जाती है। एक गरीब और अशिक्षित के लिए तो बाड़मेर आना जाना भयंकर परेशानी का सबब बन जाता है। इससे शारीरिक कष्ट समय व अर्थ की बरबादी के साथ मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। लम्बे समय से पचपदरा, गिडा, पाटोदी, सिणधरी, गुढ़ामालानी, सिवाना एवं समदड़ी तहसील को मिलाकर नया जिला बनाये जाने की मांग की जा रही है। बालोतरा जिला बनने के सभी मानदण्ड पूरे हो रहे हैं। भविष्य में जिला बनाने के उद्देश्य एवं उम्मीद में नगर परिषद् द्वारा 100 बीघा जमीन चिन्हित एवं आरक्षित है और जैरला के पास 400 के करीब सरकारी भूमि है। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिवहन अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण, जिला एवं सेशन न्यायालय एवं श्रम विभाग के साथ ही कई अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं।

उक्त सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं आम आदमी की परेशानी एवं समय की मांग और आवश्यकता को देखते हुए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध आग्रह है कि बालोतरा को इसी बजट 2022-23 में जिला घोषित कर लम्बे समय से प्रतीक्षारत बालोतरा की जनता को न्याय प्रदान कर अनुगृहीत करावें।